महानगर नई दिल्ली सोमवार 29 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

कश्मीर में नफरत फैलाने वाले सफल नहीं होंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कश्मीर के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए बेताब हैं। विकास की शक्ति, बम-बंदूक की ताकत पर हमेशा भारी पड़ती है और जो लोग विकास की राह में नफरत फैलाना चाहते हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, वे कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते।

आकाशवाणी पर प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जून महीने में जम्मू कश्मीर में आयोजित 'गांव की ओर लौट चले' जैसी ग्रामीण सशक्तिकरण पहल का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में कहा, कश्मीर के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ने को बेताब

प्रधानमंत्री ने कहा, 'ऐसे कार्यक्रम और उसमें लोगों की भागीदारी यह बताती है कि कश्मीर के हमारे भाई-बहन सुशासन चाहते हैं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि विकास की शक्ति, बम-बंदूक की शक्ति पर हमेशा भारी पड़ती है।' प्रधानमंत्री के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत यह जानने का भी प्रयास किया गया कि लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचती भी हैं या नहीं? पंचायतों को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है? उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है?

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कोई सरकारी खानापूर्ति नहीं था कि अधिकारी दिन भर गांव में घूमकर वापस लौट आएं। बल्कि इस बार अधिकारियों ने दो दिन और एक रात पंचायत में ही बिताई। सब जगह ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें उन गांवों के लोग भी शामिल बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर भाजपा कोर समूह की बैठक कल

सूबे में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

भाजपा ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल और वहां जब कभी होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को प्रदेश इकाई के कोर समूह की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, भाजपा महासचिव राम माधव, प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इन नेताओं के अलावा पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में हिस्सा लेंगे।

जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के मुख्य रणनीतिकार राम माधव ने इससे पहले चुनाव आयोग से इस साल प्रदेश में चुनाव कराने की अपील की थी।

प्रदेश भाजपा ने कहा है कि वह किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी महासचिव नरिंदर सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के पास इस साल चुनाव कराने के लिए काफी समय बचा है। जम्मू कश्मीर में 2014 में बाकी पेज 8 पर

बारामूला में चार जगहों पर एनआइए के छापे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

आतंक के लिए वित्तपोषण मामले में राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने रविवार को उत्तर कश्मीर के बारामूला में चार जगहों पर छापे मारे। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीमों को साथ लेकर छापे मारे गए। आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के लिए स्थानीय कारोबारियों व अलगाववादियों के हवाला नेटवर्क की जांच के सिलसिले में जैसे-जैसे नई जानकारियां मिल रही हैं, उसी हिसाब से छापेमारी की जा रही है।

पुलवामा के कारोबारी गुलाम अहमद वानी और उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर बाकी पेज 8 पर

धारा 35ए से छेड़छाड़ बारूद में आग लगाने जैसा होगा : महबूबा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

कश्मीर में केंद्रीय सुरक्षा बलों के अतिरिक्त 10 हजार जवानों की तैनाती को लेकर वहां का राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। इस कवायद को विधानसभा चुनाव की तैयारियों और राज्य में धारा 35 ए हटाने की तैयारी से जोड़ा जा रहा है।

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को केंद्र को आगाह किया कि धारा 35ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा। धारा 35ए जम्मू व कश्मीर के स्थायी निवासियों बाकी पेज 8 पर

भीड़ हिंसा के नाम पर हिंदू धर्म को किया जा रहा बदनाम : भागवत

मथुरा, 28 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने यहां कहा कि देश में आजकल भीड़ हिंसा के नाम पर हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम करने की गहरी साजिश रची जा रही है।

भागवत ने वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में आयोजित संघ की अखिल भारतीय सामाजिक सद्भाव समिति की द्विदिवसीय बैठक की शुरुआत करते हुए कहा, 'देश भर में हिंदू धर्म एवं संस्कृति को बदनाम करने की गहरी साजिश की जा रही है। कहीं भीड़ हिंसा के नाम पर सियासत कर-के समाज में घृणा फैलाने का काम हो रहा है तो कहीं गाय के नाम पर। कुछ राज्यों में एक योजना के तहत धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा है। देश में आज जो हालात हैं, उन्हें देखते हुए सभी प्रचारकों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है।'

कहीं भीड़-हिंसा के नाम पर सियासत करके समाज में घृणा फैलाने का काम हो रहा है तो कहीं गाय के नाम पर।

सर संघचालक ने कहा, 'हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बाकी पेज 8 पर

एनआइए को श्रीलंका बम विस्फोटों की जांच का जिम्मा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

श्रीलंका में 21 अप्रैल को हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों की जांच राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) करेगी। संसद में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद विदेश का यह पहला मामला होगा, जिसकी जांच एनआइए करेगी। श्रीलंका धमाकों के सिलसिले में एनआइए ने केरल के पलक्कड से एक युवक को गिरफ्तार कर रखा है।

संसद ने विदेश में आतंकवादी घटनाओं में भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने की स्थिति में एनआइए को मामला दर्ज कर विदेशों में जाकर जांच करने का अधिकार देने वाले एक महत्त्वपूर्ण विधेयक 'राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019' को 17 जुलाई अपनी मंजूरी दे दी थी और कानून मंत्रालय ने 25 जुलाई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। श्रीलंका में जांच प्रक्रिया के लिए दिल्ली में एक विशेष अदालत का भी गठन किया गया है। \

इसके बाद श्रीलंका विस्फोटों की जांच के लिए एनआइए को अधिकार मिल गए। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, एनआइए के दो अधिकारियों ने मई में श्रीलंका का दौरा किया था और वहां के अधिकारियों से उन दावों के बारे में चर्चा की थी जिनमें कहा गया था कि आतंकवादी संगठन आइएस से जुड़े कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर समेत भारत की यात्रा की थी। अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक एनआइए अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण कोई भी मामला दर्ज नहीं कर पाई है।

विदेश की धरती पर पहला मामला, जिसकी जांच करेगी भारतीय एजंसी।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, एनआइए के दो अधिकारियों ने मई में श्रीलंका का दौरा किया था।

लेकिन संशोधित कानून के साथ जांच एजंसी के लिए अब इसका रास्ता खुल गया है। एनआइए को इजाजत की प्रक्रिया से जुड़े रहे गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीलंका में हुए धमाकों की घटना एनआइए द्वारा विदेशों में जांच किया जाने वाला पहला मामला बनने जा रहा है। बीते 21 अप्रैल को श्रीलंका में नौ आत्मघाती हमलावरों ने सिलसिलेवार बम विस्फोटों को अंजाम दिया था, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हुई बाकी पेज 8 पर

अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा कर पलटी, दो की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

विवेक विहार थाना क्षेत्र में सीमापुरी अंडरपास के पास एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और बाद में सड़क पर लगे दिशा सूचक बोर्ड से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में एक छात्र और एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि हादसे में दो अन्य विद्यार्थी घायल हैं।

शहादरा जिला पुलिस उपायुक्त मेघना यादव ने बताया कि घटना की सूचना रविवार तड़के 5:40 बजे पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची

हादसे में जान गंवाने वालों में डीयू के छात्र-छात्रा शामिल, छात्रा सिरसा की थी।

जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहे थे कार सवार पांच दोस्त।

घायलों में एक छात्र की हालत नाजुक है, दूसरे की हालत स्थिर

विवेक विहार थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच-पड़ताल

विवेक विहार थाना पुलिस को पता चला कि राहगीर सभी बाकी पेज 8 पर

हिमाचल प्रदेश भाजपा के दो नेता पार्टी से निलंबित

शिमला, 28 जुलाई (भाषा)।

भाजपा ने कुल्लू जिले में पार्टी की युवा शाखा के एक नेता और पदाधिकारी को सोशल मीडिया पर उनका एक कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया।

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शनिवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया और वीडियो को साझा करने वालों को चेताया था। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों ने ही यह वीडियो बनाया था जो कि कुछ मिनट का है। वीडियो बाकी पेज 8 पर

कर्नाटक में 14 और बागी विधायक अयोग्य करार

इनमें कांग्रेस के 11 और जद (सेकु) के तीन विधायक शामिल

बेंगलुरु, 28 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक विधानसभाध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने रविवार को 14 और बागी विधायकों को दलबदल निरोधक कानून के तहत साल 2023 में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने तक अयोग्य करार दिया।

विधानसभाध्यक्ष का यह फैसला मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा द्वारा विधानसभा में बहुमत साबित करने के एक दिन पहले आया है। विधानसभाध्यक्ष की यह कार्रवाई कांग्रेस के 11 और जद (सेकु) के तीन विधायकों के खिलाफ की गई है। विधानसभाध्यक्ष ने अपने फैसले की घोषणा बाकी पेज 8 पर

मैंने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया। मुझे 100 फीसद आघात लगा है।
-केआर रमेश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष

सौ फीसद बहुमत साबित करूंगा : येदियुरप्पा

कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत से एक दिन पहले रविवार को मुख्मयंत्री बी एस येदियुरप्पा ने बहुमत साबित करने का विश्वास जताया। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली गठबंधन सरकार द्वारा तैयार किए वित्त विधेयक को भी बिना किसी परिवर्तन के वह सोमवार को सदन में पेश करेंगे। येदियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'सोमवार को सौ फीसद मैं बहुमत साबित कर दूंगा।'

अयोग्यता के खिलाफ कोर्ट जाएंगे : विश्वनाथ

पुणे/बेंगलुरु, 28 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रविवार को अयोग्य घोषित किए गए जद (सेकु) के बागी विधायक एएच विश्वनाथ ने कहा कि फैसला 'कानून के बाकी पेज 8 पर

भाजपा विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती जख्मी

रायबरेली/उन्नाव, 28 जुलाई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित गुरबख्शगंज इलाके में रविवार को एक बेकाबू ट्रक की टक्कर से कार सवार एक महिला की मौत हो गई तथा तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों में उन्नाव की रहने वाली वह लड़की भी शामिल है, जिसने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। सेंगर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गुरबख्शगंज क्षेत्र में रविवार दोपहर एक ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 50 साल की एक महिला की मृत्यु हो गई तथा तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ट्रक चालक भाग गया।

ट्रक ने कार को टक्कर मारी, दो जख्मी, एक मौत।

रायबरेली स्थित गुरबख्शगंज इलाके में हुआ हादसा।

सिंह ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि ट्रक रफ्तार में था और बारिश की वजह से मौके पर फिसलन थी। इसी बीच, ट्रक का चालक नियंत्रण खो बैठा और उसने कार में टक्कर मार दी। हादसे में घायल तीनों लोगों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक बाकी पेज 8 पर

दरअसल

पार्टी में सभी महत्त्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव हों | **सुझाव** | कमान किसी युवा नेता को दी जानी चाहिए

नेतृत्व को लेकर स्पष्टता की कमी से कांग्रेस को नुकसान : थरूर

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद नेतृत्व को लेकर स्पष्टता की कमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सुधार का रास्ता यही हो सकता है कि कार्यसमिति सहित पार्टी में सभी महत्त्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव हों, जिससे चुने जाने वाले नेताओं को स्वीकार्यता हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आकलन का भी समर्थन किया कि कांग्रेस की कमान किसी युवा नेता को सौंपी जानी चाहिए। थरूर ने उम्मीद जताई कि पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव होने पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें अपनी किस्मत आजमाने को लेकर फैसला करेंगी। लेकिन यह गांधी परिवार का फैसला होगा कि प्रियंका इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगी या नहीं।

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने साक्षात्कार में कहा कि कांग्रेस में सुधार का एक रास्ता यह हो सकता है कि कांग्रेस कार्यसमिति पार्टी के लिए अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष का नाम बताए और फिर इसे भंग कर दें। इसके बाद कार्यसमिति समेत पार्टी के भीतर मुख्य नेतृत्व पदों पर ताजा चुनाव हों।

प्रियंका गांधी के पास स्वाभाविक करिश्मा है जो निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को प्रेरित और एकजुट कर सकता है। इसी खूबी के कारण कई लोग उनकी तुलना दिवंगत इंदिरा गांधी से करते हैं। वह निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान डालेंगी और साथ ही मतदाताओं को भी पार्टी की ओर खीचेंगी।

पेज 5 पर संबंधित खबर

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने साक्षात्कार में कहा, 'यह बिल्कुल सही बात है कि पार्टी के शीर्ष पद पर स्पष्टता की कमी संभवतः कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को नुकसान पहुंचा रही है। ज्यादातर कार्यकर्ता व समर्थक नेता की कमी महसूस करते हैं जो अहम फैसलों को देखे, कमान संभाले और यहां तक कि पार्टी में नई जान फूंके और उसे आगे ले जाए।' थरूर ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) मौजूदा स्थिति को बहुत गंभीरता से ले रही है और वह बिना किसी देरी के समाधान खोजने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'कांग्रेस में सुधार का एक रास्ता यह हो सकता है कि सीडब्ल्यूसी पार्टी के लिए अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष का नाम बताए और फिर इसे भंग कर दें। इसके बाद सीडब्ल्यूसी समेत पार्टी के भीतर मुख्य नेतृत्व पदों पर ताजा चुनाव हों।'

उन्होंने कहा, 'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (पीसीसी) से लिए गए नेताओं को यह तय करने का अधिकार दिया जाए कि इन अहम पदों में से कौन पार्टी का नेतृत्व करेगा। इससे आने वाले नेताओं को स्वीकार्यता बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Mamta Ahuja W/o Bharat Ahuja R/o J-6/121 Second Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027 have changed my name from Arora Mamta Krushnalal to Mamta Ahuja for all future purposes. 40505162

I,Lakshmi Narayan Shukla,S/o-Chander Bhushan Shukla,R/o-39-C,Janta Flats,Ashok Vihar,Phase-3,Delhi-110052,by mistake my name mentioned Laxmi Narayan Shukla in passport of my sin Sadhu Saralsheeldass but original name is Lakshmi Narayan Shukla. 0040505161-1

I, Yash S/O Satnarain Garg R/O D-479, Sector-1, Avantika, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Yash Garg. 0040505117-7

I, Seema w/o Pritpal Singh Bhatia r/o WZ-16, Upper Ground Floor, Gali no-1, Hind Nagar, Tilak Nagar, Delhi-110018, have changed my name to SEEMA BHATIA permanently. 0040505045-2

I, Neeraj Kumar S/o Moti Lal Shah R/o D-1/296, Gali No-12, 3 Rd Pusta Sonia Vihar, Karawal Nagar, Delhi-94, have changed my name to Neeraj Kumar Shah . 0040505151-1

I, Mayur S/o Shri Ajit Kumar Jain R/o Free India Electric House, Saheed Road, Gaya, Bihar have changed my name from Mayur to Mayur Jain for all purposes 0040505076-1

I Sanjeev Kumar S/o Jagannath R/o-E-234 Amar-Colony Lajpat Nagar-4 Delhi-110024. Have Change My Name To Sanjeev Kumar Arora. 0040505133-5

I, Geeta Rani W/O Vijay Kumar R/O F-131, F-Block, Gandhi Vihar, Mukherjee Nagar, Delhi-110009. Changed My Name To Geeta Sethi. 0040505117-8

I, Daya Rani W/o Mukesh Kumar Jain R/o-144, Sector-14, Sonipat have changed my name to Daya Jain for all purposes. 0040505117-9

I, Ankita Mittal W/o Shri Vijay Kumar Aggarwal R/o T-24/10, Second Floor, DLF Phase-3, Gurugram, Haryana-122010 have changed my name from Ankita Mittal to Ankita Mithal for all purposes. 0040505077-1

I Sadhu Saralsheeldass s/o Lakshmi Narayan Shukla R/o-39-c,Janta Flats Ashok Vihar Phase-3 Delhi-110052 have changed name Amit Shukla for future. 0040505161-2

I Rashmeet Kaur Sohal D/o Kawaljeet Singh R/o WZ-310B, Street No.17, Shiv Nagar, ND-58 have changed my name to Rashmeet Sohal for all future purposes. 0040505035-1

I, Ishaan s/o Shamsher Chaudhary r/o WZ-269, Tihar Village, Delhi-110018, have changed my name to Ishan Chaudhary permanently. 0040505045-1

I, Manik S/O Shri Satwinder Kumar R/O E-3/312, Paradise Apartments, Sector-18, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Manik Kapil. 0040505133-9

PUBLIC NOTICE

We M/s Sahu Refrigeration Industries Ltd., 80 Rajasthani Udyog Nagar, New Delhi through its directors intends to mortgage the following property with State Bank of India, MCB Lawrence Road Branch, Delhi - 35, declares as under:-

We intend to create an Equitable Mortgage on the basis of Laminated Original Title Deeds of Property. On Plot No. 80, Rajasthani Coop Industrial Estate Ltd. measuring 3200 Sq. Yards registered vide Conveyance Deed dated **08.09.2009** vide **registration no. 13010** by Delhi Development Authority, bounded as under:-

North 30' Road, East 30' Road, South Plot No. 81, West Boundary.

We wish to create charge for availing Cash Credit facility from State Bank of India, MCB Lawrence Road, Branch Delhi - 35 (Branch Code 31355). If any Party has any claim towards the said relevant property, the same should be lodged with the us and also with the stated branch of State Bank of India, within 15 days from publication of this notice.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

विद्यार्थियों की हाजिरी पर नजर रखेगा सीबीएसई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अब कक्षा दस और बारह में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी नजर रखेगा। इसके तहत अब स्कूलों को विद्यार्थियों की कम हाजिरी के सभी मामलों के संबंध में सीबीएसई को सूचित करना अनिवार्य होगा। बोर्ड ही इस पर नियमानुसार अंतिम निर्णय लेगा। अभी स्कूलों के प्रधानाचार्य अपने स्तर पर भी कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दे देते हैं और इस बारे में बोर्ड को सूचित नहीं करते हैं।

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 2019 के नतीजों का आकलन करने पर पाया गया कि कम हाजिरी वाले बच्चों ने सीबीएसई परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन किया, जिस कारण कम हाजिरी वाले बच्चों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को तैयार करना पड़ा। बोर्ड के परीक्षा उपनियमों के नियम 13 में सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में बैठने के पात्र बनने के लिए विद्यार्थियों की आवश्यक हाजिरी के बारे में बताया गया है। वहीं, परीक्षा उपनियमों के नियम 14 में बताया गया है कि कितनी फीसद हाजिरी तक विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की छूट मिल सकती है या उसके परीक्षा में बैठने के संबंध में विचार किया जा सकता है।

बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ऐसा पाया गया कि विद्यार्थी, अभिभावक और स्कूल नियमों का कठोरता से पालन नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी उपस्थिति में छूट पाने के लिए वांछित दस्तावेज और प्रमाण पत्र जमा नहीं करा रहे और स्कूल भी सीबीएसई को हाजिरी की कमी के मामलों के बारे में सूचित नहीं कर रहे।

2019 के नतीजों के आकलन में पाया गया कि जिन विद्यार्थियों की हाजिरी कम थी लेकिन उन्हें परीक्षा में बैठने की छूट दी गई, उन्होंने परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया। अधिकारी के मुताबिक नियमों के अनुसार लंबी बीमारी होने पर, माता या पिता के निधन पर या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण और राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को इन मानक संचालक प्रक्रियाओं से छूट दी जा सकती है। उन्होंने ने कहा कि सभी मामलों में स्कूल को अभिभावकों द्वारा दिए अनुरोध पत्र, संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र और आवश्यक प्रोफार्मा में संबंधित स्कूल की सिफारिश संबंधी दस्तावेज जमा कराने होंगे।

सात जनवरी तक भेजनी होगी उपस्थिति की सूचना

हर शैक्षणिक सत्र में स्कूलों को एक जनवरी तक उपस्थिति संकलित करनी होगी और कम उपस्थिति के मामलों की पहचान करनी होगी। दस्तावेजों के साथा मामलों को सात जनवरी तक सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी के बारे में स्कूलों का बतांएगे और स्कूलों के पास इसका अनुपालन करने की समय सीमा होगी। सीबीएसई द्वारा इस मामले में मंजूरी देने के लिए अंतिम तिथि सात फरवरी होगी।

15 अगस्त को लोक उत्सव के तौर पर मनाएं : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन एवं स्वतंत्रता दिवस का जिक्र करते हुए देशवासियों से आजादी का पर्व मनाने एवं इसे लोक उत्सव बनाने के लिए नए तरीके ढूंढने का आग्रह किया ।

प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने संबोधन में कामना की कि सावन का यह सुंदर और जीवंत महीना आप सबमें नई ऊर्जा, नई आशा और नई उम्मीदों का संचार करे। उन्होंने कहा कि अगस्त महीना 'भारत छोड़ो' आंदोलन की याद ले कर आता है। मैं चाहूंगा कि 15 अगस्त की कुछ विशेष तैयारी करें आप लोग। आजादी के इस पर्व को मनाने का नया तरीका ढूढें। जन भागीदारी बढ़े। मोदी ने कहा, 15 अगस्त लोकोत्सव कैसे बने? जनोत्सव कैसे बने? इसकी चिंता जरुर करें आप। उन्होंने कहा कि यही वह समय है, जब देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। कई हिस्सों में देशवासी बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से कई प्रकार के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं।

बाढ़ के संकट में घिरे उन सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं, कि केंद्र, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का काम बहुत तेज गति से कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम टीवी देखते हैं तो बारिश का एक ही पहलू दिखता है–सब तरफ बाढ़, भरा हुआ पानी, ट्रैफिक जाम। मोदी ने कहा कि मानसून की दूसरी तस्वीर–जिसमें आनंदित होता हुआ हमारा किसान, चहकते पक्षी, बहते झरने, हरियाली की चादर ओढ़े धरती–यह देखने के लिए तो आपको खुद ही परिवार के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बारिश, ताजगी और खुशी यानी ताजगी और खुशहाली दोनों ही अपने साथ लाती है। मेरी कामना है कि यह मानसून आप सबको लगातार खुशियों से भरता रहे। आप सभी स्वस्थ रहें।

- 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा, सावन का यह सुंदर और जीवंत महीना आप सबमें नई ऊर्जा, नई आशा और नई उम्मीदों का संचार करे

प्रधानमंत्री ने अमरनाथ यात्रा की सफलता के लिए जम्मू–कश्मीर के लोगों और उनकी मेहमान–नवाजी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ए सारी चीज़ें भविष्य में पर्यटन के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली हैं। उन्होंने इस महीने में श्रद्धालुओं के कांवड़ यात्रा पर जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी इस वर्ष जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, तब से डेढ़ महीने के भीतर 8 लाख से अधिक श्रद्धालु, केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। 2013 में आई भीषण आपदा के बाद, पहली बार, इतनी रेकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री वहां पहुंचे हैं। मोदी ने कहा, मेरी आप सभी से अपील है कि देश के उन हिस्सों में आप जरुर जाएं, जिनकी खूबसूरती, मानसून के दौरान देखते ही बनती है।

नरेंद्र मोदी ऐप पर बनेगा स्थायी पुस्तक कार्नर, प्रधानमंत्री ने नाम सुझाने को कहा

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक पढ़ने के महत्व को रेखांकित करते हुए नरेंद्र मोदी ऐप पर एक स्थायी पुस्तक कार्नर बनाने का विचार व्यक्त किया और लोगों से इस पुस्तक कार्नर के लिये नाम सुझाने को कहा।

आकाशवाणी पर प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार प्रेमचंद जी की कहानियों की एक पुस्तक पर चर्चा के दौरान हमने तय किया था कि जो भी किताब पढ़ें, उसके बारे में कुछ बातें नरेंद्र मोदी एप के माध्यम से सबके साथ साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा, 'क्यों न हम नरेंद्र मोदी एप पर एक स्थायी पुस्तक कार्नर ही बना दें और जब भी हम नई किताब पढ़ें, उसके बारे में वहां लिखें, चर्चा करें और आप हमारे इस पुस्तक कार्नर के लिए, कोई अच्छा सा नाम भी सुझा कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि यह पुस्तक कार्नर पाठकों और लेखकों के लिए, एक सक्रिय मंच बन जाए।

मोदी ने की 'चंद्रयान 2' से जुड़ी प्रतियोगिता की घोषणा

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'चंद्रयान-2' मिशन के सफल प्रक्षेपण का जिक्र करते हुए रविवार को स्कूली बच्चों के लिए एक क्विज प्रतियोगिता की घोषणा की, जिसमें सर्वाधिक स्कोर करने वाले बच्चों को 7 सितंबर को श्रीहरिकोटा में 'चंद्रयान 2' की लैंडिंग के क्षण का साक्षी बनने का मौका मिलेगा।

आकाशवाणी पर प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि 'चंद्रयान 2 मिशन' ने एक बार फिर यह साबित किया है कि जब बात नए क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने की हो, नवोन्मेषी लगन की हो, तो हमारे वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ हैं, विश्वस्तरीय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में भी मुश्किलों को पार करने का सामर्थ्य हमारे भीतर ही है। मोदी ने कहा कि 'मन की बात' के माध्यम से वह देश के विद्यार्थी दोस्तों के साथ, युवा साथियों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प प्रतियोगिता के बारे में जानकारी साझा करना चाहते हैं और देश के युवक-युवतियों को इसके लिए निमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं स्कूलों से, अभिभावकों से, उत्साही आचार्यों और शिक्षकों से विशेष आग्रह करता हूं कि वे अपने स्कूल को विजयी बनाने के लिए भरसक मेहनत करें। ईनाम के रूप में सर्वाधिक स्कोर करने वाले बच्चों को 7 सितंबर को श्रीहरिकोटा में 'चंद्रयान 2' की लैंडिंग के क्षण का साक्षी बनने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे, आपको विजयी होना होगा।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कचरे से संसाधन (वेस्ट टू वेल्थ) बनाने का कल्चर हमारे समाज में विकसित हो। एक तरह से कहें, तो हमें कचरे से कंचन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने 'गांव की ओर लौट चलो' कार्यक्रम का भी उल्लेख किया और कहा कि इसके बारे में पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए। कश्मीर के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ने को कितने बेताब हैं, कितने उत्साही हैं, यह इस कार्यक्रम से पता चलता है। मोदी ने कहा कि ये साफ है कि जो लोग विकास की राह में नफरत फैलाना चाहते हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, वो कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते।

प्रधानमंत्री ने पुस्तक पढ़ने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, 'क्यों न हम नरेंद्र मोदी ऐप पर एक स्थायी पुस्तक कार्नर बना दें और जब भी नई किताब पढ़ें, उसके बारे में वहाँ लिखें, चर्चा करें। आप हमारे इस पुस्तक कार्नर के लिए, कोई अच्छा सा नाम भी सुझा कर सकते हैं। उन्होंने स्वच्छता एवं जल संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि त्योहारों के अवसर पर कई मेले लगते हैं।

जल संरक्षण पर जागरूकता फैलाने के लिए इन मेलों का भी उपयोग करें। इस संदर्भ में उन्होंने मेघालय की जल-नीति का जिक्र किया और राज्य सरकार को बधाई दी। उन्होंने हरियाणा में उन फसलों की खेती को बढ़ावा देने की पहल का भी जिक्र किया जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और किसान का भी कोई नुकसान नहीं होता है प्रधानमंत्री ने कहा कि मास्को में 'वर्ल्ड चिल्ड्रेंस वीनर्स गेम्स' का आयोजन हुआ। यह एक ऐसी अनोखी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें कैंसर से बचने वाले युवा ही हिस्सा लेते हैं। इसमें हमारे देश के दस चैंपियनों ने पदक जीते। इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने तो एक से ज्यादा खेलों में पदक जीते।

महाराष्ट्र में 240 सीटों के लिए कांग्रेस से हुआ समझौता : पवार

पुणे, 28 जुलाई (भाषा) ।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी और कांग्रेस के बीच 288 विधानसभा सीटों में से 240 सीटों पर सहमति बनी है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं

उधर राकांपा प्रमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के अन्य मंत्रियों पर विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं की खरीद-फरोख्त में लगे होने का आरोप लगाया।

राकांपा प्रमुख पवार ने कहा कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में आपत्तियों के चलते विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की योजना बना रही है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा कि दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेता शेष सीटों के लिए स्वाभिमानी पक्ष जैसे अन्य संगठनों से बात करेंगे। उन्होंने कहा, राकांपा और कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 240 सीटों पर सहमत हुए हैं। पवार ने बताया कि सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी कर ली जाएगी और अगले कुछ दिनों में विधानसभा क्षेत्रवार उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कांग्रेस-राकांपा गठबंधन के साथ आने के सवाल पर पवार ने कहा, मुंबई में मैंने कुछ मनसे नेताओं से मुलाकात की। हाल में राज ठाकरे सोनिया गांधी से मिले।

मनसे नेताओं को ईवीएम को लेकर संदेह हैं और उनका मानना है कि इस संबंध में कुछ फैसला किए जाने की आवश्यकता है। मनसे चुनाव बहिष्कार के पक्ष में है लेकिन यह हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है।

पुणे में रविवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार।

कश्मीर में कर्मियों को राशन जमा करने के आरपीएफ अधिकारी के निर्देश पर विवाद

श्रीनगर, 28 जुलाई (भाषा)।

बडगाम में रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने पत्र लिखकर कर्मचारियों से 'लंबे समय तक' कश्मीर घाटी में 'कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका' के कारण राशन जमा करने समेत अन्य कदम उठाने को कहा। इस पत्र के बाद विभाग में खलबली मच गई और रेलवे ने शनिवार को स्पष्ट किया कि इस पत्र का कोई आधार नहीं है और इसे जारी करने का संबंधित अधिकारी के पास कोई अधिकार नहीं है। आरपीएफ बडगाम के सहायक सुरक्षा आयुक्त सुदेश नुग्याल के इस पत्र को व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐसे पत्र के मंसूबे पर सवाल खड़ा किया है।

पत्र में कहा गया है, 'कश्मीर घाटी में लंबे समय तक स्थिति के बिगड़ने की आशंका और कानून व्यवस्था के संबंध में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और एसएसपी/जीआरपी/ एसआईएनए (श्रीनगर के सरकारी रेलवे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) से मिली जानकारी के अनुरूप 27 जुलाई को एहतियात सुरक्षा बैठक हुई।' नुग्याल ने कर्मचारियों से कम से कम चार महीने के लिए राशन इकट्ठा कर लेने और अपने परिवार को घाटी के बाहर पहुंचा आने समेत एहतियाती कदम उठाने का आह्वान किया है।

मलबे में दबकर चार कांवड़ियों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 28 जुलाई।

उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में कुंजापुरी-ऋषिकेश मार्ग में कार्बन पब्लिक स्कूल के पास पहाड़ से सड़क पर आए मलबे में दस कांवड़िए दब गए। इनमें से चार कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल हुए छह कांवड़ियों को नरेंद्र नगर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। वहीं, दूसरी घटना में रविवार को टिहरी जिले में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इसमें मौके पर दो लोगों की मौत हो गई।

पहली घटना में पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीमों ने बचाव अभियान चलाया। घायल कांवड़ियों में से गंभीर रूप से घायल दो कांवड़ियों को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक कांवड़ियों में से तीन की पहचान हरियाणा के रेवाड़ी के कमल सिंह, सन्नी और लोकश के रूप में हुई है।

हादसा रविवार सुबह ग्यारह बजे हुआ। निर्माणाधीन आल वेदर रोड का मलबा कांवड़ियों पर गिरा। इस रोड का निर्माण एक साल से चल रहा है। टिहरी के जिलाधिकारी वी. षणमुगम ने बताया कि कावड़ियों का वाहन गंगोत्री से गंगाजल भरकर हरियाणा जा रहा था। जैसे ही यह वाहन नरेंद्र नगर पहुंचा तो यह वाहन मलबे की चपेट में आ गया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कावड़ियों की हादसे में हुई मौत पर गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को घायल कांवड़ियों का इलाज उच्च प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया।

दूसरी घटना में रविवार को टिहरी जिले के चंबा-साबली मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मौके पर दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह 10 बजे मारुति कार सड़क से दो सौ मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में दो मृतकों की पहचान दीपक बहुगुणा (40) और प्रेरणा (17) के रूप में हुई है। पुलिस ने घायलों को चंबा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

The Indian EXPRESS Classifieds FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

BHARTI CONCEPT

English Vocab by Ravi Bajaj Sir

Batch Starts 31st July 2019 At 10:30AM to 11:30AM

DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9

9136335283, 09250291082

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

सड़क दुर्घटना व वाहन की चोरी रोकने के लिए ऐप | छात्र वैज्ञानिक | बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी के प्रिंट निकालने की तकनीक

सातवीं कक्षा के छात्र ने किया चार पेटेंट के लिए आवेदन

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने सड़क दुर्घटना और वाहनों की चोरी रोकने के लिए कुछ ऐप तैयार किए हैं। वह अभी बमुश्किल 12 साल का है लेकिन अब तक पेटेंट के लिए चार आवेदन कर चुका है।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के इस प्रतिभावान छात्र बीएस रेवंत नंबुरि से मुलाकात की और प्रस्तुति को देखा। गडकरी ने उसकी प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल में लाने में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। हालांकि इन ऐप को अभी तकनीकी मंजूरी नहीं मिली है।

रेवंत नागपुर के माउंट लिटेरा जी स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र है। उसने यातायात के नियमों के उल्लंघन पर पल-पल की तत्काल निगरानी के लिए ऐप तैयार किए हैं। ऐप में सीटबेल्ट सेंसर, ब्रीथेलाइजर, हर्ट रेट एनालाइजर और सीपीयू शामिल हैं जो सूचनाओं को जमा करता है और प्राधिकरणों को सावधान करता है।

दूसरा ऐप क्यूआर कोड पर आधारित है और बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी के कहीं भी डेटा या दस्तावेज का प्रिंट निकालने की सुविधा देता है। एक अन्य पेटेंट वाहनों की चोरी रोकने से संबंधित है। यह एक स्मार्ट की, पहले से लगे सिम कार्ड का इस्तेमाल करता है। रेवंत ने कहा कि उसकी प्रौद्योगिकी वृहद स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचा सके, यही सोचकर पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है ताकि इन्हें सरकार या किसी निजी निकाय को हस्तांतरित किया जा सके।

नई दिल्ली में छात्र बीएस रेवंत नंबुरि से मुलाकात करते केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होड़

सिद्धू और सिन्हा का नाम आगे

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

- दिल्ली से बाहर के व्यक्ति को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने की चर्चा जोरों पर
- जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित, योगानंद शास्त्री, माकन, लवली, महाबल भी दौड़ में

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू या बिहारी बाबू के नाम से मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली कांग्रेस की कमान सौंपे जाने की चर्चा तेज है। शीला दीक्षित के निधन के बाद खाली हुई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कई दावेदार यहीं दिल्ली में मौजूद हैं लेकिन इनके बीच आपस में छिड़ी सियासी जंग के मद्देनजर पार्टी हाईकमान बाहर के किसी नेता को दिल्ली की बागडोर सौंपने के मुद्दे पर मंथन कर रही है।

दिल्ली में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर जारी चर्चा के बीच पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब पार्टी में सिद्धू को दिल्ली लाए जाने पर चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पद से अजय माकन के इस्तीफे के बाद भी नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिन नेताओं के नाम पर पार्टी में उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई, उनमें सिद्धू का नाम शामिल था। हालांकि उस वक्त आम राय शीला दीक्षित के नाम पर बनी। उन्होंने कहा कि ऐसे आसार हैं कि पार्टी नेतृत्त्व दिल्ली में बाहर के किसी नेता को लाकर प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है।

विदेश से लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में शीला दीक्षित के घर पर उनके परिजनों के साथ ढाई-तीन घंटे का वक्त गुजारा और परिवार के सभी सदस्यों से उनका दुख बांटा। शायद यह पहला मौका होगा जब दिल्ली में पार्टी के किसी नेता के घर पर राहुल ने इतना वक्त गुजारा हो। इससे दिल्ली के सियासी गलियारों में संदीप दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई। राहुल के जाने के बाद संदीप ने स्वीकार किया कि पार्टी की गुटबाजी के कारण दीक्षित अपने आखिरी दिनों में निराश थीं। जाहिर तौर पर पार्टी नेतृत्त्व को भी यह मालूम है कि शीला के बाद अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली के किसी एक नेता के नाम पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। खासकर, कुछ ही महीनों बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को एक चमकते चेहरे की दरकार है जिसको लेकर कोई विवाद न हो।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि अजय माकन स्वेच्छा से प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं जबकि जयप्रकाश अग्रवाल, योगानंद शास्त्री, सुभाष चोपड़ा या महाबल मिश्रा सरीखे नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में एक बड़ी बाधा गुटबाजी बताई जा रही है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली एक बेहतरीन पसंद हो सकते हैं लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनाने पर कुछ लोग उनके भाजपा में जाने और लौटकर आने का मुद्दा उठा सकते हैं। शीला दीक्षित के साथ हारुन युसूफ, देवेंद्र यादव व राजेश लिलौठिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने आगे के लिए रास्ता बनाने की कोशिश जरूर की लेकिन दीक्षित के रहते यह प्रयोग बहुत सफल नहीं हो पाया। ऐसे में यदि पार्टी हाईकमान सिद्धू या शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली की कमान सौंपता है तो यह एक प्रकार से इतिहास दोहराने वाली बात होगी।

आरक्षित सीटों को भरने के लिए डीयू का आज से विशेष अभियान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पांच कटऑफ आने के बाद भी सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में डीयू प्रशासन ने खाली सीटों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विशेष अभियान 29 और 30 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद एक अगस्त को कॉलेज छठी कटऑफ जारी करेंगे। इस कटऑफ के आधार पर एक से तीन अगस्त तक दाखिला लिया जा सकेगा। छठी कटऑफ के बाद यदि सीटें खाली रहती हैं तो कॉलेज 6 अगस्त को सातवीं कटऑफ भी जारी करेंगे। इसके आधार पर 8 अगस्त तक दाखिले की प्रक्रिया चलेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, दाखिला समिति ने विशेष अभियान चलाने की संस्तुति की है। रजिस्ट्रार के मुताबिक इस अभियान के तहत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, कश्मीर विस्थापित और सिख अल्पसंख्यक वर्ग शामिल हैं। इन वर्गों के विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण कराते समय किसी कारणवश यदि संबंधित श्रेणी में पंजीकरण नहीं कर पाए थे तो वे अब इस अभियान के तहत श्रेणी बदलाव कर सकते हैं। श्रेणी बदलाव के बाद ऐसे विद्यार्थी यदि प्रवेश परीक्षा आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए योग्य होते हैं तो वे इन पाठ्यक्रमों के लिए जारी की जाने वालीं अगली सूचियों में दाखिला ले सकते हैं। ये विद्यार्थी जारी हो चुकी सूचियों के आधार पर दाखिला लेने का दावा नहीं कर सकते हैं।

एनसीवेब में भी मौके

दिल्ली की जिन छात्राओं ने डीयू से संबद्ध नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) के लिए आवेदन नहीं किया है। वे भी स्वतः एनसीवेब में दाखिले के लिए योग्य हैं। यदि अभी तक आई किसी भी कटऑफ में उनका नंबर आया है तो वे दाखिला ले सकती हैं।

प्रवेश रद्द कराने वाले भी ले सकते हैं दाखिला

ऐसे विद्यार्थी जो पांचवीं कटऑफ तक किसी न किसी कटऑफ में दाखिले के योग्य थे और उन्होंने दाखिला नहीं लिया या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दाखिला लेने के बाद उसे रद्द करा दिया और अब तक कहीं भी दाखिला नहीं लिया है। इन सभी विद्यार्थियों को सीट रहने की स्थिति में छठी कटऑफ में दाखिले का मौका दिया जाएगा।

स्तन कैंसर ऊतकों की पहचान के लिए एम्स ने शुरू की नई तकनीक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में हाल ही में स्तन कैंसर से प्रभावित ऊतकों की आसान पहचान के लिए एक नई तकनीक शुरू की गई है। यह अत्याधुनिक फ्लोरेसेंस इमेजिंग तकनीक है। एम्स में सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग के मुखिया डॉक्टर एसवीएस देव के मुताबिक स्तन कैंसर की सर्जरी के क्षेत्र में यह प्रौद्योगिकी बड़ा बदलाव लेकर आएगी क्योंकि यह सटीक रूप से प्रासंगिक ऊतक की पहचान करने में मदद करती है।

स्तन कैंसर की सर्जरी के दौरान डॉक्टर रोगियों में एक सुरक्षित और सस्ती इंडोसायनीन ग्रीन (आइसीजी) डाई इंजेक्ट करते हैं। फ्लोरेसेंस इमेजिंग तकनीक का उपयोग करते हुए सर्जन खून की नसों, महीन नसों, ऊतकों और महत्त्वपूर्ण शारीरिक संरचनाओं में अंतःक्रियात्मक रूप से खून का प्रवाह देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रासंगिक ऊतक फ्लोरोसेंट हरे रंग में प्रकाशित होते हैं। वर्तमान में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों जैसे नीले डाई की तुलना में इमेजिंग की विश्वसनीयता और कई अनुप्रयोग एक महत्त्वपूर्ण अंतर पैदा करता है।

कांग्रेस को बचाने की कवायद

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

दिल्ली में कांग्रेस को बचाना शीला दीक्षित के न रहने से ज्यादा कठिन हो गया है। कांग्रेस जितनी पुरानी पार्टी है, पार्टी की गुटबाजी उतनी ही पुरानी है। गुटों में बैठी कांग्रेस को दिल्ली में वजूद को बचाने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) से चार फीसद ज्यादा वोट लाकर कांग्रेस ने वापसी के संकेत दिए। कांग्रेस 22.50 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रही। भाजपा को 57 फीसद वोट मिले। विधानसभा के हिसाब से इस नतीजे में भाजपा 70 में से 65 सीटों पर और कांग्रेस पांच विधानसभा सीटों पर पहले नंबर पर रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सरकार के सात में से पांच मंत्रियों के इलाके में 'आप' तीसरे नंबर पर रही। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 'आप' को कोई सीट नहीं मिली थी लेकिन तब वह दूसरे नंबर पर रही और 'आप' और भाजपा के वोटों का अंतर 13 फीसद था, इस बार अंतर करीब 39 फीसद रहा।

2015 के विधानसभा चुनाव के बाद 'आप' का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिर रहा है। शीला दीक्षित के 15 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान दिल्ली के विकास कार्य ही कांग्रेस को सत्ता में वापस ला सकते हैं। यह केवल लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही नहीं दिखा बल्कि 'आप' सरकार की बेचैनी से भी दिख रहा है। जिन कामों के लिए शीला दीक्षित दिल्ली के इतिहास में अपना स्थान बना पाईं उन्हीं कामों को 'आप' दुहरा रही है। दीक्षित ने कांग्रेस को दिल्ली में जीतना सिखाया और दिल्ली की बहुशासन प्रणाली में सीमित अधिकारों के बूते दिल्ली का कायाकल्प कर दिया। 15 सालों में करीब सौ फ्लाईओवर और अंडर पास बने। दिल्ली के हर इलाके में मैट्रो पहुंची, आधुनिक लो फ्लोर बसें दिल्ली में चलने लगीं। दूसरे राज्यों में अपने पैसे से बिजली घर बना कर दिल्ली को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। पानी की उपलब्धता बढ़ाई। जिस सिग्नेचर ब्रिज को दिल्ली की मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धि बनाकर प्रचारित किया, उसके लिए कई अधिकारियों को सेवा विस्तार दिलाया और अपनी पार्टी के ही अनेक नेताओं की नाराजगी झेलकर उसे पूरा करवाया।

इस साल दस जनवरी को शीला दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनके साथ तीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। कहा यही गया कि 80 पार की दीक्षित का चेहरी सामने रहेगा लेकिन काम तीनों कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे। पार्टी के उनके विरोधियों ने कहा कि वे तो 'आप' से समझौता करवाने के लिए अध्यक्ष बनीं। वास्तविकता इसके उलट साबित हुई। दीक्षित ने कहा कि जब पार्टी के अधिकांश नेता अपने बूते चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम किसी दल से समझौता क्यों करें। कायदे से उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था लेकिन राजनीतिक गुटबाजी के चलते उन्हें चुनाव लड़वाया गया। कांग्रेस तीसरे से दूसरे नंबर पर आई। अगर वे चुनाव लड़ने के बजाए केवल प्रचार करतीं तो नतीजे अलग होते। इन नतीजों के सहारे भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बेहतर नतीजे ला सकती थी। 'आप' आम लोगों के सत्ता में भागीदारी के दावे करती रही है लेकिन सही मायने में आरडब्लूए को सक्रिय करके भागीदारी अभियान शीला दीक्षित ने चलाया। 1998 में दिल्ली में वन क्षेत्र आठ फीसद थे, उसे उन्होंने 20 फीसद तक पहुंचाया। स्वच्छ दिल्ली, हरी दिल्ली (ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली) अभियान तभी का चलाया हुआ है।

दिल्ली की सूरत बदलने के लिए शीला दीक्षित ने असंख्य काम किए। मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं, उनका नारा खूब लोकप्रिय हुआ था। जाहिर है आज के कांग्रेस के कई नेता उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और उनका योगदान भी दिल्ली को संवारने में रहा है।

'मन की बात' सुनने के लिए जगह-जगह आयोजन, भाजपा सदस्य भी बनाए गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

दिल्ली प्रदेश भाजपा की ओर से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' सुनने के लिए सभी 280 मंडलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और उत्तरी-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी सहित कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकर्ता के अलावा स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना।

'मन की बात' कार्यक्रम के बाद आरकेपुरम स्थित तमिल संगम सभागार में उपस्थित लोगों से मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री राजनीति से ऊपर उठकर जनकल्याण के मुद्दों को मन की बात में उठाते हैं। 'मन की बात' कार्यक्रम नए भारत के निर्माण में सहायक है। इस दौरान समाज के सभी वर्ग के लोगों को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता भी दिलवाई गई।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से 15 अगस्त की कुछ विशेष तैयारी करने की अपील की। मॉडल टाउन विधानसभा के आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल, डेरावाल नगर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 'मन की बात' कार्यक्रम को स्थानीय लोगों के साथ सुनने के बाद संगठन पर्व सदस्यता अभियान के अंतर्गत लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई।

फंसी योजनाओं को दौड़ाने में लगी दिल्ली सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने भी जमीनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अब तक विपक्ष के निशाने पर दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक, सीसीटीवी कैमरा, बस और निर्माण से संबंधित योजनाएं थीं। इसलिए दिल्ली सरकार ने इन योजनाओं की रफ्तार बढ़ा दी है।

शास्त्री पार्क फ्लाइओवर : राजमार्ग-24 पर जाम से राहत के लिए फ्लाइओवर निर्माण का कार्य दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग को इस कार्य का जिम्मा दिया गया है। इस मार्ग पर दिल्ली सरकार ने एकतरफा फ्लाइओवर को डबल करने और शास्त्री पार्क रेड लाइट को सिग्नल फ्री करने पर काम कर रही है। बीते दो माह में इस परियोजना ने तेज रफ्तार पकड़ी है और फ्लाइओवर के लिए खंभा बनाने का कार्य पूरा किया गया है। जल्द ही इस सबसे व्यस्ततम मार्ग पर वाहनों को जाम से मुक्ति मिलेगी। फरवरी में दिल्ली सरकार ने इस कार्य की शुरुआत की थी। इस मार्ग पर 1200 मीटर का एकतरफा फ्लाइओवर बन रहा है, जबकि शास्त्री पार्क पर 700 मीटर को दोनों तरफा फ्लाइओवर बनाया जा रहा है।

पटपड़गंज को मिला नया मोहल्ला क्लीनिक : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को मोहल्ला क्लीनिक का उद्घाटन किया। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मोहल्ला क्लीनिक क्षेत्र की आवश्यकता है और नवंबर तक क्षेत्र को 4 और मोहल्ला क्लीनिक मिलेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा की मदद से वे क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में एक एमबीबीएस डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति की वजह से एक मोहल्ला क्लीनिक तोड़ा गया है। जल्द ही पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के पास 8 मोहल्ला क्लीनिक होंगे। ऐसी ही तैयारियां दिल्ली की अन्य विधानसभाओं में भी की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने सीसीटीवी कैमरे और बसों को लेकर भी कवायद शुरू कर दी है।

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the Corporate Debtor	Lanco Solar Private Limited
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	July 16, 2008
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, - Hyderabad
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U74900TG2008PTC060157
5.	Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of Corporate Debtor	Registered Office: Plot No.4, Software Units Layout, HITEC City, Madhapur, Hyderabad - 500 081 Corporate Office: Lanco House, 397
6.	Insolvency Commencement Date of the Corporate Debtor	May 17, 2019 (order made ready and available on May 30, 2019)
7.	Date of Invitation of Expression of Interest	July 29, 2019 The detailed invitation for expression of interest is available on the website of the Corporate Debtor and can be obtained from www.lancogroup.com
8.	Eligibility for Resolution Applicants under Section 25(2)(h) of the Code is available at:	The eligibility criteria is set out in the detailed invitation for expression of interest, which can be obtained from www.lancogroup.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	These norms are set out in the detailed invitation for expression of interest
10.	Last date for receipt of Expression of Interest	August 25, 2019
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	August 31, 2019
12.	Last date for submission of objections to provisional list	September 05, 2019
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	September 15, 2019
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	August 31, 2019
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Will be provided by the Resolution Professional to the Prospective Resolution Applicants who are determined to be eligible as per the process laid down in the detailed invitation for expression of interest and in accordance with Regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016.
16.	Last date for submission of Resolution Plans	October 15, 2019
17.	Manner of submitting Resolution Plans to Resolution Professional	Will be provided by the Resolution Professional to the Prospective Resolution Applicants who are determined to be eligible as per the process laid down in the detailed invitation for expression of interest and in accordance with Regulation 36A and 36B of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016.
18.	Estimated date for submission of Resolution Plan to the Adjudicating Authority for approval	November 10, 2019
19.	Name and registration number of the resolution professional	**Name:** Huzefa Fakhri Sitabkhan **Registration Number:** IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	**Name:** Huzefa Fakhri Sitabkhan **Address:** 1012, Dalamal Tower, Free Press Journal Road, 211, Nariman Point, Mumbai - 400021 **Email:** huzefa.sitabkhan@gmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	**Address for Correspondence:** 1007-1013, Dalamal Tower, Free Press Journal Road, 211, Nariman Point, Mumbai - 400 021 **Email:** iplancosolar@gmail.com; lancosolar@thinkcapital.in
22.	Further Details are available at or with	www.lancogroup.com
23.	Date of publication of Form G	July 29, 2019

JAIPRAKASH
ASSOCIATES LIMITED

Regd. Office: Sector 128, Noida 201 304 [U.P]
Head Office: "JA House", 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057
Phone : + 91 (120) 4609000; **FAX :** + 91 (120) 4609464; **CIN :** L14106UP1995PLC019017 **Website** : www.jalindia.com, **E-mail:** jal.investor@jalindia.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

(₹ in Lacs)

S. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 30.06.2019 [Unaudited]	Quarter Ended 30.06.2018 [Unaudited]	Year Ended 31.03.2019 [Audited]	Quarter Ended 30.06.2019 [Unaudited]	Quarter Ended 30.06.2018 [Unaudited]	Year Ended 31.03.2019 [Audited]
1.	Total Income from Operations	119988	169082	683323	241961	262531	1082075
2.	Net Profit /(Loss) for the period [before Tax, Exceptional and Extraordinary Items]	(15876)	(9309)	(35006)	(73534)	(51117)	(208989)
3.	Net Profit /(Loss) for the period before Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]	(15876)	(9309)	(35006)	(74857)	(54651)	(219658)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]	(15883)	(28502)	(77368)	(75094)	(73845)	(270951)
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(15883)	(28502)	(77057)	(75092)	(73843)	(270613)
6.	Equity Share Capital [of ₹ 2/- per share]	48649	48649	48649	48649	48649	48649
7.	Other Equity [excluding Revaluation Reserve]			826697			56937
8.	Earnings Per Share [of ₹ 2/- per share] [for continuing and discontinued operations]:						
	Basic	₹ (0.65)	₹ (1.17)	₹ (3.18)	₹ (2.36)	₹ (2.49)	₹ 8.68)
	Diluted	₹ (0.65)	₹ (1.17)	₹ (3.18)	₹ (2.36)	₹ (2.49)	₹ (8.68)

Note : The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended 30th June, 2019 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended 30th June, 2019 Financial Results are available on the Stock Exchanges Website www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's Website www.jalindia.com.

Place : Greater Noida
Dated : 27th July, 2019

MANOJ GAUR
Executive Chairman
DIN - 00008480

JAYPEE GROUP
NO DREAM TOO BIG

क्लस्टर बस ने मारी टक्कर

मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

- मायापुरी थाना क्षेत्र के लाजवंती चौक पर लाल बत्ती पर खड़ा था मोटरसाइकिल सवार
- हादसे के बाद लोगों ने बस का पीछा कर आरोपी चालक को पकड़ा

मायापुरी थाना क्षेत्र के लाजवंती चौक पर लाल बत्ती पर खड़े एक मोटरसाइकिल सवार शख्स को क्लस्टर बस चालक ने कुचल दिया। इस हादसे में लखन (37) की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि घटना के समय कलस्टर बस चालक काफी तेज रफ्तार से बस चला रहा था। हादसे के बाद लोगों ने बस का पीछा कर आरोपी चालक को पकड़ लिया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक विक्रांत कुमार (23) को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, लखन अपने परिवार के साथ शकूरपुर में रहते थे। वे एक निजी कंपनी में काम करते थे। वे शुक्रवार रात कंपनी से घर आने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे। पर लाजवंती चौक पर लाल बत्ती होने की वजह से वे रुक गए थे। इसी दौरान सागरपुर की ओर से आ रहे क्लस्टर बस चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। बाद में बस उनके ऊपर से गुजर गई।

इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस लखन को पास के डीडीयू अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि उनके शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है।

यमुना में कूदा शख्स, नहीं मिला कोई सुराग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में स्थित फ्लाईओवर से रविवार सुबह एक शख्स ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और दो दमकलों के साथ कर्मचारी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शख्स को बहुत तलाशा मगर उसका कुछ पता नहीं चला। अंधेरा होने पर गोताखोरों ने शख्स की तलाश बंद कर दी। सोमवार सुबह फिर शख्स की तलाश शुरू की जाएगी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शख्स की पहचान गांधी नगर निवासी कपिल शर्मा (35) के रूप में हुई है। पुलिस को उसकी मोटरसाइकिल फ्लाईओवर के सड़क किनारे मिली है। पुलिस के मुताबिक, कपिल अपने परिवार के साथ गांधी नगर में रहता था। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। कपिल आनंद पर्वत में लोहे का काम करता है।

शाहबेरी मामला फ्लैट खरीदारों ने खोला मोर्चा

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 28 जुलाई।

शाहबेरी के फ्लैट खरीदारों ने प्राधिकरण व प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने शाहबेरी से गौड़ सिटी चौक तक पदयात्रा निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घर बचाने की गुहार लगाई है। पैदल मार्च में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। इलाके में बनी इमारतों में हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं।

निर्माण को अवैध बताते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ध्वस्त करने की चेतावनी दे रखी है। अवैध निर्माण पर प्रदेश सरकार के कड़ रुख को देखते हुए लोगों की नींद उड़ गई है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट का शाहबेरी गांव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिसूचित क्षेत्र होने की वजह से यहां प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति निर्माण कार्य नहीं कर सकता, लेकिन प्राधिकरण के नियम कानून को ताक पर रखकर बिल्डरों ने यहां बड़ी संख्या में बहुमंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी है। शाहबेरी में हुए अवैध निर्माण को सरकार ने ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इसके बाद से उन लोगों की नींद उड़ गई है, जो अपनी जिंदगी भर की कमाई फ्लैट खरीदने मे निवेश कर चुके हैं। प्राधिकरण की कार्रवाई से बचने के लिए शाहबेरी के निवासियों ने रविवार को गौड़ सिटी चौक तक पैदल मार्च निकाला। प्रशासन व प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फ्लैट खरीदरों ने कहा कि प्रशासन व प्राधिकरण के अधिकारी उस समय कहां थे, जब बिल्डर फ्लैट बना रहे थे। बिल्डर की गलती की सजा हम क्यों भुगतें। खरीदारों का तर्क है कि यदि निर्माण गलत था, तो प्राधिकरण ने रजिस्ट्री क्यों कराई। लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर जो भी जांच टीम बनी है, उसमें शाहबेरी के संघर्ष समिति के भी सदस्य हो, ताकि जांच टीम प्राधिकरण के दबाव में कोई गलत रिपोर्ट न सौंपे दे। प्राधिकरण व प्रशासन ने पहले पूरे क्षेत्र को आंख बंद करके बसने दिया।

परिवार के तीन सदस्यों की मौत

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी की पुष्टि

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

आइआइटी परिसर में वरिष्ठ लैब सहायक गुलशन, उसकी पत्नी सुनीता और मां कांता ने सामूहिक रूप से खुदकुशी की थी। रविवार को डॉक्टरों के एक पैनल ने जब तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया तो उससे यह पुख्ता हो गया कि यह मामला खुदकुशी का ही है। हालांकि पोस्टमार्टम में यह बात सामने आई है कि गुलशन ने थोड़ी देर के बाद खुदकुशी की जबकि मां और पत्नी ने एक साथ पंखे से लटककर जान दी। तीनों ने खुदकुशी से पहले कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। खुदकुशी घरेलू कलह की वजह से की गई।

जिले के पुलिस उपायुक्त देवेंद्र आर्या ने रविवार रात को बताया कि पूछताछ में पुलिस और एसडीएम को दिए बयान में सुनीता की मां कृष्णा देवी ने कहा था कि उसकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है।

15 लाख के जेवर चुराने के आरोप में घरेलू सहायिका गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 28 जुलाई।

- दंपति ने सावधानी के लिए जूतों की रैक में रखे थे 15 लाख रुपए के जेवरात
- जेवरात को पीतल का बताकर महज सवा लाख रुपए में सुनार ने खरीदा

सेक्टर-25 में एक घर से 15 लाख रुपए के जेवरात चोरी करने वाली घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया है। जेवरात को सुरक्षित रखने के लिए पीड़ित दंपति ने उन्हें जूतों की रैक में रखा था।

एसपी सिटी विनीत जायसवाल ने बताया कि सेक्टर-25 के एल ब्लॉक में रीति अपने पति के साथ रहती हैं। उन्होंने घर में काम करने के लिए करीब पांच साल पहले सेक्टर- 9 निवासी पिंकी को घरेलू सहायिका के रूप में रखा था। पीड़ित दंपति का मानना था कि चोरी होने पर भी चोर केवल बिस्तर, अलमारी आदि खंगालते हैं। एक कोने में रखी जूतों की रैक पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन घरेलू सहायिका ने उनको गलत साबित कर दिया। बताया गया है कि एक दिन जूतों की रैक की सफाई के दौरान पिंकी ने जेवरात देख लिए। तभी से वह उन्हें चोरी करने की योजना तैयार करने लगी। करीब 15 दिन पहले उसने मौका देखकर चुपके से सोने की आठ चूड़ियां, मांग का टीका, हीरे का एक कड़ा, एक हार और अंगूठी चोरी कर ली। चोरी के बाद वह काम करने आती रही। एक सप्ताह बाद उसने घरेलू दिक्कतें बताकर काम छोड़ दिया। चुराए हुए जेवरात बेचने के लिए पिंकी ने हरौला के एक सुनार नरेश से संपर्क किया। सुनार ने आधा माल पीतल का बताते हुए उसे महज सवा लाख रुपए देकर जेवरात लिए। रीति ने थाना सेक्टर-20 में मामला दर्ज कराते हुए पिंकी पर शक जताया। पुलिस ने तफ्तीश के आधार पर पिंकी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पिंकी ने चोरी की बात कबूल ली। पुलिस ने जेवरात बरामद कर दोनों आरोपियों को जेल भेजा है।

खबरों में शहर

ऑटो चालकों के साथ हुआ धोखा : गोयल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

राज्यसभा सदस्य और दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने रविवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के साथ धोखा किया है। गोयल ने बड़ी संख्या में ऑटो और टैक्सी चालकों को भाजपा की सदस्या दिलवाई। इस दौरान गोयल ने कहा कि ऑटो चालकों ने अपने आप को ठगा महसूस किया है। सभी आश्वासन वादे ही साबित हुए हैं।

पौधरोपण कार्यक्रम में पहुंचे खट्टर

फरीदाबाद, 28 जुलाई (जनसत्ता)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को फरीदाबाद में आयोजित जलशक्ति अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकारी और निजी स्कूलों के छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने आसपास के क्षेत्र में पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे पौधा लगाएं वो उसका फोटो खींच कर जियो टैगिंग पर भेजें। छह महीने बाद उसी पौधे का फोटो खींचकर दोबारा से भेजें। सरकार प्रत्येक छात्र-छात्रा के खाते में 50 रुपए जमा करवाएगी। लगातार तीन साल तक फोटो भेजने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में सरकार 600 रुपए जमा करवाएगी।

हरियाणा भवन में मीडिया सेंटर का उद्घाटन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

राजधानी स्थित हरियाणा भवन में नवनिर्मित मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में सभी जिला मुख्यालयों पर मीडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के विकास में मीडिया की महती भूमिका रही है। वर्तमान में मीडिया का कार्य और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है। हरियाणा भवन में भी विभिन्न सुविधाओं से युक्त 41 लाख 75 हजार रुपए की लागत से सेंटर स्थापित किया गया। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो व अतिरिक्त स्थानीय आयुक्त चंद्रशेखर खरे मौजूद रहे।

गुरुग्रंथ साहिब की प्रति पहुंचाएगी समिति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

दिल्ली सिख गुरु प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दुनिया भर में फैले अपने समुदाय के लोगों तक ग्रंथ गुरुग्रंथ साहिब की प्रति पहुंचाने के लिए कमर कसी है। यह ग्रंथ दिल्ली के अलावा केवल अमृतसर में ही छपता है, लिहाजा समिति ने ग्रंथ के प्रकाशन की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कई नई मशीनें स्थापित की हैं।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

भारत नीति प्रतिष्ठान: 'क्राइसिस आफ हिंदू सिविलाइजेशन' पर व्याख्यान, डिप्टी स्पीकर हाल, कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, शाम 4:30 बजे।

कांग्रेस बेहाल

दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष रहीं शीला दीक्षित के निधन के बाद दिल्ली कांग्रेस बुरे हाल में पहुंच गई है। गुटबाजी का आलम यह है कि शीला दीक्षित विरोधी खेमे के नेताओं को पिछले शनिवार को दीक्षित के निधन की सूचना मिलने के बावजूद के उस दिन अंतिम दर्शन की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सुना गया कि दीक्षित समर्थक एक नेता निधन के मौके पर ही विरोधियों को बुरा-भला कह रहे थे। निधन के मौके पर कोई और अप्रिय विवाद न होने के डर से सभी विरोधी दूसरे दिन शीला दीक्षित के अंतिम दर्शन कर पाए। दोनों गुट एक दूसरे पर भाजपा के हाथों खेलने का आरोप लगा रहे थे। शीला दीक्षित समर्थक तो यह भी कहने से नहीं चूके कि उनकी मौत पार्टी के विवाद के तनाव से हुई। वैसे वे काफी समय से बीमार थीं और मुख्यमंत्री रहते हुआ ही उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। इतना ही नहीं तबीयत पूरी तरह से ठीक न होने से उनका फ्रांस में भी इलाज हुआ। यह जरूर था कि इस उम्र में जिस तरह उनकी पार्टी के लिए उपयोगिता थी, वह नहीं की गई।

बड़ा दिल

शीला दीक्षित के निधन के दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के एक जत्थे के साथ वैष्णों देवी की यात्रा पर जाना था। उन्होंने जाना रद्द किया और अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ शीला दीक्षित के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गए। दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। वास्तव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के वोटों के बूते ही दिल्ली की सरकार में आई और कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक वर्ग उससे अलग होकर वापस कांग्रेस के साथ आया, अगर शीला दीक्षित स्वस्थ्य रह कर काम करती तो संभव था कि अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास वापस उसके और वोटर लौटते। दिल्ली में एक वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि शीला दीक्षित ने विपरित माहौल में दिल्ली को बेहतर करने का काम किया।

समय से आगे!

दिल्ली में मतदान संपन्न हुए ढाई महीने से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन सड़कों पर दौड़ते हुए दिल्ली परिवहन बेड़े की बसें आज भी 12 मई को मतदान जरूर करें की अपील करती नजर आ रही हैं। बीते दिनों केंद्रीय सचिवालय स्थित बस स्टॉप पर खड़े होकर बस की बाट जोह रहे लोगों के बीच जब एक व्यक्ति की नजर बस के डिसप्ले बोर्ड पर पड़ी तो उससे सहसा निकल पड़ी आवाज से कई लोग चौंक गए। दरअसल, बस वोट देने की अपील के साथ तारीख भी बता रही थी। किसी ने कहा-अच्छे दिन है। सरकार व महकमा चुस्त है! मौके पर मौजूद एक अन्य अधेड़ ने बात को आगे बढ़ाया। कहा- कौन कहता है डीटीसी की बसें तेज नहीं चलती वो तो समय से आगे चलती है। तभी तो 12 मई को आज भी दर्शा रही है। है न, समय से आगे!

खुली पोल

दिल्ली सरकार दावा करती है कि बारिश से पहले नालों और नालियों की सफाई कर ली गई है। पर हर बार बारिश के दिनों में दिल्ली जलमग्न हो जाती है और उन सभी विभागों के दावों की पोल खुल जाती है, जो प्रतिवर्ष दावा करते हैं कि इस बार दिल्लीवासियों को जलभराव से दो-चार होना नहीं पड़ेगा। इस बार भी दिल्ली के कई क्षेत्रों में अंडरपास में पानी भर गया और लोगों को अंडरपास पार करने के लिए ट्रैक्टर और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई तो विभाग के अधिकारी अपनी गलती मामने की बजाय दूसरे विभाग पर ठीकरा फोड़ते नजर आए। उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि अधिकारी यह मामने को तैयार ही नहीं थे कि उनके विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल दिल्ली बारिश के बाद जलमग्न हो जाती है और दावों की पोल खुलती है। बावजूद इसके विभाग के अधिकारी एक-दूसरे पर दोष मढ़ कर अपनी नाकामियों को छुपाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

महंगे शौचालय

स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर नोएडा की व्यस्त सड़कों पर बनाए निशुल्क सार्वजनिक शौचालय अब इनका इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। इसकी वजह यातायात पुलिस का अभियान है। पिछले कुछ दिनों में शौचालयों का इस्तेमाल करने वाले दर्जनों वाहन चालकों के चालान केवल इस वजह से काट दिए गए हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी की थी। दीगर है कि शहर में जहां भी इन शौचालयों को बनाया गया है, वे सभी व्यस्त मार्ग हैं। शौचालयों के आसपास काफी दूर तक कहीं भी ऐसी जगह नहीं हैं, जहां पर कुछ देर के लिए वाहन खड़ा किया जा सके। लिहाजा शौचालय का इस्तेमाल कर चंद ही मिनट में बाहर आने पर वाहन चालक को पता चलता है कि उसकी नो पार्किंग में खड़ी करने के चलते जब्त की जा रही है। गाड़ी छुड़ाने के लिए चालान भरवाया जा रहा है। दलील देने के बावजूद यातायात पुलिस कर्मी विभाग के लक्ष्य की प्रतिपूर्ति की बात कहकर कुछ सुनने को तैयार नहीं है।

गरीब कौन?

दिल्ली स्थित दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने वर्तमान में प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन नियुक्तियों में केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए हैं। प्रोफेसर पद पर नियुक्ति पाने के लिए उम्मीदवार के पास किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर पढ़ाने का कम से कम दस साल का अनुभव होना चाहिए। हमारे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर का शुरुआती वेतन एक लाख रुपए प्रति महीने के आसपास होता है। यानी उसे कम से कम सालाना 12 लाख रुपए की आमदनी होगी। यह तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की आमदनी है और इसमें उसके परिवार के अन्य सदस्यों की आमदनी नहीं जोड़ी गई है। ऐसे में कम से कम 12 लाख रुपए सालाना पाने वाला गरीब कैसे हो सकता है। ऐसा है तो फिर प्रोफेसर पदों पर ईडब्लूएस आरक्षण कैसे दिया जा रहा है।

कौन बांटेगा टिकट

दिल्ली में कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक अनिश्चितता का आलम है। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी की कमान कौन संभाले यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर तय नहीं हो पा रहा। कई राज्यों में नेतृत्त्व के सवाल पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में यह संकट नये सिरे से खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित के निधन के बाद अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन कुछ ही महीने बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सूबे के कांग्रेसियों को इस खबर में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो अगला अध्यक्ष बनेगा, वही विधानसभा के चुनावी टिकट भी बांटेगा। इसीलिए समझदार नेता अभी से सूंघने में लग गए हैं कि आखिर किसकी गोटी लाल होने वाली है। इन नेताओं की मानें तो पार्टी में सियासत चलती रहती है। बड़ा परिवार है तो लड़ाई झगड़े होंगे ही। नेताओं के बीच मतभेद भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सबके बीच कोई एक ही नेता दिल्ली की कमान संभालेगा और वहीं विधानसभा के चुनाव में टिकटों को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। चूंकि हार-जीत की जवाबदेही सबसे ज्यादा उस पर होगी, लिहाजा सबसे ज्यादा हाईकमान उसकी ही सुनेगा भी, इसीलिए इस नेता की तलाश अभी से सरगर्मी से जारी है। फिलहाल पार्टी के तीनों कार्यकारी अध्यक्ष ही इसके खेवनहार हैं, लिहाजा बहुत सारे नेता इनकी परिक्रमा में भी जुटे हैं क्योंकि कुछ लोग अंदाजा यह भी लगा रहे हैं कि क्या पता इन्हीं में से किसी एक की किस्मत खुल जाए।

छपास का रोग

ऐसा कोई व्यक्ति, संगठन या एजंसी नहीं जिसे छपास का रोग न लगा हो। दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट भी इसी छपास रोग की शिकार हो रही है। कारण पीसीआर का मानवीय चेहरा अकस्मात दिखने लगा है। हर हफ्ते नहीं बल्कि कमोबेश हरेक दिन पीसीआर ऐसे मामले सुलझा रहे हैं जिनमें कभी बिछड़े बच्चे को उसके परिवार से मिलाया जा रहा है तो कभी किसी महिला या युवती को खुदकुशी करने से बचाया जा रहा है। लेकिन यह अकस्मात कैसे हो रहा है? इसका जबाब एक अधिकारी ने दबी जुबान से दिया। उनका कहना था कि यह और कुछ नहीं बल्कि छपास रोग है। जिस मानवीय चेहरे को प्रतिदिन पेश किया जा रहा है वह सालों से था, अंतर इतना ही है कि पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता था अब इसे बढ़ा-चढ़ाकर सार्वजनिक कर वाहवाही लूटी जा रही है। यह सिर्फ छपास रोग है और कुछ नहीं।

'दिल्ली में केजरीवाल'

लोकसभा चुनाव में सातों सीटों पर हुई करारी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में जमीन तैयार करनें में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने एक बार फिर 'दिल्ली में तो आप' या 'दिल्ली में तो केजरीवाल' के नाम से अपना चुनावी प्रचार शुरू किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इसी नारे को लेकर दिल्ली वालों से वोट मांगती नजर आएगी।

खामोशी और सुगबुगाहट

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन के बाद अब भाजपा में सुगबुगाहट है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की कड़ी परीक्षा होने वाली है। दरअसल पार्टी शीला दीक्षित की मौजूदगी में होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से अपनी सीटों के आंकड़े का गणित बैठाने में लगी थी। वर्तमान स्थिति में पार्टी को भी लग रहा है कि अगर सीधी टक्कर का मुकाबला होता है तो दिल्ली के समीकरण में बदलाव कर पाना उसके के लिए एक कड़ी चुनौती हो सकती है।

राजनीतिक चोट

चुनाव के पहले तक भाजपा के नेता एक दल और एक बल में नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली के चुनाव नजदीक आते हैं तो पार्टी की गुटबाजी आम आदमी को भी साफ नजर आने लग जाती है। इसका असर पार्टी के तीन शीर्ष नेताओं के जोर आजमाइश में भी इन दिनों नजर आ रहा है। पार्टी एक ही मुद्दे पर कई तरफ से चोट कर रही है, जिससे पार्टी की राजनीतिक टक्कर कमजोर पड़ती नजर आ रही है।

-बेदिल

अभिभावक शिक्षक बैठक में बताई गईं पॉक्सो कानून की बारीकियां

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

नगर निगम के स्कूलों में आयोजित मेगा पीटीएम (अभिभावक-शिक्षक बैठक) में विद्यार्थियों और अभिभावकों को पॉक्सो (बच्चों से जुड़े अपराध रोकने को बने कानून) के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही कल्याण योजनाओं, सीपीआर प्रशिक्षण, जल जनित रोगों और बच्चों के समग्र विकास और बच्चों को मानसिक रूप से प्रखर बनाने में अभिभावकों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। दक्षिणी निगम के रविवार को आयोजित इस पीटीएम में लगभग 78 प्रतिशत अभिभावक पहुंचे। इस दौरान मेयर, उपमेयर, स्थाई समिति के अध्यक्ष, शिक्षा समिति की अध्यक्ष, समिति के निदेशक और पार्षदों ने भी अलग-अलग स्कूलों में जाकर बैठक का जायजा लिया। मेयर सुनीता कांगड़ा ने मादीपुर वार्ड में स्थित 581 स्कूलों में पीटीएम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में सीखने के रवैये को उत्तम बनाया जा सकेगा।

अधूरी परियोजनाओं पर खरीदारों की चिंता

एनबीसीसी सुविधाएं दे या अधूरी परियोजनाएं पूरी कराए

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 28 जुलाई।

आम्रपाली मामले पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को अधूरी परियोजना पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस परियोजना से जुड़े फ्लैट खरीदारों को चिंता है कि एनबीसीसी पहले उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरी करे या फिर अधूरी परियोजना का काम पूरा कराए जिनका अभी तक कब्जा नहीं मिला है। शहर में आम्रपाली बिल्डर के करीब 10 हजार खरीदार हैं। ये ऐसे खरीदार हैं जिन्हें कब्जा तो मिला है लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रह रहे हैं।

आम्रपाली बिल्डर कंपनी की सेक्टर- 45, 76, 107, 119, 120 में आठ आवासीय परियोजनाएं हैं। बुनियादी सुविधाओं के आभाव में इन परियोजनाओं में करीब 10 हजार खरीदार रह रहे हैं। इन परियोजनाओं में लिफ्ट, अग्निशमन प्रबंधन, सीवर, पार्किंग समेत तमाम खामियां हैं। एनबीसीसी को जिम्मेदारी मिलने के बाद अब सवाल यह है कि वह पहले अधूरी परियोजनाओं का निर्माण करे या फिर उन परियोजनाओं में मूलभूत सुविधाओं को सुधारे। माना जा रहा है कि बिजली, पानी और सड़क निर्माण में नोएडा प्राधिकरण मदद करेगा। खरीदारों का तर्क है कि एनबीसीसी को पहले उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बिल्डर ने आवासीय परियोजना में 56 की जगह केवल 31 लिफ्ट स्थापित की हैं। भूमिगत पानी दिया जा रहा है। हालांकि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद प्राधिकरण ने सभी को पानी का कनेक्शन दिया है।

दो से तीन बिल्डर और फंसे तो डूबेंगे 10 हजार करोड़ रुपए

शीर्ष अदालत से आम्रपाली का फैसला आने के बाद इससे मिलते-जुलते अन्य मामलों के लिए फैसले को आधार बनाया गया तो प्राधिकरण के करीब 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की रकम डूब सकती है। इसमें दो से तीन बिल्डर फंसते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में यूनिटेक पर करीब सात हजार करोड़ रुपए और बिल्डर कंपनी थ्री सी पर प्राधिकरण का करीब 1256 करोड़ रुपए बकाया है। थ्री सी बिल्डर की सभी परियोजनाओं की हालत खस्ता है। करीब 800 करोड़ रुपए के बकाएदार एक अन्य बिल्डर कंपनी का भी मामला इसी दिशा में बढ़ रहा है।

हमें प्राधिकरण और एनबीसीसी से मतलब : नेफोमा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली ड्रीम वैली परियोजना पर फ्लैट खरीदरों के संगठन नेफोमा की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आगे की रणनीति तय करने के लिए चर्चा की गई। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स मैन एसोसिएशन (नेफोमा) अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि अब इस मामले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कोई सरोकार नहीं है। असल में कोर्ट की तरफ से नियुक्त रिसीवर ही हमारा प्राधिकरण है।

प्रियंका को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मुहिम तेज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के मद्देनजर अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद नेतृत्व को लेकर मझधार में फंसी पार्टी की कमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सौंपे जाने की आवाज बुलंद होने लगी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका को पार्टी अध्यक्ष बनाने की न केवल पुरजोर वकालत की है, बल्कि यह भी कहा है कि उनमें ही अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह मुश्किल वक्त में पार्टी को दोबारा सत्ता में ला खड़ा करने का दमखम है। इन नेताओं ने यह दलील भी दी है कि यदि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी में बिखराव होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

केंद्र सरकार के पूर्व मंत्रियों नटवर सिंह, भक्तचरण दास, श्रीप्रकाश जायसवाल, अनिल शास्त्री आदि नेताओं के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद शशि थरूर ने भी उम्मीद जताई है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रियंका जरूर हिस्सा लेंगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र व पश्चिम बंगाल की जांगीपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमाने वाले अभिजीत मुखर्जी भी पहले ही कह चुके हैं कि अपनी दादी की तरह ही प्रियंका गांधी में भी पार्टी को इस मुश्किल वक्त से उबारकर दोबारा सत्ता में ला खड़ा करने की क्षमता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह ने हाल ही में कहा कि राहुल गांधी के इस्तीफे के मद्देनजर पार्टी की कमान अब प्रियंका गांधी को सौंपी जानी चाहिए क्योंकि वह हर प्रकार से इसके योग्य हैं। उनका यह भी मानना है कि पार्टी को एकजुट रखने व बिखराव से बचाने के लिए गांधी परिवार के ही व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। एक अन्य नेता अनिल शास्त्री ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रियंका पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व हैं

● नटवर सिंह, भक्तचरण दास, श्रीप्रकाश जायसवाल और अनिल शास्त्री आदि खुलकर प्रियंका को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में
● शशि थरूर ने भी की प्रियंका के नाम की वकालत

और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को चाहिए कि वह उनको अपना नेता चुने।

इसी प्रकार श्रीप्रकाश जायसवाल ने भी कहा कि यही वह मौका है जब प्रियंका को पार्टी की बागडोर संभालने चाहिए क्योंकि वह इस पद के सर्वाधिक योग्य नेता हैं। ओड़ीशा से पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्तचरण दास ने भी यह मांग की कि देश के लाखों कार्यकर्ताओं की मांग के मद्देनजर प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालना चाहिए।

प्रियंका के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व केरल की तिरुवनंतपुरम संसदीय सीट से कांग्रेस सासंद थरूर ने भी एक इंटरव्यू में रविवार को कहा कि उनको उम्मीद है कि पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव होने पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें अपनी किस्मत आजमाने को लेकर फैसला करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास स्वाभाविक करिश्मा है जो निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं को प्रेरित और एकजुट कर सकता है। उनकी इसी खूबी के कारण कई लोग उनकी तुलना उनकी दादी और पूर्व पार्टी अध्यक्ष दिवंगत इंदिरा गांधी से करते हैं। वह निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं में नयी जान डालेंगी और साथ ही मतदाताओं को भी पार्टी की ओर खीचेंगी।

चुनावी हार के बाद बीते 25 मई की कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाले राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके बाद उनके परिवार का कोई और व्यक्ति भी यह पद नहीं संभालेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि दो महीने से अधिक का वक्त गुजर चुकने के बावजूद कांग्रेस राहुल का विकल्प नहीं ढूंढ़ पाई है।

इस बीच, सोनभद्र आदिवासी हत्याकांड मामले में प्रियंका गांधी के तीखे तेवर देख तमाम पार्टी नेताओं को उनसे उम्मीदें बंध गई हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका गांधी से मिलकर उनसे अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया भी था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अब कर्नाटक में कांग्रेस की गठबंधन सरकार के पतन और देश भर में कांग्रेस पार्टी में मची भगदड़ को देखते हुए यह देखना अहम है कि कांग्रेस कब तक इस महत्वपूर्ण मामले में निर्णय तक पहुंच पाती है।

बंगाल में बदमाश को पीट-पीटकर मार डाला ग्रामीणों ने

कल्याणी (पश्चिम बंगाल), 28 जुलाई (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पीट-पीटकर मार डाला और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह जानकारी पुलिस ने रविवार को दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना शनिवार रात में कल्याणी पुलिस थानाक्षेत्र के दोगच्चा क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि तीन बदमाशों ने कुछ स्थानीय युवकों पर हमला करके उनसे कीमती सामान लूटने का प्रयास किया। यह सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तीनों बदमाशों को घेर लिया और उन्हें पीटने लगे।

उन्होंने बताया कि उनमें से एक बदमाश भागने में सफल रहा जबकि दो अन्य की ग्रामीणों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।'

आनलाइन परीक्षा टेंडर की जानकारी आरटीआइ में नहीं मिल सकती : आयोग

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 28 जुलाई।

राजस्थान सूचना आयोग ने अपने महत्त्वपूर्ण फैसले में लोक सेवा आयोग की आनलाइन परीक्षा टेंडर की जानकारी को संवेदनशील और गोपनीयता के लिहाज से आरटीआइ के दायरे से बाहर माना है। आयोग ने इसकी जानकारी हासिल करने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए प्रतियोगी परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता को देखते हुए कहा कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सूचना आयोग ने राज्य लोक सेवा आयोग के खिलाफ दायर द्वितीय अपील को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। राज्य सूचना आयुक्त आसुतोष शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता लाने के साथ संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता को भी बनाए रखना है। इसलिए ऐसी सूचनाएं किसी सरकारी दफतर की सामान्य टेंडर की सूचनाएं नहीं मानी जा सकती है। सूचना आयोग में अजमेर निवासी तरूण अग्रवाल ने द्वितीय अपील के जरिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से आनलाइन परीक्षा टेंडर से जुडी जानकारियों को समस्त दस्तावेजों के साथ सूचनाएं चाही गई थी। लोक सेवा आयोग ने यह सूचनाएं देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अग्रवाल ने सूचना आयोग में अपील दायर कर सूचनाएं दिलाए जाने की गुहार लगाई थी। अग्रवाल का कहना था कि सरकारी कार्यालय में टेंडर की सूचनाएं देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके जवाब में लोक सेवा आयोग ने तर्क दिया था कि चाही गई सूचना आरटीआइ एक्ट की धारा 8 और अन्य उप धाराओं के तहत नहीं दी जा सकती है। ऐसी सूचनाएं देने से परीक्षा की गोपनीयता और विश्वसनीयता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त आसुतोष शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी कार्यालयों में टेंडर प्रक्रिया से जुडी सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती है। लोक सेवा आयोग से परीक्षाओं के टेंडर से जुडी जानकारियां सामान्य सरकारी दफतरों के टेंडर की सूचना नहीं है। यह ऐसी संवेदनशील सूचना है जो परीक्षा की गोपनीयता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने महिला को पीटा

सागर (मध्य प्रदेश), 28 जुलाई (भाषा)।

सागर शहर के कैंट पुलिस थाना क्षेत्र के भगवानगंज में शनिवार शाम को भीड़ ने मानसिक रूप से बीमार एक महिला (43) की बच्चा चोर होने के शक में कथित तौर पर पिटाई कर दी। कैंट पुलिस थाने के प्रभारी जेजे चौधरी ने रविवार को बताया कि पुलिस को शनिवार शाम को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने सागर रेलवे स्टेशन के पास भगवानगंज में एक महिला को बच्चा चुराने वाली समझ कर पकड़ लिया है व उसके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को अपनी सुरक्षा में लेकर थाने ले आई। चौधरी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि इस महिला का नाम मंजू है और वह मध्य प्रदेश के रतलाम शहर की शुभम कॉलोनी की रहने वाली है। उन्होंने कहा कि वह मानसिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ नहीं लग रही है। वह यह नहीं बता पा रही है कि किस परेशानी के चलते ट्रेन में सवार होकर यहां आई। चौधरी ने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मेघालय के विधानसभा अध्यक्ष रॉय का निधन

शिलांग/गुरुग्राम, 28 जुलाई (भाषा)।

मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष डॉनकूपर रॉय का गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में रविवार को निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वह 64 साल के थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रॉय को सबसे पहले शिलांग के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर पिछले 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा था।

किशोरी से सामूहिक बलात्कार, चार के खिलाफ मामला दर्ज

अलवर, 28 जुलाई (भाषा)।

राजस्थान में अलवर जिले के बडौदामेव थाना क्षेत्र में दो युवकों ने एक किशोरी के साथ बलात्कार किया और उसकी निर्वस्त्र फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने बताया कि किशोरी के परिजनों ने सामूहिक बलात्कार करने वाले दो व्यक्तियों सहित चार लोगों के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज करवाया।

थानाधिकारी दिनेश मीणा ने रविवार को बताया कि दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता के पड़ोस में रहने वाली एक महिला पिछले सप्ताह उसे बुलाकर अपने घर ले गई जहां पहले से मौजूद एक युवक ने उसके साथ बलात्कार किया। महिला के पति ने पीड़िता की निर्वस्त्र फोटो खींची और उसने भी उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद एक अन्य एक युवक पीड़िता से मिला और उसकी निर्वस्त्र फोटो उसके पास होने की बात कह कर उससे अकेले में मिलने को कहा। जब पीड़िता ने इस बात से इनकार किया तो उसने उसकी फोटो वाट्सऐप पर वायरल कर दी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी जद (एकी) में शामिल

पटना, 28 जुलाई (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई वाले जनता दल (एकी) की सदस्यता ग्रहण कर ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता रहे फातमी ने हालिया लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर राजद से नाता तोड़ लिया था।

जद (एकी) के स्थानीय मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह ने फातमी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सिंह ने फातमी का जद (एकी) परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि फातमी साहब के जुड़ने से पार्टी संगठन को दरभंगा के साथ ही पूरे बिहार में मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि फातमी साहब जिस दल से आए हैं उस दल के चंद नेताओं में शुमार थे, ऐसे में इनका उस दल को छोड़ जद (एकी) की सदस्यता लेना बड़ा फैसला है।

तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में जदयू के रुख के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि सदन में बहस के समय हम लोगों का जो रुख होगा उससे आप अवगत हो ही जाएंगे, पर इसको लेकर हमारा पहले जो रुख था, उस पर हम अभी भी कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे। लोकसभा में तीन तलाक बिल का विरोध करते हुए राजग में शामिल जद(एकी) सदन से वॉकआउट कर गई थी।

फातमी ने कहा कि जद(एकी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे न्याय के साथ विकास, खासकर बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए सरकार के जरिए जितनी भी जनोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ व हो रहा है, इससे पहले किसी भी पार्टी की सरकार के जरिए नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने समाज के पिछड़े वर्गों और अकलियतों, चाहे वो किसी भी तरह के अकलियत हों, के मुद्दे पर कभी कोई समझौता नहीं किया।

टिकटॉक पर वीडियो डालने के मामले में दो कांस्टेबल निलंबित

राजकोट, 28 जुलाई (भाषा)।

गुजरात के राजकोट में ड्यूटी के दौरान शूटिंग करने और सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक पर एक वीडियो डालने के मामले में दो पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि एक पूर्व यातायात वार्डन ने एक पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) वैन के बोनेट पर खड़े होकर पोज दिया जबकि एक कांस्टेबल गाड़ी चला रहा था और दूसरा पुलिसकर्मी वीडियो शूटिंग कर रहा था।

ए-संभाग पुलिस इंस्पेक्टर एनके जडेजा ने बताया, ड्यूटी के दौरान एक पीसीआर वैन का इस्तेमाल कर एक वीडियो रिकार्ड करने में संलिप्त पाए जाने के बाद ए-संभाग थाना के दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल की ओर से की गई जांच में पता चला है कि कॉन्स्टेबल अमित प्रागजी वैन चला रहा था और कांस्टेबल नीलेश पूनाभाई कुछ दूरी से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रागजी और पूनाभाई दोनों को निलंबित कर दिया गया है। जडेजा ने बताया, वीडियो करीब डेढ़ महीना पहले रामनाथ पारा पुलिस लाइन इलाके में शूट किया गया था।

बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़ों के लिए जारी

लुकआउट सर्कुलर के बारे में सूचना नहीं देगी सीबीआइ

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने सूचना के अधिकार कानून के तहत उन लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) की संख्या बताने से इनकार कर दिया है, जो उसने 2014 और 2019 के बीच बैंक और वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में आरोपियों को पकड़ने के लिए जारी किए हैं। सीबीआइ ने कहा कि इससे जारी जांच पर प्रभाव पड़ सकता है।

सूचना मांगने वाले एक आरटीआइ आवेदनकर्ता के अनुसार जांच एजंसी ने स्वयं द्वारा एलओसी जारी करने के बाद सक्षम प्राधिकारियों की ओर से प्राप्त आदेशों की जानकारी भी देने से इनकार कर दिया। सीबीआइ ने इसके लिए आरटीआइ कानून की धारा 8(1एच) का उल्लेख किया, जो ऐसी सूचना मुहैया कराने से उसे छूट प्रदान करता है जो किसी आरोपी की गिरफ्तारी या अभियोजन पर प्रतिकूल असर डाल सकती है।यह जवाब पुणे के आरटीआइ कार्यकर्ता विहार दुर्वे की ओर से सीबीआइ, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में आरटीआइ अर्जी दायर करने के बाद आया है। उक्त अर्जी के माध्यम से बैंक धोखाधड़ी के फरार आरोपियों के खिलाफ जांच के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। दुर्वे ने कहा कि एजंसी द्वारा अपने अधिकारियों द्वारा भगोड़ों को वापस लाने के लिए कानूनी और यात्रा सेवाओं पर किए गए खर्च के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।

मधुबनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U65100DL1991PTC045031
पंजीकृत कार्यालय : ग्रीन फील्ड्स फार्म, खसरा नं. 8/1-1 10-2 9/ 3-4-5-6, गादीपुर रोड, तहसील महरौली, नई दिल्ली-110084
ई-मेल gks@vsnl.com
प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (ग) के अनुसरण में]
सार्वजनिक सूचना
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कार्पोरेट मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, प. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5)(क) के विषय में
तथा
मधुबनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्रीन फील्ड्स फार्म, खसरा नं. 8/1-1 10-2 9/ 3-4-5-6, गादीपुर रोड, तहसील महरौली, नई दिल्ली-110084 में स्थित है के विषय में
......याचिकादाता
[illegible]
बोर्ड की समिति के आदेश द्वारा
वास्ते मधुबनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(देविंदर सिंह बराड़)
निदेशक (डीआईएन : 00068502)
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 24.07.2019

प्रारूप संख्या आईएनसी-25 क
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और
डिवस ई कॉमर्स लिमिटेड
(CIN U52590DL2015PLC282937)
जिसका पंजीकृत कार्यालय खसरा नं. 350, एम जी रोड, सुल्तानपुर, नई दिल्ली-110030 में स्थित है, के मामले में
......आवेदक
[illegible]
कृते
डिवस ई कॉमर्स लिमिटेड
अनुश्री झा
(निदेशक)
DIN:07331153
तिथि : 27.07.2019
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्र. का. 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008.
फोन-011-25782926
वेबसाइट : www.psbindia.com,
ईमेल: complianceofficer@psb.co.in
सूचना
सेबी (सूचीकरण दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मंडल की बैठक 07 अगस्त, 2019 को दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही (Q1) के बैंक के अलेखापरीक्षित, समीक्षित वित्तीय परिणामों को रिकॉर्ड में लेने के साथ-साथ उनको कलमबद्ध किया जायेगा।
(उक्त सूचना बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com/investors_information.php तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com/ एवं www.nseindia.com/ पर उपलब्ध है।)
दिनांक: 26 जुलाई, 2019
स्थान: नई दिल्ली
[विनय संडेलवाल]
कम्पनी सचिव

GLOBUS SPIRITS LIMITED
CIN: L74899DL1993PLC052177
REGISTERED OFFICE: F-0, GROUND FLOOR, THE MIRA CORPORATE SUITES, PLOT NO. 1 &2, ISHWAR NAGAR, MATHURA ROAD, NEW DELHI-110065
TEL : 011-66424600, FAX: 011-66424629 E mail: corpoffice@globusgroup.in, Website: www.globusspirits.com
Globus Spirits heritage of excellence
NOTICE
In terms of the Clause 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the next meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 3rd August, 2019, inter-alia (I), to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 1st Quarter ended on 30th June 2019 (II) to fix the date and venue for conducting the Annual General Meeting for the financial year 2018-19 & to fix the Book Closure date for the purpose of AGM, and (III) to consider the proposal for issuance of warrants convertable into equity shares on preferential basis to the promoter Groups/entities of the company subject to the approval of share holders.
The said notice is also available on the company's website www.globussprints.com and also available on BSE & NSE website.
For Globus Spirits Limited
Sd/-
Santosh Kumar Pattanayak
(Company Secretary)
Dated: 27th July, 2019

एनटीपीसी NTPC एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन: L40101DL1975GOI007966
पंजीकृत कार्यालय : एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24360959, फैक्स: 011-24360241
ई-मेल: csntpc@ntpc.co.in, वेबसाइट: www.ntpc.co.in
43वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोज़र और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना
1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) बुधवार, 21 अगस्त, 2019 को प्रातः 10.30 बजे मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, नई दिल्ली-110010 में होगी जिसका उद्देश्य इसकी सूचना (दिनांक 18 जुलाई, 2019 के परिशिष्ट के साथ पढ़ें) में उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करना है। कम्पनी के शेयरधारकों के पंजीकृत पते / ई-मेल पते पर 43वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ ए.जी.एम. की सूचना, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, अंकेक्षक की रिपोर्ट और निदेशक की रिपोर्ट भेज दी गई है। 43वीं एजीएम की सूचना और इसके परिशिष्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
2. एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अंतर्गत एवं के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजी और शेयर ट्रांसफर बुक 15 अगस्त, 2019 से 21 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी। यदि वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार इक्विटी शेयरों पर अंतिम रूप से लाभांश की घोषणा होती है तो वास्तविक रूप से शेयर रखने वाले उन सदस्यों को जिनके नाम 21 अगस्त, 2019 को कम्पनी की पंजी में होंगे और डीमैट शेयर के मामले में शेयर के उन लाभार्थी स्वामी, जिनके नाम नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए लाभार्थी स्वामित्व के विवरण में 14 अगस्त, 2019 को कारोबार समय बन्द होने तक दर्ज होंगे, को 3 सितम्बर, 2019 को भुगतान किया जाएगा।
3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर संशोधित और सेबी (सूचीकरण दायित्व और आवश्यक उद्घोषणा) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कम्पनी सहर्ष अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दे रही है ताकि वे एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से 8 जुलाई, 2019 दिनांकित एजीएम सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकें।
4. रिमोट ई-वोटिंग रविवार 18 अगस्त, 2019 भारतीय समयानुसार प्रातः 9.00 बजे आरंभ और मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 भारतीय समयानुसार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल मतदान के ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर देगी। किसी प्रस्ताव पर मतदान कर देने के बाद सदस्य इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। रिमोट ई-वोटिंग के बारे में विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।
5. रिमोट ई-वोटिंग से मतदान / ए.जी.एम. में मतदान की सुविधा केवल उसे होगी जिसका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् 14 अगस्त, 2019 को सदस्यों की पंजी या डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध लाभार्थी स्वामियों की पंजी में होगा।
6. एजीएम की सूचना भेजने के बाद परंतु कट ऑफ तिथि या उससे पहले कम्पनी के सदस्य बनने वाले अंशधारक evoting@nsdl.co.in पर आवेदन भेजकर अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल में पंजीकृत सदस्य वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ मतदान कर सकते हैं।
7. रिमोट ई-वोटिंग से मतदान कर चुके सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं, पर दोबारा मतदान नहीं कर सकते। सदस्यगण ये ध्यान रखें कि ए.जी.एम. में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी।
8. पारदर्शिता और ईमानदारी से मतदान और रिमोट ई-वोटिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने मैसर्स ए. कौशल एंड एसोसिएट्स के श्री अमित कौशल, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव को स्क्रूटनाइजर नियुक्त किया है।
9. सदस्यों से आग्रह है कि ए.जी.एम. सूचना में प्रकाशित रिमोट ई-वोटिंग संबंधी निर्देश सावधानी से पढ़ लें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे (प्रबंधक), एनएसडीएल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, ई-मेल: evoting@nsdl.co.in, फोन: 1800 222 990/91 22 24994200/91 22 24994545 से संपर्क करें।
10. अब तक ई-मेल नहीं रजिस्टर कराने वाले सदस्य या ई-मेल अपडेट करने के इच्छुक सदस्य पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग के उद्देश्य से कृपया अपने संबंधित डीपी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग हेतु) या अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड / कम्पनी (वास्तविक रूप से होल्डिंग हेतु) से संपर्क करें ताकि सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिल सकें।
कृते एनटीपीसी / लिमिटेड
हस्ता./-
(नंदिनी सरकार)
कंपनी सचिव
दिनांक : 26 जुलाई, 2019
स्थान : नई दिल्ली
विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}
संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	जोत इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	9 जनवरी, 1998
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय-आरओसी-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U18101DL1998PLC091759
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत पताः 1/204, भूतल, सदर बाजार, दिल्ली कैन्ट, नई दिल्ली-110010, भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	14 मई, 2019- आदेश की तिथि, 16 मई, 2019- आईआरपी के रूप में नियुक्ति के निर्णय की सूचना देते हुए माननीय एनसीएलटी से ईमेल प्राप्त की गई। 21 मई, 2019-आदेश की प्रति की प्राप्ति।
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	29 जुलाई, 2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	http://www.llcairp.com/
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	http://www.llcairp.com/
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	19 अगस्त, 2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	29 अगस्त, 2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	3 सितम्बर, 2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	13 सितम्बर, 2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	03 सितम्बर, 2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	संहिता की धारा 29(2) के अनुसार गोपनीयता का अंडरटैकिंग प्राप्त करने के बाद क्रेडीटरों की समिति द्वारा निर्दिष्ट तथा दिवाला एवं दिवालिया संहिता (संहिता) की धारा 29(2) के अनुसार योग्यता मानदंड पूरा करने वाले संभावित प्रस्ताव आवेदकों को रिजोल्यूशन प्लान जमा करने के लिये सूचना मेमोरैण्डम, प्रॉसेस नोट, मूल्यांकन मैट्रिक तथा रिजोल्यूशन प्लान के लिये अनुरोध रिजोल्यूशन प्रॉफेशनल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति/भौतिक पद्धत्ति में उपलब्ध कराई जायेगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	7 अक्टूबर, 2019
17.	प्रस्ताव कर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	पत्राचार के पते पर रिजोल्यूशन प्रॉफेशनल के पास मुहरबंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट द्वारा/हाथों-हाथ तथा उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति jipl.irp@llca.net पर ईमेल द्वारा।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	29 अक्टूबर, 2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	अखिलेश कुमार गुप्ता IBBI/IPA-001/IP-P00780/2017-18/11353
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	अखिलेश कुमार गुप्ता एलजीएफ, ए-16/4, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057, ई-मेलः Akhilesh@llca.net
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	अखिलेश कुमार गुप्ता, लूथरा एंड लूथरा रीस्ट्रक्चरिंग एंड इन्सॉल्वेन्सी एडवायजरी एलएलपी, एलजीएफ, ए-16/9, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057, ई-मेल आईडीः jipl.irp@llca.net
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	http://www.llcairp.com/
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	29 जुलाई, 2019

(अखिलेश कुमार गुप्ता), रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल
पंजीकरण संख्या- IBBI/IPA-001/IP-P00780/2017-18/11353
पंजीकृत पताः एलजीएफ, ए-16/4, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
जोत इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट ऋणधारक) के लिये
तिथिः 29 जुलाई, 2019
स्थानः दिल्ली

LUMAX ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड DK JAIN GROUP
पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरवंश भवन-II, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046
वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxindustries, दूरभाष 011-49857832
ईमेल : lumaxshare@lumaxmail.com, सीआईएन : L74899DL1981PLC012804
सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 38वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 को 10.30 पूर्वा. में एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी जिसमें कम्पनी के शेयरधारकों को भेजी गई सूचना में वर्णित व्यवसायों (साधारण तथा विशेष) को निष्पादित किया जाएगा।
एजीएम की सूचना सहित वित्त वर्ष 2018-19 के लिये कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट उनके पंजीकृत पते पर शेयरधारकों को प्रेषित कर दी गई है तथा ऐसे सभी शेयरधारकों को ईमेल कर दी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं।
कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxindustries.com पर भी उपलब्ध है तथा एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यावसायिक मदों से संबंधित दस्तावेज सभी कार्य दिवसों को (शनिवार छोड़कर) व्यावसायिक अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा सोमवार, 19 अगस्त, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू हो गई तथा गुरुवार, 22 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में शुरू होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ सभा में मत-पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।
यदि कोई व्यक्ति सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 16 अगस्त, 2019 को शेयर धारित करते हैं, वे ई-मेल आईडी einward.iris@karvy.com पर कार्वी को अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख ई-वोटिंग निर्देशों में किया गया है जो कम्पनी तथा कार्वी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए कार्वी में पहले से पंजीकृत हैं, तो रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
जिन सदस्यों ने रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों, वे सभा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, उनके लिए सभा में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत लागू होने वाले नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 17 अगस्त, 2019 से शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक इक्विटी शेयर लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए बंद रहेंगे।
ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नों/समस्याओं के लिए शेयरधारक https://evoting.karvy.com के "Downloads" खंड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा निम्नलिखित से संपर्क करें:
क) सुश्री अंकिता गुप्ता, प्लॉट नं. 878, उद्योग विहार, फेज-V, गुरुग्राम-122016 अथवा ankita.gupta@lumaxmail.com
ख) मै. कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर-बी, प्लॉट 31-32, गाछीबाउली फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, टेली.: 040-67162222 अथवा टोल फ्री नं. 1800-3454-001
ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
अंकिता गुप्ता
कंपनी सचिव
स्थानः गुरुग्राम
तिथिः 27.07.2019

सुरक्षा पर सियासत

कश्मीर में एक बार फिर वहां के सियासी दल केंद्र के खिलाफ भड़काऊ बयान देने लगे हैं। मामला यह है कि केंद्र ने दस हजार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू कर दी है और बाद में दस हजार और सैनिक भेजे जाने की बात कही है। इसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कान्फ्रेंस ने अनुच्छेद 35-ए हटाने की तैयारी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया है। पीडीपी की नेता और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले पर यहां तक कह दिया कि अगर कोई अनुच्छेद 35-ए को हाथ लगाएगा, तो भस्म हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला भी इसे सियासी रंग दे रहे हैं। इस तरह दोनों दल वहां के लोगों में भ्रम फैलाने और उन्हें उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि पिछले हफ्ते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कश्मीर दौरे से लौटने के बाद उनकी सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सैनिक कंपनियां भेजने का फैसला किया। वहां आतंकवाद निरोधक ग्रिड काफी समय से अतिरिक्त सैनिकों की मांग कर रहा था। फिर खुफिया सूत्रों से आने वाले दिनों में सीमा पार से हमले की सूचना भी थी। ऐसे में सुरक्षा कारणों से घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला करना पड़ा।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की समस्या कोई छिपी बात नहीं है। उससे निपटना केंद्र के लिए खासी चुनौती बनी हुई है। तमाम कड़े कदम उठाने और निरंतर तलाशी अभियान चलाने के बावजूद आतंकियों पर नकेल कसना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण वहां चुनाव कराने में भी देरी हो रही है। जब तक घाटी में शांति बहाली नहीं होगी, चुनाव कराना टेढ़ा काम होगा। इसलिए अगर सरकार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर स्थिति को काबू में लाना चाहती है, तो वहां के सियासी दलों से इसमें सहयोग की अपेक्षा की जाती है, न कि उसमें बाधा डालने की। कश्मीर का मसला सियासी जरूर है, पर आतंकवाद को मदद कहां से मिल रही है और उसका मकसद क्या है, यह न तो उमर अब्दुल्ला से छिपा है और न महबूबा मुफ्ती से। आतंकी संगठनों के प्रति नरम रवैया अपनाने की वजह से ही इन दोनों की सरकारें घाटी में अमन का माहौल बनाने में विफल रही हैं। इससे वहां के अलगाववादी संगठनों को भी शह मिलती रही है। इस तरह वहां के आम लोगों की रोजी-रोटी और युवाओं के रोजगार की संभावनाएं भी सिकुड़ती गई हैं। आखिर दहशतगर्दी को कोई भी दल या व्यक्ति कैसे सहन कर सकता है।

कश्मीर समस्या का समाधान वर्तमान केंद्र सरकार के लिए बड़ा मसला है। भाजपा अपने चुनावी वादों में बहुत पहले से इस समस्या के समाधान की बात कहती रही है। पिछले पांच साल की सरकार में इस दिशा में कोई उल्लेखनीय नतीजा नहीं निकला। इसलिए इस बार वह उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो यह स्वाभाविक है। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तो भ्रम फैलाता ही रहता है, इस पर घाटी के लोगों को भी गुमराह करता रहा है। इसी का नतीजा है कि सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को संचालित किया जाता रहा है। उस पर नकेल कसना सेना के जरिए ही संभव दिखता है। इसलिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। मगर शायद वहां के सियासी दलों को डर है कि विधानसभा के चुनाव हुए, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। इसलिए भी वे इसे सियासी रंग दे रहे हैं।

भीड़तंत्र और सवाल

देश में उन्मादी भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राज्यों से यह पूछा है कि इसे रोकने के लिए पिछले साल दिए गए निर्देशों पर अमल की क्या स्थिति है। बेकाबू होती भीड़ हिंसा वाकई बहुत गंभीर मसला है, जिस पर शीर्ष अदालत ने राज्यों से जवाब तलब कर पूरे देश की चिंता को ही जाहिर किया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और ग्यारह राज्यों को नोटिस जारी किए हैं। देश में बढ़ती इस तरह की हिंसा को लेकर शीर्ष अदालत काफी सख्त है और पिछले सवा साल में सरकारों को कसा है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी राज्य ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए कोई कदम उठाया हो या कोई कठोर कानून बनाया हो, ऐसा देखने में नहीं आया। सरकारों का यह हाल तो तब है जब देश की सर्वोच्च अदालत सक्रिय है और बार-बार नोटिस जारी कर रही है, दिशानिर्देश जारी कर रही है और अपने निर्देशों पर अमल के बारे में पूछ रही है। इससे क्या यह बात प्रमाणित नहीं होती कि सरकारें चाहे राज्यों की हों या केंद्र की, शीर्ष अदालत की बात को कोई तवज्जो नहीं दे रही हैं?

ऐसा नहीं है कि भीड़ की हिंसा को रोका नहीं जा सकता। लेकिन केंद्र और राज्यों का इस मामले में अब तक का रवैया बहुत ही निराशाजनक रहा है। लगता है, ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा। वरना क्या यह संभव है कि पुलिस प्रशासन चाहे और ऐसी घटनाएं न रुकें! सवाल तो यह है कि उन्मादियों की हिंसा से बचाव के लिए सरकारों ने कौनसे उल्लेखनीय कदम उठाए जिनसे ऐसे बर्बर कृत्यों को अंजाम देने वालों के भीतर भय पैदा होता। सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल जो निर्देश दिए थे, वे अपने में पर्याप्त हैं और अगर इन पर अमल होता तो निश्चित रूप से भीड़ तंत्र के न्याय पर लगाम लगती। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने, खुफिया सूचनाएं जुटाने के लिए विशेष कार्यबल का गठन करने, पुलिस तंत्र को दुरुस्त करने, गश्ती बढ़ाने जैसे कदम उठाने को कहा था। इसके अलावा भीड़ हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाने को कहा गया था। लेकिन जिस तेजी से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उससे लगता है कि सरकारों ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि ऐसी घटनाओं को सामान्य अपराध ही मान कर कार्रवाई की जा रही है। शीर्ष अदालत का स्पष्ट निर्देश है कि भीड़ की हिंसा को सामान्य अपराधों से अलग रखा जाए।

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से भीड़ हिंसा के खिलाफ कानून बनाने को कहा था। लेकिन इस दिशा में अब तक कुछ नहीं हुआ। राज्यों ने तो कोई कानून बनाया ही नहीं, केंद्र ने भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की। केंद्र का रवैया तो डांवाडोल स्थिति वाला रहा है। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने यह कह दिया था कि भीड़ की हिंसा से निपटने के लिए वह कोई कानून नहीं बनाएगी, क्योंकि राज्यों के पास पर्याप्त शक्तियां और अधिकार हैं, वही इससे निपटने के उपाय करें और कानून बनाएं। लेकिन बाद में इस तरह की खबरें भी आईं कि भीड़ हिंसा से निपटने के लिए केंद्र जल्द ही ऐसा कानून बनाएगा। जब सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से कानून बनाने को कहा है तो कानून बनना चाहिए। सवाल है जब संवेदनशील मामलों में भी सरकारें सर्वोच्च अदालत के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेंगी तो समस्या से कैसे निजात मिलेगी!

कल्पमेधा

बुद्धिजीवियों का व्यक्तिवाद अनिवार्यतः उनमें एक ऐसा मानसिक रोग पैदा कर देता है, जो उन्माद का निकट संबंधी है।
–मैक्सिम गोर्की

बाढ़ और सूखे की दुविधा

सुविज्ञा जैन

जल प्रबंधन की परियोजनाएं बनना और लागू होना कोई एक-दो महीने का काम नहीं होता, बल्कि इसके लिए चार-छह साल का वक्त लगता है। फिलहाल कुछ कर सकते हैं तो बस इतना कि बाढ़ और सूखे के बाद राहत और दूसरे काम की तैयारियां अभी से करके रख लें। लेकिन उससे बड़ा काम यह होना चाहिए कि देश में जल संभरण या संचयन की बड़ी योजनाओं पर सोचना शुरू कर दें। खासतौर पर वैसी जल योजनाएं जो थोक में पानी को रोक कर सकती हों।

देश में मुख्य मानसून के चार महीने ही होते हैं। दो महीने गुजरने को हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि अब तक औसत से सत्रह फीसद पानी कम गिरा है। यानी इस साल सूखे का अंदेशा और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि अभी पूरा मानसून गुजरा नहीं है। दो महीने और बचे हैं। हो सकता है कि ताबड़तोड़ बारिश हो जाए और इस साल पूरे मानसून में सामान्य बारिश का सरकारी अनुमान सही भी साबित हो जाए। लेकिन दो महीने में अगर औसत से सवा गुनी बारिश हो गई तो देश में कई जगह भयावह बाढ़ का खतरा खड़ा हो जाएगा। देश में इस समय तक जो हालात बने हैं, उनसे भयानक बाढ़ या भीषण सूखे के आसार बराबर के बन गए हैं। ऐसे हालात को प्रबंधन प्रौद्योगिकी के लिहाज से भी देखा जाना चाहिए।

बीस दिन पहले तक देश के कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बन रहे थे। जून के महीने में बारिश औसत से तैंतीस फीसद कम हुई थी। पिछले महीने मीडिया में सूखे तालाबों में गड्ढे खोद कर पानी ढूंढ़ने और टैंकरों से पानी लेने के लिए लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें छप रही थीं। उसके बाद जुलाई में पांच-सात दिन कुछ ज्यादा बारिश हो गई और देश में कई जगह बाढ़ के हालात बन गए। हैरत इस बात पर होनी चाहिए कि जुलाई के चौथे हफ्ते तक देश में कुल बारिश औसत से सत्रह फीसद कम हुई है, इसके बावजूद कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में हैं। यानी इस साल के मानसून की बेतरतीब चाल ने इस दुविधा में डाल दिया है कि हम बाढ़ से ज्यादा चिंतित हों या सूखे से? या इस बार बाढ़ और सूखा दोनों ही संकटों से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? एक ही साल में बाढ़ और सूखे की स्थिति को मानसून की गड़बड़ी की बजाय जल प्रबंधन के नजरिए से देखे जाने की दरकार है।

जल विज्ञानी और जल प्रबंधक कई साल से बार-बार बताते आ रहे हैं कि देश में पानी की समस्या का समाधान बारिश से मिले खरबों घनमीटर पानी को रोक कर रखने से ही संभव है। यही एकमात्र उपाय है जो बाढ़ और सूखे से निजात दिला सकता है। इसीलिए इस साल बांध और जलाशयों में पानी रोक कर रखने की मौजूदा स्थिति पर नजर डालनी जरूरी है। देश के बांधों और जलाशयों पर हफ्ते दर हफ्ते निगरानी रखने वाले केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) के मुताबिक इस समय तक देश के सभी मुख्य बांधों में सिर्फ दो सौ सत्तावन अरब घनमीटर पानी रोक कर रखने की व्यवस्था है। गौरतलब है कि देश की धरती पर बरसे कुल पानी में हर साल हमें औसतन एक हजार आठ सौ अरब घनमीटर पानी उपलब्ध होता है। बाकी पानी नदियों को उफनाता और बाढ़ की तबाही मचाता समुद्र में वापस चला जाता है।

यही नहीं, अपने बांधों की दो सौ सत्तावन अरब घनमीटर क्षमता भी कहने को ही है, क्योंकि मानसून के बाद इस्तेमाल के लिए इन बांधों की पानी जमा करने की क्षमता (लाइव स्टोरेज) सिर्फ एक सौ इकसठ अरब घनमीटर ही है। बाकी छियानवे अरब घनमीटर पानी वह है जिसे जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह डेड स्टोरेज कहलाता है। कई कारणों से इस पानी को निकालने की मनाही होती है। डेड स्टोरेज इसलिए बनाया जाता है ताकि भूजल रिचार्ज होता रहे और उस इलाके का पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। डेड स्टोरेज पानी के साथ बह कर आने वाली मिट्टी के कारण बांध को जल्दी बेकार हो जाने से भी रोकते हैं।

जल आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक सौ इकसठ अरब घनमीटर संभरण क्षमता वाले बांधों में जुलाई के आखिरी हफ्ते तक सिर्फ चालीस अरब घनमीटर पानी भरा जा सका है। पिछले साल इस समय तक यह आंकड़ा पैंसठ अरब घनमीटर का था। उस हिसाब से इस साल अब तक जल भंडारण पिछले साल से अड़तीस फीसद कम हुआ है। यहां इस बात पर गौर होना चाहिए कि पिछले साल सामान्य से छह फीसद ही कम बारिश हुई थी, मगर देश का लगभग आधा हिस्सा सूखे की चपेट में आ गया था। इसका एक मतलब यह निकलता है कि इस साल के हालात पिछले साल से ज्यादा गंभीर हैं। हालांकि ये अलग बात है कि देश का मौसम विभाग अभी भी पूरे मानसून में औसतन सामान्य वर्षा की उम्मीद में है। लेकिन यह हिसाब अभी नहीं लगा है कि अगर मानसून के बाकी बचे समय में औसत से बीस फीसद ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ से तबाही का आकार कितना बड़ा होगा। और अगर सामान्य से ज्यादा बारिश न हुई तो सूखा पड़ना लगभग तय है। बेशक यह ऐसी आफत है जिसका फौरन ही कोई हल नहीं निकाला जा सकता। जल प्रबंधन की परियोजनाएं बनना और लागू होना कोई एक-दो महीने का काम नहीं होता, बल्कि इसके लिए चार-छह साल का वक्त लगता है। फिलहाल कुछ कर सकते हैं तो बस इतना कि बाढ़ और सूखे के बाद राहत और दूसरे काम की तैयारियां अभी से करके रख लें। लेकिन उससे बड़ा काम यह होना चाहिए कि देश में जल संभरण या संचयन की बड़ी योजनाओं पर सोचना शुरू कर दें। खासतौर पर वैसी जल योजनाएं जो थोक में पानी को रोक कर सकती हों।

कुदरती आपदाओं से कम से कम नुकसान हो, इसकी कोशिशें अभी से होनी चाहिए। और अगर बाढ़ और सूखे से बचाव करना है तो बारिश के पानी को नदियां उफनाते हुए, बाढ़ की तबाही मचाते हुए वापस समुद्र में जाने से रोकने के लिए नए बांध और जलाशय बनाने पर सोचना ही पड़ेगा। वैसे इस काम के लिए भी हमने अपने लिए बहुत से व्यवधान खड़े कर रखे हैं। इससे अलग एक मसला यह भी है कि जो बांध, झीलें, तालाब आदि देश में मौजूद हैं उनमें से कई अपनी क्षमता के मुताबिक पूरे भर नहीं पा रहे हैं। ये बांध और तालाब क्यों नहीं भर पाते हैं, कम से कम इसके कारणों को खत्म करने के काम पर फौरन ही लगा जा सकता है। मसलन जिस भी बांध, जलाशय या दूसरे जल निकाय के जल ग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में गड़बड़ियां पैदा कर दी गई हैं, उन्हें फौरन सुधारा जाए। जल ग्रहण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां बरसा पानी किसी जल निकाय में जाकर जमा होता है। लेकिन कई जगह ऐसी सड़कें या रिहाइशी इमारतें बन गई हैं कि जलाशय तक पानी जाने के रास्ते ही बंद हो गए हैं। यही कारण है कि अच्छी बारिश के बावजूद कई बांध, तालाब और कुंड भर ही नहीं पाते और इसी कारण शहरी इलाकों में जलभराव और बाढ़ की समस्या बढ़ गई है। इसी वजह से जमीन के भीतर भी पानी नहीं पहुंच पाता। जल विज्ञान के विशेषज्ञ इसके समाधान के लिए 'जलग्रहण क्षेत्र उपचार' (कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट) नाम का उपाय सुझाते हैं। हाल फिलहाल अगर और कुछ न हो सकता हो तो सरकार कम से कम ऐसे उपायों पर विचार-विमर्श तो शुरू करवा ही सकती है।

इस बात पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है कि जल संचयन की परियोजनाएं बहुत खर्चीली हैं। बांधों-तालाबों से गाद निकालने का काम भी खर्चीला है। जलग्रहण क्षेत्र उपचार का काम भी भारी-भरकम है। साल दर साल बाढ़ और सूखे के कारण देश की आर्थिक वृद्धि दर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए जल संचयन पर ज्यादा खर्च करना भी मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है।

बिसरता परिवेश

अशोक कुमार

दुनिया मेरे आगे

मेरे एक मित्र का आठ साल का बेटा उनसे पूछ रहा था- 'पापा कुआं कैसा होता है? हमें दिखा दीजिए।' मेरे मित्र ने उसे दिखाने का आश्वासन देकर उस वक्त तो उसे बहला दिया, लेकिन मुझसे कहने लगा कि ऐसे ही नई-नई बातों से परेशान करता रहता है। मैंने उसे कहा कि दरअसल वह तुम्हें परेशान नहीं करता, यह उसके भीतर का कौतूहल है। वह नई चीजों के बारे में जानना चाहता है। हममें से कई लोग हैं जो अपने आसपास की चीजों को नजदीक से जानना चाहते हैं, लेकिन कई इसे सामान्य ढंग से ही लेते हैं। मित्र के साथ कुछ देर की बातचीत के बाद मैं अपने घर आ गया। लेकिन बच्चे के कुएं के बारे में नहीं जानने को लेकर मन उद्विग्न था कि ऐसा किन वजहों से हुआ होगा।

किसी को यह हास्यास्पद लग सकता है कि बच्चे कुआं के बारे में नहीं जान रहे हैं! जाने भी कैसे? हम अपने आसपास के जल-स्रोतों को खत्म कर रहे हैं। पानी निकालने के नई तकनीक का ईजाद कर रहे हैं। बिना यह सोचे समझे कि इससे पानी का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो रहा है या हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में ही यह सवाल दिमाग उभरता है कि हम हर अगले रोज अपना परिवेश को भूलते तो नहीं जा रहे! जो कल तक हमारे लिए अति महत्त्वपूर्ण थे, जिन पर हमारा जीवन निर्भर था, आज उसके बारे में हमारे बच्चे ही नहीं जान रहे हैं। भावी पीढ़ियों की क्या हालत होगी, यह सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं।

हम बच्चों की किताबों में कई शब्द पढ़ते हैं। हल, बैल, तालाब, घर की चक्की आदि। एक समय था जब हमारी पूरी खेती का आधार ही हल और बैल था। लेकिन बदलते समय और तकनीक ने हल और बैल को सदियों पुरानी पद्धति बना दिया। पहले गांव से शहरों तक तालाब जल संरक्षण का महत्त्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था। लेकिन आज तालाबों और पोखरों को भर कर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी गई हैं। इन बहुमंजिला इमारतों को देख कर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कभी यहां बहुत बड़े तालाब भी रहे होंगे, जिसमें हजारों लीटर पानी सालों भर रहते होंगे।

इसके अलावा, घर की चक्की का तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। अमूमन सभी घरों के कोने में यह चक्की पड़ी रहती थी। हमारी दादी और नानी इसी चक्की में गेहूं, चावल आदि पीस कर उसके आटा से भोजन तैयार करती थीं। आमतौर पर योग स्थल पर इस विषय पर योग शिक्षक बताते हैं कि चक्की चलाने और मोटा दाना के भोजन से हमारे पहले की पीढ़ियां या बुजुर्ग कितने स्वस्थ रहते थे। कई लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं कि विज्ञान के इतने विकास करने के बाद भी हम उन्हीं पुरानी पद्धतियों को क्यों ढोएं! मैं यह नहीं कहता कि आज जब सभी क्षेत्रों में इतनी तरक्की हुई है, तब भी पुराने ढर्रे पर काम होता रहे।

मेरा मानना है कि इन चीजों को सहेजने की जरूरत है कि आने वाली पीढ़ियां इन संसाधनों के बारे में भी जानें। वह यह भी जानने का प्रयास करें कि जब लोगों के पास संसाधनों का घोर अभाव था, तब वे कैसे और किन-किन संसाधनों का उपयोग कर अपने को जीवित रखते थे। लेकिन सिमटते संसार ने लोगों के पास वक्त ही नहीं रहने दिया इन सब पर सोचने के लिए। विकास के दौर में वे तेज रफ्तार से भागे जा रहे हैं। आज जब उनके बच्चे उन्हीं के पूर्वजों के उपयोग के साधनों पर सवाल पूछते हैं तो वे झल्ला उठते हैं। वे उनके प्रश्नों को टालने का प्रयास करते हैं।

आज के बच्चे भी प्रकृति से प्रेम न करके टीवी और मोबाइल की दुनिया को ही सच मान लेते हैं। उनसे अलग किसी दुनिया का उन्हें आभास ही नहीं। अक्सर सुनने को मिलता है कि शहर के बच्चे तारे को नहीं जान पाए। यह हास्यास्पद, लेकिन गंभीर प्रश्न है कि रोज रात को टिमटिमाने वाले तारों को हम नहीं देख पा रहे हैं। उसके विषय में जितना कुछ किताबों में पढ़ा है, उससे अधिक कुछ न देख पाते हैं और न कुछ सोच पाते हैं। नए जमाने के उपकरण के तौर पर स्मार्ट फोन ने तो लोगों को और अधिक आभासी दुनिया में धकेल दिया है। हमारे पास एक मिनट भी कुछ और स्वतंत्र तरीके से सोचने के नहीं बच पा रहा है। हम नए उपकरणों के दौर में पुराने साधनों को भूलते जा रहे हैं। हम न केवल पुराने औजारों को, बल्कि अपने परिवेश को ही भूल रहे हैं। पुरानी पद्धतियों को भूल रहे हैं। मानव जीवन के विकास के क्रम में पुराने संसाधनों का भी महत्त्व है। हम अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों के साधनों के बारे में बताएं तो जरूर वे इसे सहेज कर उसमें नवीनता का रंग भर सकेंगे।

आतंकवाद पर लगाम

आतंकवाद भारत ही नहीं अपितु विश्व की गंभीर समस्याओं में से एक है। भौगोलिक सीमाओं से परे आतंकवाद हर जगह अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। अमेरिका, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि कई देश आतंकवाद की मार झेल रहे हैं। आतंकवाद दरअसल वैश्विक राजनीति में दबदबा बनाए रखने वाले कुछ देशों का एक तरह का अभियान ही है। इसी से उनके स्वार्थ और हित पूरे होते हैं। इसीलिए आतंकवादी संगठनों को कई देशों का समर्थन हासिल होता है। ऐसे देश मानव सभ्यता के लिए खतरा हैं।

भारत सरकार ने आतंकवाद के मुद्दे पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने का दावा किया है। सरकार जिस प्रकार से संसद सत्र में आतंकवाद से जुड़े विधेयक पेश कर रही है, उससे साफ है कि सरकार आतंकवाद को लेकर गंभीर है। लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) एक्ट संशोधन, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2019 तो पास हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन संशोधन से सरकार अपनी कथनी को करनी के रूप में पेश करना चाह रही है। आतंकवाद से लड़ना एक चुनौती है जिसे संपूर्ण विश्व को स्वीकार करना होगा, ताकि इस गंभीर समस्या से जल्द से जल्द निजात पा जा सके।

● मुकुल सिंह चौहान, दिल्ली

इमरान से उम्मीद

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिका में दिए हालिया बयान को दो परिप्रेक्ष्यों में देखा जा सकता है। इमरान खान ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान में चालीस हजार से ज्यादा आतंकवादी हैं। इमरान खान ने यह बयान बहुत ही सोच-समझ कर दिया लगता है। पहला तो यह कि पाकिस्तान इस समय बेहद ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे आर्थिक संकट से उबरने के लिए उसे अमेरिका सहित अन्य देशों से आर्थिक सहयोग की बेहद आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इमरान खान ने अमेरिका में ऐसा बयान दिया है। यह कहीं न कहीं सत्य भी है। इमरान खान के इस बयान के बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि शायद पाकिस्तान अपने यहां चल रहे आतंकी संगठनों पर नकेल कसे अपनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही इमरान खान विकास और शांति की बात करते आ रहे हैं। इसलिए उनके इस बयान के बाद उम्मीद और जगी है कि वे पाकिस्तान की सरजमीं से आतंकियों का सफाया कर एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। मगर पाकिस्तान से यह उम्मीद कम ही की जानी चाहिए कि वह अपने इस रुख पर ज्यादा समय तक कायम रह पाएगा। अगर सचमुच पाकिस्तान अपनी सरजमीं से आतंकियों का सफाया करना चाहता है तो इस काम के लिए भारत उनकी तारीफ ही करेगा।

● विकास बिश्नोई, हिसार

बिजली के वाहन

भारत सरकार की योजना है कि वर्ष 2030 तक सड़कों पर मौजूद वाहनों में तीस फीसद वाहन बिजली से चलने वाले हों। लेकिन इस तंत्र के बाद बिजली से चलने वाली कारें काफी महंगी हो जाएंगी और बढ़े दाम आम ग्राहक को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार क्रेडिट प्वाइंट जैसी सुविधा या टोल टैक्स आदि में कुछ छूट जैसे प्रावधान कर सकती है। बीएस-6 मानक लागू होने से बिजली से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित कर सकती है। यहां इ-वाहनों में लगी लिथियम आयन बैटरी की क्षमता पर भी विचार करना होगा, जिसमें बैटरी बार बार चार्ज होने पर इसकी क्षमता में कमी आने लगती है। अभी इ-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में यात्रा करने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विश्वसनीय बैटरी स्टेशन विकसित किए जाएं जो डिस्चार्ज बैटरी के बदले चार्ज की हुई बैटरी उपलब्ध करवा सकें। विकसित देशों में सामान्यतः एक बैटरी एक लाख साठ हजार किलोमीटर तक या आठ वर्ष तक काम करती है। लेकिन खासकर भारत में बेकार हुई बैटरियों से निपटना भी समूची व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती होगी। प्लास्टिक कचरे से निबट रही दुनिया के सामने बेकार बैटरियों का ढेर लग जायेगा। ऐसे में बैटरी के अन्य उपयोग के बारे में भी सोचा जाए।

● अजीत कुमार गौतम, गोरखपुर

खत्म हो तीन तलाक

लोकसभा ने तीसरी बार मुसलिम महिलाओं के लिए, तैयार तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक लोकसभा में दो बार पहले भी पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अटक जाता है। तीन बार 'तलाक-तलाक-तलाक' बोल कर या लिख कर तलाक देने वाले पुरुषों को तीन साल की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट भी बोल कर तलाक लेने की प्रक्रिया को गैरकानूनी करार दे चुका है। पाकिस्तान, इराक, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश जैसे बाईस इस्लामी देश तीन तलाक को गैरकानूनी करार दे चुके हैं। पिछले दो-तीन साल में तीन तलाक के लगभग छह सौ मामले आए हैं। इस मसले पर हाल में संसद में जम कर बहस हुई। महिलाओं के हक से जुड़े इस मुद्दे पर इस बार बहस इसलिए भी अहम थी, क्योंकि नई संसद में सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंची हैं। लेकिन क्या ज्यादा महिला सांसदों का होना औरतों को ज्यादा हक और सुरक्षा की गारंटी हो सकती है? देखना यह होगा कि अब राज्यसभा में यह विधेयक पारित होता है या नहीं। विपक्ष ने इसे गलत ठहराते हुए कई दलील दी है। तीन बार तलाक बोल कर रिश्ता खत्म करना अगर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा तो मुसलिम महिलाओं के लिए यह सबसे बड़ा तोहफा होगा।

● राघव जैन, जालंधर

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

खबर कोना

बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह मुंबई में 19वें ग्लैमर संस्करण का उद्घाटन करती हुईं।

रेलवे, डीडीए जैसे संगठन शोधित जल-मल का करें उपयोग : समिति

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) द्वारा नियुक्त यमुना निगरानी समिति ने सुझाव दिया है कि हरित पैनल फार्म हाउसों, डीडीए, रेलवे एवं मॉल जैसे बड़े संगठनों पर अपने बोरवेल बंद करके शोषित जल-मल के प्रयोग का दबाव बनाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। दो सदस्यीय निगरानी समिति ने हरित पैनल को हाल में दी गई दूसरी पूरक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया। इस समिति के सदस्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पूर्व विशेषज्ञ बीएस सजवान और दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा हैं।समिति ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड प्रतिदिन 45 करोड़ 90 लाख गैलन शोधित जल-मल पैदा करता है, जिसमें से प्रतिदिन केवल आठ करोड़ 90 लाख गैलन पानी ही इस्तेमाल किया जाता है।

वीके जौहरी बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) ।

आइपीएस अधिकारी वीके जौहरी देश के सबसे बड़े सीमा प्रहरी बल 'बीएसएफ' के अगले महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नियुक्ति से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने रविवार को यह आदेश जारी किया। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृहमंत्री अमित शाह उसके सदस्य हैं। मध्य प्रदेश संवर्ग के 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी जौहरी फिलहाल कैबिनेट सचिवालय में रॉ के विशेष सचिव हैं। वह सीमा बीएसएफ में रजनीकांत मिश्रा की जगह लेंगे जो 31 अगस्त को सेवानिवृत हो जाएंगे। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जोहरी को तत्काल प्रभाव से केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मुरबाड में पुल का हिस्सा बहा, यातायात बाधित

ठाणे, 28 जुलाई (भाषा) ।

महाराष्ट्र के ठाणे में मुरबाड और कल्याण को जोड़ने वाली नदी पर बने एक पुल का एक हिस्सा भारी बारिश होने के कारण रविवार तड़के बह गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।मुरबाड तहसीलदार अमोल कदम ने एजंसी को बताया कि रायता गांव में उल्हास नदी पर बने पुल का एक हिस्सा बह गया और भारी बारिश के कारण सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके कारण मुंबई से अमदाबाद को जोड़ने वाले राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है।उन्होंने बताया, अगला आदेश मिलने तक मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। उल्हास नदी में पानी बढ़ जाने के कारण बदलापुर, टिटवाला और कल्याण में बाढ़ आई हुई है। कदम ने जानकारी दी कि बाढ़ में 370 मकान जलमग्न हो गए हैं और बचाव टीमों ने परिवारों को ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचाया है।

बाघ संरक्षण के लिए मोटरसाइकिल यात्रा पर निकला दंपति पहुंचा महाराष्ट्र

नागपुर, 28 जुलाई (भाषा) ।

वन्यजीव एवं बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोलकाता से देश भर की 40000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू करने वाला एक दंपति शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे। रतीन्द्रनाथ दास और उनकी पत्नी गीतांजलि ने बताया कि पश्चिम बंगाल से 15 फरवरी को शुरू हुई उनकी यात्रा खुशनुमा रही और जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई उन्होंने उनका स्वागत किया, लेकिन मध्य प्रदेश के एक गांव में उन्हें गलती से बच्चा चोर समझ लिया गया था। एक वन्यजीव संरक्षक रतीन्द्रनाथ (43) ने बताया, हम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुरा बाघ अभयारण्य जा रहे थे। रास्ते में, हम एक पेड़ के नजदीक आराम करने के लिए रुके। एक स्कूली छात्र ने हमें बच्चा चोर समझ लिया और नजदीक के ग्रामीणों को सतर्क कर दिया। हम पहले उनसे डर गए थे लेकिन हम उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में समझाने में सफल हुए, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी और हमारा सहयोग किया।

यमुना किनारे उगाई जा रहीं सब्जियों में खतरनाक स्तर की धातुएं, कैंसर का डर

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

यमुना नदी के किनारे खेतों में उगाई जा रही सब्जियों में खतरनाक स्तर की धातुएं पाई गई हैं, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं।

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) के अध्ययन के अनुसार, सात तरह की सब्जियों गोभी, फूल गोभी, मूली, बैंगन, धनिया, मेथी और पालक में धातु की सांद्रता की स्थिति का पता लगाने के लिए पूर्वी दिल्ली के तीन स्थानों से नमूने एकत्र किए गए। सब्जियों के नमूने उस्मानपुर खादर, गीता कॉलोनी और मयूर विहार से लिए गए तथा उनमें सीसा, निकल और कैडमियम जैसी धातुओं की मौजूदगी का परीक्षण किया गया।

रिपोर्ट में गीता कॉलोनी से एकत्र किए गए धनिए में अधिकतम सीसा पाया गया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के अनुसार, सब्जियों में सीसा की सुरक्षित सीमा 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। यमुना के मैदानी भाग से एकत्र की गई सब्जियों में सीसे का स्तर 2.8 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से 13.8 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों पर किए गए नीरी के अध्ययन में कहा गया है, 'भारी धातुओं की मौजूदगी वाले खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खाने से मानव शरीर में कई जैविक और जैव रासायनिक प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं।' इसमें कहा गया है, 'भारी धातुओं की विषाक्तता ऊर्जा का स्तर कम कर सकती है और मस्तिष्क, फेफड़े, किडनी और यकृत के संचालन को नष्ट कर सकती है। यह खून बनने की प्रक्रिया और अन्य महत्त्वपूर्ण अंगों को भी नष्ट कर सकते हैं। लंबे समय तक ये मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से कैंसर भी हो सकता है।'

> **सब्जियों** के नमूने उस्मानपुर खादर, गीता कॉलोनी और मयूर विहार से लिए गए तथा उनमें सीसा, निकल और कैडमियम जैसी धातुओं की मौजूदगी का परीक्षण किया

रिपोर्ट में कहा गया कि कैडियम और निकल जैसी अन्य धातुएं एफएसएसएआइ के मानकों से कम पाई गई। नीरी ने कहा, 'इस अध्ययन में ज्यादातर सब्जियों में केवल सीसे की मात्रा एफएसएसएआइ के मानकों से अधिक पाई गई इसलिए हमें यह पता करने की जरूरत है कि सब्जियों में कहां से सीसा मिल रहा है। सीसे के संभावित स्रोत ऑटोमोबाइल, बैटरी, पेंट, पॉलिथीन, कीटनाशक और सीसा प्रसंस्करण इकाई हैं।'

हिमालयी प्रदेशों ने विशेष सहायता की मांग की

जनसत्ता संवाददाता
मसूरी (देहरादून) 28 जुलाई।

हिमालयन कान्क्लेव में केंद्र सरकार से हिमायली राज्यों को ग्रीन बोनस देने की मांग सर्वसम्मति से की गई। साथ ही हिमालयी राज्यों 'मसूरी-संकल्प' पारित कर हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और देश की समृद्धि में योगदान देने का संकल्प लिया। प्रकृति प्रदत्त, जैव विविधता, ग्लेशियरों, नदियों, झीलों के संरक्षण का प्रण लिया। तय किया गया कि हर साल विभिन्न हिमालयी राज्यों में हिमालयन कान्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।

सम्मेलन में तय किया गया कि हिमालयी राज्यों की भावी पीढ़ी के लिए लोककला, हस्त कला, संस्कृति आदि का संरक्षण किया जाएगा और पर्वतीय संस्कृति के आध्यात्मिक परंपरा के संरक्षण और मानवता के हितों के लिए कार्य किया जाएगा। समानता और न्याय की भावना के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के सतत विकास की रणनीति पर काम किया जाएगा। सभी हिमालयी राज्यों की प्रमुख समस्याओं का एक

समान एजेंडा तैयार कर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया गया। साथ ही हिमालयी राज्यों ने संयुक्त रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की कि पर्यावरणीय संरक्षण के एवज में सभी हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए। एजेंडे में कहा गया कि हिमालयी राज्य देश के जल स्तम्भ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल शक्ति संचय मिशन को सफल बनाने में अपना अहम योगदान देंगे। साथ ही इस एजेंडे में मांग की गई कि नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण के लिए केंद्र पोषित योजनाओं में हिमालयी राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाए। नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने में केंद्र सरकार द्वारा सहयोग दिए जाने की मांग भी की। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमालयी राज्यों की समस्याओं के प्रति चिंता जताते हुए इनके निदान का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमालयी राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमालयी राज्यों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन हिमालयी राज्यों के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए केंद्र सरकार से अलग से बजट आबंटित करने की मांग की।

उन्होंने सभी हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों से एक साथ मिलकर काम करने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन अत्यंत कठिन है। यहां की समस्याएं अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल और हवाई सेवाएं और अधिक विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

बम भोले हरिद्वार से लौटते हुए कांवड़िए रविवार को गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से गुजरते हुए। फोटो : अरुण चोपड़ा

अस्पतालों और दवा कारखानों का कचरा एंटीबायोटिक को बना रहा बेअसर

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

विश्व स्तर पर एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने को लेकर जताई जा रही गंभीर चिंता के बीच पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय का कहना है कि एंटीबायोटिक दवा कारखानों का कचरा इसका एक कारण हो सकता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक संभवतः एंटीबायोटिक दवा कारखानों का कचरा, इन दवाओं के मानव शरीर पर असर को खत्म करने वाली प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर रहा है।

मंत्रालय ने संसद सत्र के दौरान पिछले सप्ताह राज्यसभा में बताया कि उसे इस बात की जानकारी है कि एंटीबायोटिक बनाने वाली इकाइयों और अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट एंटीबायोटिक के प्रतिरोध का कारण बन रहा है।

इस बारे में किए गए अध्ययन के हवाले से मंत्रालय ने बताया कि एंटीबायोटिक अपशिष्टों की पर्यावरण में मौजूदगी के कारण, रोगजनक तत्वों को बढ़ाने वाले सूक्ष्मजीव रोधी प्रतिरोध (एएमआर) का संवर्धन होता है।

सूक्ष्मजीव रोधी प्रतिरोधक क्षमता तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्मजीव किसी औषधि के प्रभाव को सहन कर जीवित रह जाते है जबकि सामान्यतः औषधि के प्रभाव की वजह से सूक्ष्मजीव या तो नष्ट हो जाते हैं या इनकी वृद्धि रुक जाती है।

> **पर्यावरण**, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले सप्ताह राज्यसभा में बताया कि उसे इस बात की जानकारी है कि एंटीबायोटिक बनाने वाली इकाइयों और अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट एंटीबायोटिक के प्रतिरोध का कारण बन रहा है

मंत्रालय ने बताया, 'औषधि निर्माण इकाइयों या अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट का निपटान वैज्ञानिक ढंग से नहीं किए जाने पर, एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के संभावित कारण हो सकते हैं।' इसकी वजह पर्यावरण में अनुमानित निष्प्रभावी सांद्रता (पीएनईसी) से अधिक सांद्रता में एंटीबायोटिक की मौजूदगी के कारण सूक्ष्मजीव रोधी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होना है।

मंत्रालय ने बताया कि दवा कंपनियों और अस्पतालों से निकलने वाले हानिकारक रसायनों को पर्यावरण में घुलने से रोकने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत केंद्र और राज्यों के स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दवा कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को शोधित करने के बाद ही सिचाई या जलशोधन संयंत्र (सीईटीपी) में इस्तेमाल की अनुमति देते हैं।

सुरक्षा बलों के लिए पहली एअर एंबुलेंस को मंजूरी

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैनात सुरक्षा बलों और ऊंचाई वाले स्थानों पर सीमा चौकियों की निगरानी में तैनात जवानों के लिए अपनी तरह की पहली एअर एंबुलेंस सेवा को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक हालिया आदेश के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल के एमआई-17 हेलिकॉप्टर पर एअर एंबुलेंस होगी और इसे झारखंड की राजधानी रांची में तैनात रखा जाएगा। इस बाबत एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को समर्पिता इस एअर एंबुलेंस सेवा में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे।

अधिकारी ने बताया कि स्टेबिलाइजर तथा ऑक्सीजन सिलिंडर जैसे चिकित्सा उपकरणों को भी इस हेलिकॉप्टर में लगाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस नई सुविधा से अभियानों में घायल हुए जवानों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने तथा उनके रक्तस्राव को रोकने में महत्त्वपूर्ण रूप से समय की बचत होगी और इससे बेशकीमती जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। वैसे इस एंबुलेंस का इस्तेमाल सुदूरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय पुलिस कर्मियों को वहां से हटाने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। यह पहला मौका है जब केंद्रीय बलों के लिए ऐसी पूर्णकालिक हवाई चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। इससे खासकर नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में मदद मिलेगी जहां चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है और जो संपर्क की समस्याओं से प्रभावित है।

दलित विधायक के धरना स्थल का शुद्धिकरण करने पर विवाद

त्रिशूर (केरल) , 28 जुलाई (भाषा) ।

केरल में भाकपा के दलित विधायक के धरने के विरोध में प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कथित प्रतीकात्मक शुद्धिकरण कार्यक्रम पर विवाद खड़ा हो गया है। विधायक ने इसे जातिवादी करार देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राज्य के मंत्रियों ने भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निंदा की और कहा कि ऐसे कृत्य स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

> **केरल में**, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस कदम के खिलाफ विधायक ने पुलिस में शिकायत दज कराई

त्रिशूर के समीप चेरप्पू में शनिवार को नत्तिका की विधायक गीता गोपी इलाके में सड़क की 'खराब दशा' के विरूद्ध लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी थीं। उनके विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और आरोप लगाया कि धरना लोगों को 'बेवकूफ' बनाने की हरकत है।

जहां पर गीता धरने पर बैठी थीं, वहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक शुद्धिकरण के तौर पर गाय के गोबर मिश्रित पानी का छिड़काव भी किया। विधायक ने आरोप लगाया कि यह कार्यक्रम जातिवादी था और उन्होंने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। केरल के संस्कृति मंत्री एके बलान ने कहा, ऐसी हरकतें आम तौर पर उत्तरी भारत में देखने को मिलती है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री के के श्यालजा ने भी इस घटना की निंदा की।

अदालत ने प्राधिकारियों से पूछा

मनोरोगियों के लिए कोई समीक्षा बोर्ड क्यों नहीं?

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राधिकारियों से यह बताने को कहा कि मनोरोगियों के लिए कानून के तहत अनिवार्य समीक्षा बोर्ड अभी तक क्यों गठित नहीं किया गया है।

एक गैर सरकारी संगठन ने स्वयं को एमबीबीएस स्नातक बताने वाली और एनजीओ के आश्रय गृह में रहने वाली एक बेघर महिला के मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए याचिका दायर की थी। महिला ने अदालत के आदेश के बिना या वकील की गैरमौजूदगी में चिकित्सकीय जांच कराने से इनकार कर दिया था। इस याचिका की सुनवाई के दौरान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राधिकारियों से यह सवाल किया।

न्यायाधीश ने इसे एक अजीब हालात बताते हुए कहा कि मनोरोगी को उसकी मर्जी के बिना भर्ती कराने और उसका उपचार करने की अनुमति देने का अधिकार जिला मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के पास होता है और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के पास इस संबंध में अधिकार नहीं हैं।

अदालत ने कहा, 'यह सूचित किया जाता है कि जिला मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड अभी गठित किए जाने हैं। ...मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कानून, 2017 की धारा 73 के तहत अनिवार्य है कि राज्य प्राधिकारी सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड गठित करें।' उसने कहा, 'राज्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया जाए कि वे अदालत के सामने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट दें कि मनोरोगियों के लिए कानून की अनिवार्यता के अनुसार समीक्षा बोर्ड अभी तक गठित क्यों नहीं किया गया।'

1297 चयनित ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास के सिर्फ 56 फीसद कार्य पूरे हुए | **आंकड़े** | **11 अक्तूबर, 2014 को यह योजना शुरू की गई थी**

सांसद आदर्श ग्राम योजना में आधे से ज्यादा काम पूरा

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में प्रारंभ सांसद आदर्श ग्राम योजना लक्ष्य से काफी दूर है और योजना शुरू होने के करीब पांच वर्ष बाद 1297 चयनित ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास के सिर्फ 56 फीसद कार्य ही पूरे हो सके हैं। इस योजना की परिकल्पना गांवों का कायापलट करने और सुविधा संपन्न बनाने के लिए की गई थी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट 'डब्लूडब्लूडब्लू डॉट सांझी डॉट जीओवी डॉट इन' पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, तीन जुलाई 2019 तक सांसदों ने इस योजना के तहत 1484 ग्राम पंचायतों की पहचान की थी। सांसदों के मार्गदर्शन में ग्राम विकास योजना (वीडीएफ) के लिए गांवों को विकास के लिए गोद लिया जाता है। अब तक 1297 ग्राम पंचायतों ने ग्राम विकास योजना के संदर्भ में 68,407 परियोजनाओं का ब्योरा अपलोड किया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 'सांसद ग्राम योजना के तहत इनमें से 38,021 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो कुल परियोजना का 56 फीसद है।'

गौरतलब है कि गांवों के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में किया था। 11 अक्तूबर 2014 को यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत सांसदों को अपने क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम का चयन करके उसका विकास करना था।

योजना के तहत 2014 से 2019 के बीच चरणबद्ध तरीके से सांसदों को तीन गांव गोद लेने थे और 2019 से 2024 के बीच पांच गांव गोद लेने की बात कही गई है। इस योजना के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है और सांसदों को सांसद निधि (एमपीलैड) के कोष से ही इसका विकास करना होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल महाराष्ट्र, ओड़ीशा, पंजाब में सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यों का क्रियान्वयन खराब पाया गया है।

अरुणाचल में गोद ली गईं 7 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 216 परियोजनाओं में से 28 योजनाएं ही पूरी हुई हैं जबकि असम में गोद ली गई 35 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 2,229 परियोजनाओं में से केवल 580 योजनाएं ही पूरी हो सकीं। बिहार में ऐसी 82 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 4817 परियोजनाएं में से 1614 योजनाएं ही पूरी हो सकीं।

इसी तरह, दिल्ली में गोद ली गई 13 ग्राम पंचायतों में कोई ग्राम विकास योजना अपलोड नहीं की गई है।

हिमाचल प्रदेश में गोद ली गईं 14 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 1291 परियोजनाओं में से 420 योजनाएं ही पूरी हुई । कर्नाटक में ऐसी 57 ग्राम पंचायतों में 9,650 ग्राम विकास योजनाओं में से 5,085 योजनाएं पूरी हुई।

सड़क पर नमाज अदा करने से परहेज करें मुसलिम : पर्सनल लॉ बोर्ड

लखनऊ, 28 जुलाई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सड़क पर नमाज पढ़ने के विरोध में कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने की घटनाओं के बीच मुसलिम धर्म गुरुओं ने सड़क पर नमाज अदा करने से परहेज करने को कहा है। ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने रविवार को एक बातचीत में कहा कि शरीयत के हिसाब से खाली जगह पर नमाज अदा की जा सकती है। इस सवाल पर कि सड़क तो कोई खाली जगह नहीं है, मौलाना ने कहा कि वह इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहते। मेरी बात का मतलब निकालने का काम सुनने और पढ़ने वालों पर छोड़ दें। उधर, कथित हिंदूवादी संगठनों द्वारा जबरन 'जय श्रीराम' बुलवाने और विरोध पर मारपीट करने की हाल की घटनाओं पर बोर्ड के एक अन्य वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व के बारे में जितना भी पढ़ा है, उसमें कहीं भी जोर-जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। भगवान राम ने कहीं भी अपने मानने वालों से यह नहीं कहा है कि किसी से जबरन जयकारा लगवाएं। वह तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं।

उनके नाम पर अमर्यादित आचरण कैसे किया जा सकता है? जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भगवान राम और उनकी शिक्षा का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि वह जिनके नाम पर जुल्म कर रहे हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है।

बारामूला में चार जगहों पर एनआइए के छापे

पेज 1 का बाकी

एनआइए की टीमों ने छापे मारे। हवाला नेटवर्क और पाकिस्तान से आतंक मचाने के लिए धन भेजने की साजिश के शक में एनआइए पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनआइए ने इससे पहले 23 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित केलर इलाके में कारोबारी गुलाम अहमद वानी के घर पर छापेमारी की थी। भारत-पाक के बीच नियंत्रण रेखा के आर-पार कारोबार से जुड़े वानी पर हवाला नेटवर्क और पाकिस्तान से आतंक के लिए फंडिंग की साजिश में संलिप्त होने के शक के आधार पर यह छापेमारी की गई थी।

पिछले महीने ही एनआइए ने दावा किया था कि कश्मीर घाटी में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से आतंक के लिए धन आता रहा है। हुर्रियत कांफ्रेंस और कई अन्य अलगाववादी नेताओं से पूछताछ के बाद एनआइए ने यह दावा किया था। एनआइए के मुताबिक, मुस्लिम लीग नेता मसर्रत आलम ने अधिकारियों से बताया कि पाकिस्तान समर्थित एजंट ने विदेश से पैसे जुटाए और हवाला संचालकों के जरिए उसे जम्मू-कश्मीर भेजा।

गौरतलब है कि एनआइए ने जमात उद दावा, दुख्तरान ए मिल्लत, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू-कश्मीर के दूसरे अलगाववादी समूहों के खिलाफ फंड जुटाने को लेकर 20 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। एनआइए ने 13 आरोपियों पर इस संदर्भ में आरोप-पत्र दाखिल किया है। इसमें कई अलगाववादी नेता, हवाला कारोबारी और पत्थरबाज शामिल हैं।

धारा 35ए से छेड़छाड़ बारूद में आग लगाने जैसा होगा : महबूबा

पेज 1 का बाकी

को विशेष अधिकार प्रदान करती है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का स्थापना दिवस मनाने के लिए श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अनुच्छेद 35 ए की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार रहें। उन्होंने कहा, 'हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि धारा 35 ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा। यदि कोई हाथ 35 ए को छूने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ वह हाथ, बल्कि सारा शरीर जलकर राख बन जाएगा।'

महबूबा ने अतिरिक्त 100 कंपनियों को तैनात करने के केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दा राजनीतिक समस्या है, जिसे सैन्य तरीके से हल नहीं किया जा सकता है। केंद्र को अपनी कश्मीर नीति पर पुनर्विचार करना होगा। अतिरिक्त 10 हजार सैनिकों की तैनाती के फैसले ने घाटी के लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है।

डोभाल ने कश्मीर के आतंक रोधी ग्रिड के अधिकारियों के साथ की बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने रविवार को कश्मीर के आतंक रोधी ग्रिड के आला अफसरों के साथ दिल्ली में बैठक की। कश्मीर में अर्द्धसैनिक बलों के 10 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के बाद वहां बढ़ी राजनीति हलचल और बड़े आतंकी हमले की खुफिया सूचना के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने चर्चा की।

कश्मीर में आतंकी हमले की खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा तैयारियों पर विचार

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, डोभाल के साथ बैठक में खुफिया ब्यूरो, अर्द्धसैनिक बलों व कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। कश्मीर में आतंकी हमले की खुफिया एजंसियों द्वारा जुटाई गई जानकारी के मद्देनजर बैठक बुलाई गई थी। साथ ही, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया के असर को लेकर भी अधिकारियों ने चर्चा की। महबूबा का कहना है कि केंद्र सरकार कश्मीर में धारा 35ए हटाने की तैयारी कर रही है। इसीलिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है।

अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर में हिंसा भड़काने की कोशिश और शांति भंग करने के प्रयास के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। इस तरह के किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है। कोशिश होगी कि आम नागरिकों को कम-से-कम असुविधा हो।

जम्मू-कश्मीर भाजपा कोर समूह की बैठक कल

पेज 1 का बाकी

विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में हुए थे।

जम्मू कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसे तीन जुलाई से और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

इस बीच, जम्मू में जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) पर अनुच्छेद 370 के नाम पर और जम्मू कश्मीर को प्राप्त 'विशेष दर्जा' के बहाने लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा कि इन दलों ने आजादी के बाद करीब आधी सदी तक राज्य में शासन किया और उनके शासन के तहत संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर तक विस्तारित किए गए।

भाजपा विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती जख्मी

पेज 1 का बाकी

के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक ही परिवार के हैं। बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़की, उसकी चाची और मौसी अपने वकील के साथ जेल में बंद अपने एक रिश्तेदार मुलाकात करने गए थे। मालूम हो कि इस लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित सरकारी आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद ही सेंगर वाला मामला बाहर आया था।

भीड़ हिंसा के नाम पर हिंदू धर्म को किया जा रहा बदनाम : भागवत

पेज 1 का बाकी

भिन्न-भिन्न मतों-पंथों और उपासना पद्धतियों के लोग साथ बैठें और समाज में जाति एवं वर्गों के बीच पनप रहे भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करें। जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर कई समस्याएं हल हो जाएंगी।'

इस बैठक में भारतीय सामाजिक सद्भाव समिति से जुड़े उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा और मेघालय समेत सभी राज्यों के प्रतिनिधि एवं संघ से जुड़े अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। संघ के सभी प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों की रिपोर्ट बिंदुवार रखी। संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, दतात्रेय होसबोले और भैया जी जोशी ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे।

कश्मीर में नफरत फैलाने वाले सफल नहीं होंगे

पेज 1 का बाकी

हुए, जो बेहद संवेदनशील और दूरदराज के इलाकों में स्थित हैं। सरकारी अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा करने के लिए गांव- गांव पहुंचे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'जिन अधिकारियों को कभी गांव वालों ने देखा तक नहीं था, वे खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंचे, ताकि विकास के काम में आ रही बाधाओं को समझा जा सके, समस्याओं को दूर किया जा सके।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'ये अधिकारी उन सीमावर्ती पंचायतों तक भी पहुंचे, जो हमेशा सीमा पार से होने वाली गोलीबारी के साए में रहती हैं। यही नहीं शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिले के अति संवेदनशील इलाके में भी अधिकारी बिना किसी डर के पहुंचे। पहली बार वरिष्ठ अधिकारी 4,500 से अधिक पंचायतों में ग्रामीणों की दहलीज पर पहुंचे।

प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया कि एक जुलाई से शुरू होने के बाद तीन लाख से अधिक तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पूरी कर चुके हैं और तीर्थयात्रियों का आंकड़ा वर्ष 2015 में 60 दिनों में तीर्थयात्रा करने वाले कुल तीर्थयात्रियों को पीछे छोड़ चुका है। प्रदेश के लोगों की आदर सत्कार भावना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन में वृद्धि होगी।

उन्होंने उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का भी जिक्र किया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने पवित्र तीर्थस्थलों की यात्रा की है। उन्होंने बताया कि 2013 की विनाशकारी आपदा के बाद आठ लाख से अधिक लोग केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर चुके हैं।

अपने 25 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोगों से 15 अगस्त को विशेष तैयारियों के साथ मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'आपको अवश्य ही इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि 15 अगस्त को कैसे लोक उत्सव के रूप में और जनता के त्योहार के रूप में मनाया जा सकता है।' देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकारों के साथ मिलकर तेजी से काम कर रहा है, ताकि लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके।

अयोग्यता के खिलाफ कोर्ट जाएंगे : विश्वनाथ

पेज 1 का बाकी

विरुद्ध' है और वह और अन्य असंतुष्ट विधायक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

विश्वनाथ ने फोन पर कहा, 'अयोग्यता विधि विरुद्ध है। मात्र उन्हें जारी विप के आधार पर आप विधायकों को सदन में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।' विधायक ने किसी अज्ञात स्थान से कहा, 'अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हम सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।' वहीं, अयोग्य घोषित किए गए एक अन्य विधायक प्रताप गौड़ा पाटिल ने बेंगलुरू में मतदाताओं के नाम जारी वीडियो संदेश में कहा कि वे चिंतित न हों। उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलने का पूरा विश्वास है।

पाटिल ने कहा, 'प्रिय मतदाताओं और मेरे शुभचिंतकों, विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे विधानसभा से अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं।' इसके साथ ही एक अन्य अयोग्य विधायक मुनिरत्न ने एक स्थानीय समाचार चैनल से कहा कि वे इस बात से अवगत थे कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें इस बारे में धमकी दी थी।

मुनिरत्न ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता गठबंधन सरकार का खात्मा चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस पर काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के भीतर नेताओं ने सरकार को निर्बाध ढंग से चलाने में कुमारस्वामी का सहयोग तक नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया, 'वे (कांग्रेस नेता) अब यह दिखाने के लिए खेल खेल रहे हैं कि वे जद (सेकु) के प्रति वफादार हैं। आगामी दिनों में लोगों के सामने हम हर चीज का खुलासा कर देंगे।' वहीं, येल्लापुर से विधायक रहे शिवराम हेब्बार ने फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया कि बागी विधायकों को अयोग्य करने का फैसला दबाव में पक्षपातपूर्ण ढंग से किया गया और मामला जल्द ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। शीर्ष अदालत से न्याय मिलने का विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अपने मतदाताओं पर उनको पूरा भरोसा है और वह खुद को जल्द ही जनता की अदालत के समक्ष पेश करेंगे।उन्होंने मतदाताओं और समर्थकों से कहा, 'मैं जल्द ही आपको अपने फैसलों के कारणों के बारे में बताऊंगा और आपसे विचार-विमर्श के बाद आगे का कदम उठाऊंगा।'

हिमाचल प्रदेश भाजपा के दो नेता पार्टी से निलंबित

पेज 1 का बाकी

भाजयुमो नेता (जिसे निलंबित कर दिया गया है) की पत्नी के हाथ उस समय लगा था, जब उस महिला ने फरवरी में उसके पति को वाट्सऐप पर इसे भेजा था। उस महिला और नेता की पत्नी के बीच कुछ मिनट का एक ऑडियो टेप भी जारी हुआ है, जिसमें वह, उस महिला को पति से दूर रहने को कह रही है। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने बताया कि दोनों नेता कुल्लू जिले की भाजपा इकाई और पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाइएम) से जुड़े हैं।

कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि वीडियो में दिख रही महिला के पुलिस से शिकायत करने पर शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67ए के तहत बंजर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जिला पुलिस प्रमुख ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इसे साझा करने को लेकर चेताया है। जिला पुलिस प्रमुख ने कहा, 'वीडियो को जिसने साझा किया है, या जो इसे साझा करेंगे या इसे अपने पास रखेंगे उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'

कर्नाटक में 14 और बागी विधायक अयोग्य करार

पेज 1 का बाकी

जल्दबाजी में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में की। उनका यह फैसला कांग्रेस-जद (सेकु) गठबंधन सरकार गिरने के बाद येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के दो दिन बाद आया है।

विधानसभाध्यक्ष की इस कार्रवाई का येदियुरप्पा सरकार के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इन विधायकों के तत्काल प्रभाव से अयोग्य ठहराए जाने से उनकी अनुपस्थिति से सदन की प्रभावी संख्या कम हो जाएगी जिससे भाजपा के लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जद(सेकु) गठबंधन सरकार द्वारा पेश विश्वासमत पर मतविभाजन के समय 20 विधायकों के अनुपस्थित रहने से कई सप्ताह के नाटकीय घटनाक्रम के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। इन 20 विधायकों में 17 बागी विधायक और एक-एक कांग्रेस व बसपा का और एक निर्दलीय था।

17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बाद 224 सदस्यीय विधानसभा (विधानसभाध्यक्ष को छोड़कर जिन्हें मत बराबर होने की स्थिति में मतदान का अधिकार है) में प्रभावी संख्या 207 हो गई है। इसके साथ ही जादुई संख्या 104 रहेगी। भाजपा के पास एक निर्दलीय विधायक के समर्थन से 106 सदस्य, कांग्रेस 66 (मनोनीत सदस्य सहित), जद (सेकु) 34 और एक बसपा का सदस्य जिसे विश्वासमत के दौरान कुमारस्वामी सरकार के लिए मतदान नहीं करने के लिए पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया गया है।

कुमार से जब अयोग्य ठहराने के उनके विवादास्पद फैसले, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और पूरे मुद्दे पर उनके व्यवहार को लेकर आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैंने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया। मुझे 100 फीसद आघात लगा है।' विधानसभाध्यक्ष की ओर से यह फैसला अचानक ऐसे समय आया है जब भाजपा की ओर से यह संकेत दिया गया कि स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ने पर वह उनके खिलाफ सोमवार को विधानसभा की बैठक के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। कुमार ने कहा कि वह यह कार्रवाई उन बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली कांग्रेस और जद (सेकु) की अर्जियों पर कर रहे हैं जिन्होंने विधानसभा सदस्य के तौर पर अपने इस्तीफे सौंप दिए थे और जो एच डी कुमारस्वामी द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव पर मतविभाजन के दौरान मौजूद नहीं थे। उसके कारण कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। कुमार ने कहा कि उन्होंने बागी विधायकों के उस अनुरोध को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफों और उनके खिलाफ अयोग्य ठहराने की अर्जियों को लेकर उनके समक्ष पेश होने के लिए और चार सप्ताह का समय मांगा था। विधानसभाध्यक्ष ने इससे पहले बागी तीन विधायकों को अयोग्य ठहराने के समय ही स्पष्ट कर दिया था कि दलबदल निरोधक कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी सदस्य वर्तमान सदन के कार्यकाल की समाप्ति तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इस दलील को भाजपा, बागी विधायकों और कई अन्य विधिक विशेषज्ञों ने चुनौती दी है।

विधानसभाध्यक्ष ने इन विधायकों के नाम पढ़ते हुए कहा, 'ये तत्काल प्रभाव से 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति (2023 में) तक विधायक नहीं रहेंगे।' उन्होंने कहा, 'मैंने यह निर्णय जिम्मेदारी और भय के साथ लिया है।' कुमार ने भावुक होते हुए कहा, 'जिस तरह से एक विधानसभाध्यक्ष के तौर पर इन चीजों से निपटने को लेकर मुझ पर मानसिक दबाव डाला जा रहा है, मैं भारी अवसाद में चला गया हूं।' अयोग्य ठहराए गए विधायक हैं: प्रताप गौड़ा पाटिल, बी सी पाटिल, शिवराम हेब्बर, एस टी सोमशेखर, बी बसावराज, आनंद सिंह, रोशन बेग, मुनीरत्ना, के सुधाकर और एम टी बी नागराज और श्रीमंत पाटिल (सभी कांग्रेस के)। अन्य पार्टी विधायकों रमेश जरकीहोली, महेश कुमातली और शंकर को गुरुवार को अयोग्य ठहरा दिया गया था। कार्रवाई का सामना करने वाले जद (सेकु) के विधायकों में गोपालैयाह, ए एच विश्वनाथ और नारायण गौड़ा हैं। विधानसभाध्यक्ष ने सत्र से एक दिन पहले अपने आदेश को जल्दबाजी में सुनाने को उचित ठहराते हुए कहा कि उन्हें ऐसा सोमवार को विधानसभा की बैठक के मद्देनजर करना था जिसका 'विशिष्ट एजेंडा' विश्वास प्रस्ताव को लेना और महत्वपूर्ण विनियोग विधेयक पारित करना है।

बिहार में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से सात बच्चों की मौत

छपरा, 28 जुलाई (भाषा)।

बिहार के सारण जिले के इसुआपुर थाना अंतर्गत डोइला गांव स्थित एक तालाब में रविवार को नहाने के दौरान डूबने से सात बच्चों की मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर राय ने बताया कि मृतक बच्चों के शव तालाब से निकाल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तालाब में कुल नौ बच्चे नहाने के दौरान डूबने लगे जिनमें दो को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। सुआपुर थानाध्यक्ष रूपेश कुमार वर्मा ने बताया कि मृतक बच्चों में राजा नट, अर्जुन नट, बिट्टू नट, सत्यम नट, चंदन नट, टीमन नट और सूरज नट शामिल हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है।

एनआइए को श्रीलंका बम विस्फोटों की जांच का जिम्मा

पेज 1 का बाकी

थी। इसमें कई भारतीय नागरिक भी थे। ईस्टर हमलों से पहले भारत ने श्रीलंका को सतर्क किया था कि आइएस के आतंकवादी वहां हमला करने की साजिश रच रहे हैं। एनआइए ने श्रीलंका के अधिकारियों को नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) के प्रमुख जहरान हाशिम का एक वीडियो भी सौंपा, जिसमें वह श्रीलंका के अलावा भारत के तमिलनाडु, केरल में आतंकी हमलों के लिए गुमराह युवकों को उकसा रहा है और कह रहा है कि इस इलाके में इसलाम का राज कायम करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। श्रीलंका में जिन नौ आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोट किए, उनमें हाशिम भी था। श्रीलंका धमाकों के सिलसिले में एनआइए ने केरल के पलक्कड से 29 साल के रियाज अबूबकर उर्फ अबु दुजाना को पकड़ा है। वहां सोशल मीडिया के जरिए हाशिम के संपर्क में था।

नेतृत्व को लेकर स्पष्टता की कमी से कांग्रेस को नुकसान : थरूर

पेज 1 का बाकी

मिल सकेगी और उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने का विश्वसनीय जनादेश मिलेगा।' थरूर ने पार्टी अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने के लिए ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की शैली अपनाने का सुझाव दिया जिससे वह फिर और ज्यादा मतदाताओं को अपनी ओर प्रेरित कर सकती है।

कांग्रेस की कमान युवा नेता के हाथ में सौंपने के अमरिंदर सिंह के बयान पर सहमति जताते हुए थरूर ने कहा कि पार्टी की मौजूदा स्थिति और राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जो भी अध्यक्ष का पद संभालेगा, उसे दो लक्ष्य हासिल करने होंगे। पहले तो कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा और दूसरा कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं को प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर नया अध्यक्ष पूरी तरह से संगठनात्मक व्यक्ति होता है तो हो सकता है कि वह कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर पाए और पार्टी की नींव मजबूत कर पाए लेकिन वे शायद और मतदाताओं को जोड़ नहीं पाए। थरूर ने कहा कि अगर अध्यक्ष कोई करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनता है लेकिन उसके पास अगर संगठनात्मक कौशल का अभाव है तो वह चाहे राष्ट्रीय मतदाताओं को निजी तौर पर प्रभावित कर सके लेकिन अपने करिश्मे को चुनावी नतीजे में बदल पाने की गुंजाइश कम होगी। उन्होंने कहा, 'इन परिस्थितियों में कोई भी यह मानेगा कि जो लंबे समय से इन भूमिकाओं को निभाते हुए थका न हो ऐसा युवा नेता, यह दोनों काम करने के लिए इस पद पर उपयुक्त होगा।'

यह पूछने पर कि क्या उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त है, इस पर थरूर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उनके पास स्वाभाविक करिश्मा है जो निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को प्रेरित और एकजुट कर सकता है। उनकी इसी खूबी के कारण कई लोग उनकी तुलना उनकी दादी व पूर्व पार्टी अध्यक्ष दिवंगत इंदिरा गांधी से करते हैं।

अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा कर पलटी, दो की मौत

पेज 1 का बाकी

घायलों को पास के जीटीबी अस्पताल में लेकर गए हैं। वहां पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि हादसे में सिरसा, हरियाणा निवासी छात्रा रूबल (20) और सब्जी मंडी, मलकागंज, दिल्ली निवासी छात्र प्रभजोत सिंह (18) की मौत हो गई। वहीं, कमला नगर निवासी केशव (21) की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हरियाणा की सिरसा निवासी अर्शप्रीत कौर (19) का भी जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के समय लक्ष्य माम नाम का युवक वाहन चला रहा था। लक्ष्य का इलाज सर गंगाराम अस्पताल में पुलिस हिरासत में चल रहा है।

शुरुआती छानबीन में पता चला है कि सभी दोस्त जन्मदिन की पार्टी कर लौट रहे थे। पुलिस को कार से शराब की बोतलें और खाने-पीने की चीजें मिली हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखचे उड़ गए। सीट बेल्ट और एअर बैग खुलने की वजह से कार चला रहा लक्ष्य (22) बच गया। उसको मामूली चोट लगी है। अर्शप्रीत का शनिवार को जन्मदिन था। पार्टी मनाकर वे सभी लोग लौट रहे थे। माना जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान इन लोगों ने शराब पी रखी होगी और कार चला रहे लक्ष्य ने अपना संतुलन खो दिया होगा।

पुलिस को कार से शराब की कुछ बोतलें, सिगरेट के पैकेट और खाने के सामान मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मूलरूप से सिरसा की रहने वाली रूबल बचपन की दोस्त अर्शप्रीत के साथ सोहनगंज, सब्जी मंडी इलाके में पीजी में रहती थी। रूबल दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा थी। वहीं, अर्शप्रीत दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के एक कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही है। प्रभजोत परिवार के साथ सोहनगंज में रहता था। अर्शप्रीत के अलावा केशव, प्रभजोत और रूबल पढ़ाई के अलावा कमला नगर में अक्षय नामक युवक के कॉल सेंटर में नौकरी करते थे। अक्षय का छोटा भाई लक्ष्य अर्शप्रीत का दोस्त है। शनिवार को अर्शप्रीत का जन्मदिन था। लक्ष्य, केशव, रूबल और प्रभजोत ने अर्शप्रीत का जन्मदिन मनाने का फैसला किया था। शनिवार रात के समय लक्ष्य अपने भाई की होंडा सिटी कार लेकर आ गया। पांचों ने दिलशाद गार्डन इलाके में एक फ्लैट पर रातभर पार्टी की। इस बीच, रविवार तड़के 5:40 बजे पांचों दोस्त गाजियाबाद के रामप्रस्थ अपने एक दोस्त से मिलने गए। वहां से सभी कमला नगर के लिए लौट रहे थे। कार लक्ष्य चला रहा था। रूबल चालक के बराबर वाली सीट पर बैठी थी। बाकी पीछे केशव, अर्शप्रीत व प्रभजोत बैठे थे। रामप्रस्थ से निकलने के बाद लक्ष्य काफी तेज गति से कार चलाने लगा। सीमापुरी अंडरपास से पहले वह कार से नियंत्रण खो बैठा और पेट्रोल पंप के सामने डिवाइडर से कार टकरा गई।

ईरान ने टैंकर विवाद को परमाणु समझौते से जोड़ा

विएना, 28 जुलाई (एएफपी)।

ईरान ने रविवार को कहा कि उसका मानना है कि ब्रिटेन द्वारा ईरानी तेल टैंकर को पकड़ना 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन है। समझौते को बचाने के लिए इससे जुड़े शेष पक्षों की विएना में हुई बैठक में यह मुद्दा उठा।

ब्रिटिश अधिकारियों ने जुलाई के शुरू में ईरान के एक तेल टैंकर को पकड़ लिया था और आरोप लगाया था कि यह सीरिया पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने 19 जुलाई को हरमुज जलडमरूमध्य में ब्रिटेन के झंडे वाले टैंकर को पकड़ लिया था जिस पर चालक दल के 23 सदस्य सवार थे।

विएना बैठक में पहुंचे ईरान के उपविदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पत्रकारों से बातचीत में टैंकर विवाद को संयुक्त समग्र कार्य योजना (जेसीपीओए) के नाम से जाने जाने वाले परमाणु समझौते से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जेसीपीओए के तहत ईरान को तेल आयात करने का हक है और ईरान को तेल निर्यात करने से रोकने कोई भी कोशिश जेसीपीओए के खिलाफ है। ईरान के तेल निर्यात का मसला और अमेरिका के उसे पूरी तरह रोकने की कोशिश का मुद्दा भी बैठक में उठा। अरागची ने कहा, 'मेरे खयाल से माहौल रचनात्मक था और चर्चा अच्छी रही। मैं नहीं कह सकता कि हम सब कुछ हल कर देंगे।' आस्ट्रिया की राजधानी में हुई इस बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस और ईरान के प्रतिनिधि शामिल हुए। चीन के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख फू कॉन्ग ने कहा कि रविवार की वार्ता अच्छे और पेशेवर माहौल में हुई, लेकिन भागीदारों के बीच कुछ तनावपूर्ण क्षण भी हुए।

विएना में बैठक

मास्को में चुनाव को लेकर प्रदर्शन, 1400 गिरफ्तार

मास्को, 28 जुलाई (एएफपी)।

मास्को में शनिवार को चुनाव संबंधी मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान रूस की पुलिस ने करीब 1400 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शनिवार को हुए इस प्रदर्शन में 3500 लोगों ने हिस्सा लिया था।

अधिकारियों द्वारा विपक्ष के प्रमुख उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के बाद शनिवार को यह प्रदर्शन किया गया। करीब एक सप्ताह पहले ही अधिकारियों पर यह फैसला वापस लेने का दबाव बनाने के लिए 22,000 लोग सड़कों पर उतरे थे। शनिवार को मौके पर मौजूद पत्रकारों ने बताया कि पुलिस ने सिटी हॉल के बाहर एकत्रित होने की कोशिश कर रहे लोगों को रोकने के लिए लाठियां चलाईं।

मास्को सिटी काउंसिल के मतदान पत्र से विपक्षी उम्मीदवारों का नाम हटाए जाने के खिलाफ मास्को में प्रदर्शनकारियों को रोकते सुरक्षाकर्मी। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन का प्रसारण कर रहे टीवी स्टेशन के कार्यालय में भी प्रवेश किया।

एलर्जी होने के बाद विपक्षी नेता अस्पताल में भर्ती

मास्को, 28 जुलाई (भाषा)।

रूस के विपक्ष के नेता एलेक्सी नावालनी को गंभीर एलर्जी के कारण जेल से रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एलेक्सी के चेहरे पर सूजन है और शरीर की त्वचा लाल हो गयी है। मास्को शहर के चुनावों में हिस्सा लेने से प्रमुख विपक्षी उम्मीदवारों को रोकने के विरोध में एलेक्सी ने जन आंदोलन का आह्वान किया था। इसके बाद उन्हें 30 दिन के कारावास की सजा दी गई थी। नावालनी के प्रवक्ता कीरा यारमाईश ने ट्वीट किया, 'एलर्जी कैसे हुई है इसका पता नहीं चल पाया है।'

खाड़ी में यूरोपीय बलों का बेड़ा भेजने का प्रस्ताव उकसाने वाला : ईरान

तेहरान, 28 जुलाई (एएफपी)।

ईरान ने रविवार को खाड़ी में टैंकरों के साथ चलने के लिए यूरोप की अगुआई वाले नौसैनिक मिशन के ब्रिटेन के प्रस्ताव को उकसाने वाला करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। जहाजों की जब्ती के मुद्दे पर पहले से कायम तनाव के बीच ईरान ने ब्रिटेन पर निशाना साधा है।

सरकारी प्रवक्ता अली रबीई ने कहा, 'हमने सुना है कि वह फारस की खाड़ी में यूरोपीय बेड़ा भेजने वाले हैं, जो स्वाभाविक तौर पर प्रतिकूल संदेश है, उकसावे भरा है और इससे तनाव बढ़ेगा।' ब्रिटेन ने सोमवार को कहा था कि वह 19 जुलाई को ईरान द्वारा उसके तेल टैंकर को कब्जे में लेने के जवाब में यूरोपीय नेतृत्व वाले बल को खाड़ी में भेजने पर विचार कर रहा है। 'स्टेना इम्पेरो' नाम के इस तेल टैंकर को ईरान ने तब जब्त किया था जब इससे दो हफ्ते पहले ब्रिटिश अधिकारियों ने 'ग्रेस वन' नाम के ईरानी टैंकर को जब्त कर लिया था। 'ग्रेस वन' पर आरोप था कि वह सीरिया पर यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है। ईरान के सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि ईरान का मानना है कि क्षेत्र के देशों को तेल संपन्न खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा बरकरार रखनी होगी। अली ने कहा, 'हम फारस की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा के सबसे बड़े एजेंट हैं।' ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि ऐसे बल से मामला और बिगड़ेगा ही। तेहरान में ओमान के विदेश राज्य मंत्री यूसुफ बिन अलावी से वार्ता के बाद रूहानी ने कहा, 'विदेशी बलों की मौजूदगी से क्षेत्र की सुरक्षा में मदद नहीं मिलेगी और यह तनाव का मुख्य स्रोत होगा।'

हांगकांग में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी गई

हांगकांग, 28 जुलाई (एएफपी)।

हांगकांग में दंगा रोधी पुलिस ने रविवार को बेजिंग कार्यालय के पास लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां दागीं।

शहर में रविवार को लगातार दूसरे दिन भी हिंसा हुई, जहां कई सप्ताह से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। यह झड़प उस लायजन आफिस के पास आवासीय इलाके के नजदीक हुई जो कि यहां बेजिंग का प्रतिनिधित्व करता है। इस कार्यालय पर पिछले सप्ताह अंडे और पेंट फेंके गये थे। शहर में हजारों प्रदर्शनकारियों द्वारा मार्च किए जाने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई घंटे गतिरोध रहा। करीब 200 प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने शेउंग वान जिला स्थित लायजन आफिस की ओर मार्च किया, जहां उनका सामना दंगा रोधी पुलिस से हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से सभा समाप्त करने की अपील की। बाद में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और रबर की गोलियां दागी गईं।

अफगानिस्तान में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के दफ्तर पर हमला, एक मरा

काबुल, 28 जुलाई (एएफपी)।

अफगानिस्तान में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के कार्यालय को निशाना बनाकर रविवार को यहां एक हमला किया गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 13 अन्य घायल हो गए। यह हिंसा उसी दिन हुई जब सितंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए प्रचार अभियान शुरू हुआ है। पूर्व में भी चुनावों के दौरान हिंसा और रक्तपात हो चुका है।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी ने कहा कि हमला उत्तरी काबुल में ग्रीन ट्रेंड पार्टी के कार्यालय पर एक बम धमाके के साथ शुरू हुआ। इस पार्टी का नेतृत्व अमरुल्लाह सालेह करते हैं। रहीमी ने कहा, 'शाम करीब चार बजकर 40 मिनट पर पहले ग्रीन ट्रेंड कार्यालय के पास एक बम धमाका हुआ। इसके बाद कई हमलावर कार्यालय में घुस गए।' दो घंटे बाद भी हमला जारी था। उन्होंने कहा, 'सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा बल जितनी जल्दी हो सके हमलावरों को मारना चाहते हैं।' किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रहीमी ने कहा कि सालेह इस हमले में घायल नहीं हुए हैं। सालेह पूर्व में देश की खुफिया एजेंसी के प्रमुख के पद पर रह चुके हैं।

तालिबान ने सरकार के साथ सीधे समझौते की बात खारिज की

काबुल, 28 जुलाई। अफगानिस्तान के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि सरकार दो हफ्तों के अंदर तालिबान के साथ पहली सीधी वार्ता शुरू करेगी, लेकिन विद्रोहियों ने तत्काल ऐसी किसी मुलाकात की योजना को खारिज किया और जोर देकर कहा कि वे सरकारी प्रतिनिधियों से उनकी आधिकारिक क्षमता में बातचीत के खिलाफ है। **(एपी)**

संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी का झांसा देने वाले जालसाजों के खिलाफ चेताया

दुबई, 28 जुलाई (भाषा)।

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर लोगों को अबू धाबी में एक भारतीय स्कूल में नौकरी के जाली विज्ञापनों में न फंसने के लिए चेताया है।

मीडिया में आई खबर के अनुसार भारतीय दूतावास ने गुरुवार को ट्विटर पर दिए संदेश में संयुक्त अरब अमीरात, भारत और अन्य देशों में रह रहे भारतीयों से अनुरोध किया कि अगर ऐसे जालसाज उनसे संपर्क करने की कोशिश करें तो वे तुरंत इस मामले की शिकायत स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को दें। भारतीय दूतावास आए-दिन भारतीयों को लुभाने वाले नौकरी के जाली विज्ञापनों से बचने को लेकर नौकरी पाने वाले लोगों को आगाह करता रहता है। ताजा संदेश में दूतावास ने कहा कि उसे ड्यून्स इंटरनेशनल स्कूल ने सूचित किया कि कुछ जालसाज अपने आप को स्कूल के प्रतिनिधि और नियोक्ता बता रहे हैं और उसकी तरफ से नौकरी के फर्जी विज्ञापन दे रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों के जालसाजों के जाल में फंसने की खबरें आम है।

दक्षिण कोरिया समुद्री सीमा में दाखिल हुई उत्तर कोरियाई नौका

सियोल, 28 जुलाई (एएफपी)।

दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा में दाखिल हुई उत्तर कोरियाई नौका को पकड़ लिया गया और बंदरगाह ले जाया गया। इसमें चालक दल के तीन सदस्य भी थे। समाचार एजंसी 'योन्हप' ने दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हवाले से कहा कि शनिवार रात 11 बजकर 20 मिनट पर लकड़ी की नौका पूर्वी सागर (जापान सागर) में उत्तरी सीमा रेखा को पार कर गई। चालक दल के सदस्यों और नौका को जांच के लिए दक्षिण कोरियाई सैन्य बंदरगाह ले जाया गया है।

भारतीय रेत कलाकार अमेरिका में सम्मानित

न्यूयार्क, 28 जुलाई।

मशहूर भारतीय रेत कलाकार व पद्म पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक को अमेरिका में 'सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल' में 'पीपल्स च्वाइस अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन ने महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने संबंधी संदेश देते हुए रेत पर कलाकृति बनाई थी। बोस्टन में 'रिवीर बीच' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय 'सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल' 2019 में हिस्सा लेने के लिए विश्व भर से चुने गए 15 शीर्ष रेत कलाकारों में पटनायक भी थे।

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने 113 लोगों की जान ली

काठमांडो, 28 जुलाई (भाषा)।

नेपाल में मूसलाधार मानसूनी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से 113 लोगों की जान चली गई जबकि 38 लोग अब भी लापता हैं। काठमांडो घाटी के कुछ हिस्सों समेत मध्य और दक्षिणी नेपाल के कई इलाकों में बीते दो हफ्तों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पानी भरा हुआ है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि इस मानसून में कम से कम 113 लोगों की जान गई है जबकि 67 अन्य घायल हुए हैं।

नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञानी श्रिफर का देहांत

टालाहसी, 28 जुलाई (एपी)।

सुपरकंडिक्टिविटी की महत्त्वपूर्ण थ्योरी देने के लिए साल 1972 में भौतिकी विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जॉन रॉबर्ट श्रिफर का निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि श्रिफर का फ्लोरिडा के टालाहसी में शनिवार को एक नर्सिंग केंद्र में नींद में ही निधन हो गया। उनके परिवार में तीन बच्चे हैं। श्रिफर को जॉन बार्डीन और लियोन कूपर के साथ बीसीएस थ्योरी विकसित करने के लिए भौतिकी विज्ञान में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। यह सुपरकंडिक्टिविटी की पहली सफल माइक्रोस्कोपिक थ्योरी मानी जाती है। साल 2005 में उन्हें 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाकर एक व्यक्ति की हत्या करने और सात अन्य लोगों को घायल करने के जुर्म में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

खालिदा ने स्वास्थ्य आधार पर भ्रष्टाचार मामले में जमानत मांगी

ढाका, 28 जुलाई (भाषा)।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री व विपक्षी दल बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया ने रविवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्वास्थ्य के आधार पर जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत देने की मांग की है। इस मामले में उन्हें सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।

कश्मीर पर ट्रंप की पेशकश पाक की उम्मीदों से कहीं अधिक : कुरैशी

इस्लामाबाद, 28 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की वाशिंगटन की पहली यात्रा के दौरान कश्मीर पर मध्यस्थता की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश 'पाकिस्तान की उम्मीदों से कहीं अधिक' है।

सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि कुरैशी ने निजी समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री खान ने अमेरिका को इस बात पर सहमत किया कि कश्मीर मुख्य मुद्दा है, जिसका जल्द समाधान निकालने की जरूरत है। ट्रंप ने वाइट हाउस में खान के साथ पहली बैठक में गत सप्ताह कश्मीर मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बनने की पेशकश की थी। भारत ने सख्ती से ट्रंप की पेशकश को खारिज करते हुए कहा था कि भारत का लगातार यह रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय चर्चा ही होगी। कुरैशी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा मध्यस्थता की पेशकश किया जाना पाकिस्तान की उम्मीदों से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह बताया गया कि पाकिस्तान शांति प्रिय देश है और वह भारत समेत क्षेत्र में शांति चाहता है।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
मामले में
स्टार्टलिंग जीएमपी क्लीन रूम प्राईवेट लिमिटेड
CIN: U45500HR2017PTC067222,
कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय नं. 455, 4था तल, स्पेज आई-टेक पार्क, टावर बी-2, सेक्टर-49, सोहना रोड, गुड़गाँव, हरियाणा-122018, भारत में है
--आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 26 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार (शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में निहित) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में क्षेत्रीय निदेशक के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृते एवं के लिए
स्टार्टलिंग जीएमपी क्लीन रूम प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि: 29 जुलाई, 2019 विक्रम प्रधान (निदेशक)
स्थान: गुड़गाँव DIN: 08447117

KARVY FINANCE
कॉर्पोरेट कार्यालयः कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लि. 705/706, 7वाँ तल, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, संत दानेश्वर मार्ग, गुरु नानक हॉस्पीटल के सामने, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051
ई-मेलः abdullatif.patel@karvy.com
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम, 2002) के अंतर्गत कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.5.2019 जारी कर मै. श्री कृष्णम फूड्स, श्री राम पाल यादव, श्री राज पाल यादव एवं श्री मदन लाल यादव को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 23324420/- (रुपए दो करोड़ तैंतीस लाख चौबीस हजार चार सौ बीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 23 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 23324420/- तथा अनुबंध के अनुसार उस पर ब्याज की राशि के लिए कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लि. के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋण अनुबंध सं./ ऋणधारकों/ सह-ऋण-धारक का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	ली गई कब्जा की तिथि एवं प्रकार	अचल सम्पत्तियों का विवरण
1.	ऋण अनुबंध सं. 7005501 1. मै. श्री कृष्णम फूड्स (आवेदक) मकान सं. 642, सेक्टर 10 ए, गुरुग्राम, हरियाणा, पिनकोड-122001 1. क. मै. श्री कृष्णम फूड्स (आवेदक) नाथू स्वीट्स, पटौदी रोड, कादीपुर गाँव, सेक्टर 10 ए के निकट, गुरुग्राम, हरियाणा, पिनकोड-122001 2. श्री राम पाल यादव (सह आवेदक) मकान सं. 642, सेक्टर 10 ए, गुरुग्राम, हरियाणा, पिनकोड-122001 2. क. श्री राम पाल यादव (सह आवेदक) नाथू स्वीट्स, पटौदी रोड, कादीपुर गाँव, सेक्टर 10 ए के निकट, गुरुग्राम, हरियाणा, पिनकोड-122001 3. श्री राज पाल यादव (सह आवेदक) मकान सं. 642, सेक्टर 10 ए, गुरुग्राम, हरियाणा, पिनकोड-122001 4. श्री मदन लाल यादव (सह आवेदक) मकान सं. 642, सेक्टर 10 ए, गुरुग्राम, हरियाणा, पिनकोड-122001 5. प्रोमिला यादव (सह आवेदक) मकान सं. 642, सेक्टर 10 ए, गुरुग्राम, हरियाणा, पिनकोड-122001	3 मई, 2019 एवं रु. 23324420/- (रुपए दो करोड़ तैंतीस लाख चौबीस हजार चार सौ बीस मात्र)	23.7.2019 (सांकेतिक कब्जा)	सम्पत्ति प्लॉट नं. 642-पी, सेक्टर 10 ए, माप 297 वर्ग मी. जो आवासीय कॉलोनी "अर्बण इस्टेट" के नाम से विदित, गुरुग्राम, हरियाणा, पिनकोड-122001 में स्थित है, का सभी भाग तथा हिस्सा।

स्थानः दिल्ली
तिथिः 29.07.2019
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये

CORAL NEWSPRINTS LTD.
Regd. Office : A-138, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092
CIN NO : L22219DL1992PLC048398, E-mail: cnpl_5000@rediffmail.com
Website : www.coralnewsprintslimited.com, Tel. : 22010998
Annexure XI
Abstract of Un-audited Financial Result (Standalone) for the quarter & year ended on 30.06.2019
(Rs. in lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2019 Unaudited	Year to date Figures 31.03.2019 Audited	Quarter ended 31.12.2018 Unaudited
1.	Total income from operations (net)	303.92	1598.61	368.89
2.	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(28.33)	(60.51)	(8.02)
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(28.33)	(60.51)	(8.02)
4.	Equity Share Capital	505.27	505.27	505.27
5.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	(798.73)	(770.40)	(717.94)
6.	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)			
	Basic :	(0.56)	(1.20)	(0.16)
	Diluted :	(0.56)	(1.20)	(0.16)
7.	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)			
	Basic :	(0.56)	(1.20)	(0.16)
	Diluted :	(0.56)	(1.20)	(0.16)

Note : The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on Company's website at www.coralnewsprintslimited.com

By Order of the Board
For Coral Newsprints Ltd.
(Sd./-)
Dated : 27.07.2019 (Pushpendra P.S.Chauhan)
Place : Delhi Whole Time Director & CEO, (DIN No : 01871760)

प्रपत्र ए - सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	17 मई, 2000
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली के पास कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U72200DL2000PTC105754
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत पताः डी-3, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली 110017 कॉर्पोरेट पताः प्रियस ग्लोबल, छठा तल, प्लॉट नं.-3, 4 एवं 5, सेक्टर-125, गौतम बुध नगर, नोएडा-201301
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	25 जुलाई, 2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	21 जनवरी, 2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के रूप में कार्यरत है	महेन्दर खण्डेलवाल आईपी पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का पता एवं ईमेलः	पताः बी-2ए, सन्नी वैल्ली सीजीएचएस, प्लॉट नं. 27, सेक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली-110078 ई-मेलः mahender.khandelwal@pwc.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्रा.लि., प्लॉट # वाई-14, ब्लॉक ईपी, सेक्टर V, साल्ट लेक, कोलकाता-700 091 ईमेलः claims.pr@in.pwc.com, ip.m.pr@in.pwc.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	8 अगस्त, 2018
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, दिल्ली ने 25 जुलाई, 2019 को एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के पास 8 अगस्त, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।
दावे का प्रमाण भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 ("सीआईआरपी विनियमन") के चैप्टर IV के अनुसार जमा किया जा सकता है। दावे सीआईआरपी विनियमनों के अनुसार अधोलिखित विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किये जा सकते हैं। ● प्रपत्र बी- ऑपरेशनल क्रेडीटर द्वारा दावे ● प्रपत्र सी-वित्तीय क्रेडीटर्स द्वारा दावे ● प्रपत्र डी- कर्मियों/कर्मचारी द्वारा दावे ● प्रपत्र ई- कर्मियों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि द्वारा दावे ● प्रपत्र एफ- क्रेडीटरों (वित्तीय क्रेडीटरों तथा ऑपरेशनल क्रेडीटरों के अतिरिक्त) द्वारा दावे। प्रपत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए आप वेबसाईटः www.ibbi.gov.in (http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html) तथा सीआईआरपी विनियमनों से ऊपर वर्णित प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
महेन्दर खण्डेलवाल
29 जुलाई, 2019 एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल
दिल्ली IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

प्रपत्र ए - सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
पायने रीअल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	पायने रीअल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	18 फरवरी, 2002
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली के पास कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U45200DL2008PTC174167
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत पताः डी-3, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली 110017 कॉर्पोरेट पताः प्रियस ग्लोबल, छठा तल, प्लॉट नं.-3, 4 एवं 5, सेक्टर-125, गौतम बुध नगर, नोएडा-201301
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	25 जुलाई, 2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	21 जनवरी, 2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के रूप में कार्यरत है	महेन्दर खण्डेलवाल आईपी पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का पता एवं ईमेलः	पताः बी-2ए, सन्नी वैल्ली सीजीएचएस, प्लॉट नं. 27, सेक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली-110078 ई-मेलः mahender.khandelwal@pwc.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्रा.लि., प्लॉट # वाई-14, ब्लॉक ईपी, सेक्टर V, साल्ट लेक, कोलकाता-700 091 ईमेलः claims.pr@in.pwc.com, ip.m.pr@in.pwc.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	8 अगस्त, 2018
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, दिल्ली ने 25 जुलाई, 2019 को पायने रीअल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा पायने रीअल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के पास 8 अगस्त, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।
दावे का प्रमाण भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 ("सीआईआरपी विनियमन") के चैप्टर IV के अनुसार जमा किया जा सकता है। दावे सीआईआरपी विनियमनों के अनुसार अधोलिखित विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किये जा सकते हैं। ● प्रपत्र बी- ऑपरेशनल क्रेडीटर द्वारा दावे ● प्रपत्र सी-वित्तीय क्रेडीटर्स द्वारा दावे ● प्रपत्र डी- कर्मियों/कर्मचारी द्वारा दावे ● प्रपत्र ई- कर्मियों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि द्वारा दावे ● प्रपत्र एफ- क्रेडीटरों (वित्तीय क्रेडीटरों तथा ऑपरेशनल क्रेडीटरों के अतिरिक्त) द्वारा दावे। प्रपत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए आप वेबसाईटः www.ibbi.gov.in (http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html) तथा सीआईआरपी विनियमनों से ऊपर वर्णित प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
महेन्दर खण्डेलवाल
29 जुलाई, 2019 पायने रीअल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल
दिल्ली IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}
श्री राज महल ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड के संभावित प्रस्ताव आवेदकों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	श्री राज महल ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	12.05.2019
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U36103DL2009PTC190236
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः शॉप नं. 1 एवं 2, निम्न भूतल, 2678, डॉयमंड मॉल, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	24.04.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	29.7.2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	विवरण cirp.rajmal@outlook.in पर ई-मेल भेज कर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही वह कॉर्पोरेट ऋणधारक की वेबसाईट www.shreerajmahaljewellers.in पर भी उपलब्ध है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	आईबीबीआई की वेबसाईट (www.ibbi.gov.in) पर उपलब्ध अथवा cirp.rajmahal@outlook.in पर ईमेल भेज कर मांगी जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	132.08.2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	20.08.2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	22.8.2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	22.08.2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	24.08.2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	विवरण cirp.rajmahal@outlook.in पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	24.09.2019
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	cirp.rajmahal@outlook.in पर मेल करें।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव योजना जमा करने की अनुमानित तिथि	10.10.2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	निशांत गौरव गुप्ता IBBI/IPA-002/IP-N00572/2017-18/11739
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	निशांत गौरव गुप्ता "सिद्धांत एडवोकेट्स" फ्लैट नं. 542, 1ला तल, डीडीए, एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर-22, पॉकेट-1, द्वारका, सेक्टर-22, नई दिल्ली-110077, ई-मेलः nishantgaurav@outlook.in
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	पताः जैसा कि उपर है ई-मेलः cirp.rajmahal@outlook.in
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	विवरण cirp.rajmahal@outlook.in पर ईमेल भेजकर मांगी जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	29.7.2019

निशांत गौरव गुप्ता
IBBI/IPA-002/IP-N00572/2017-18/11739
तिथिः 27.7.2019 श्री राज महल ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड के लिए रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल
स्थानः नई दिल्ली आईबीबीआई में पंजीकृत पताः फ्लैट नं. 542, 1ला तल, डीडीए, एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर-22, पॉकेट-1, द्वारका, सेक्टर-22, नई दिल्ली-110077, ई-मेलः nishantgaurav@outlook.in

5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का रास्ता भी यूपी से : शाह

लखनऊ, 28 जुलाई (जनसत्ता/भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उसी तरह भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग भी उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है।

शाह ने यहां दूसरी 'ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी' में 65 हजार करोड़ रुपए की 250 से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद कहा, मैं जब 16 साल का था तब से सुनता हूं कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। मैं आज कहना चाहता हूं कि पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का रास्ता भी लखनऊ से ही होकर जाता है।

मैं आश्वस्त हूं कि उत्तर प्रदेश एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर इसमें अपना योगदान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं को धरातल पर लाने का काम हो रहा है। एक साल के अंदर एक लाख 20 हजार करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारना बहुत बड़ा काम है।

शाह ने प्रदेश में प्रशासन को राजनीतिकरण से दूर रखे जाने को सूबे में आए मूलभूत परिवर्तन की नींव करार देते हुए कहा, पिछली सरकारों में प्रशासन का इस कदर राजनीतिकरण हुआ कि पारदर्शिता दूर-दूर तक नहीं रह गई थी। 14वें वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को मिलने वाली धनराशि तीन लाख 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 8 लाख 80 हजार करोड़ रुपए कर दी। राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं हाथ में ली हैं, उनका परिपूर्ण होना तय है और प्रदेश में बदलाव आना भी सुनिश्चित है। आने वाले दिनों में यहां चमत्कारिक प्रदर्शन होगा। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा।

मैं जब 16 साल का था तब से सुनता हूं कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। मैं आज कहना चाहता हूं कि पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का रास्ता भी लखनऊ से ही होकर जाता है। मैं आश्वस्त हूं कि उत्तर प्रदेश एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर इसमें अपना योगदान सुनिश्चित करेगा।

शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा, जब योगी को उत्तर प्रदेश की कमान देने का फैसला किया गया तो बहुत सवाल उठे थे। किसी ने कहा कि योगी ने कभी नगर निगम तक का प्रशासन नहीं संभाला तो वह इतना बड़ा प्रदेश कैसे चलाएंगे।

मगर भाजपा ने निष्ठा और परिश्रम करने की क्षमता को मानक बनाकर उत्तर प्रदेश का भविष्य योगी आदित्यनाथ के हाथ सौंपा। योगी ने प्रदेश के 22 करोड़ लोगों में यह आत्मविश्वास जगाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश भी देश में सर्वोत्तम प्रदेश बन सकता है। मैं आज बड़े संतोष से कह सकता हूं कि हमारा निर्णय उचित था।

गृह मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, मोदी खुली आंख से सपने देखने की आदत रखते हैं। जो ऐसे ख्वाब देखते हैं उनको तब तक नींद नहीं आती जब तक सपना साकार नहीं होता। आज प्रधानमंत्री के पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के संकल्प पर टीका टिप्पणी हो रही है। मगर 2014 से 2019 तक के कार्यकाल में वह इसकी बुनियाद रख चुके हैं। पांच साल में देश की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, उसे देखने से इसका अंदाजा भी लग जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का कार्यकाल खत्म होने के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत 11वें स्थान पर था। उसके बाद 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार चली, मगर कोई सुधार नहीं हुआ।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन सूचना
टी. ए. सं0. 06 वर्ष 2018 में
(पुराना ओ. ए. सं0 1096/2015 डीआरटी, लखनऊ)

(ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावलीए 1993, समय–समय पर संशोधितानुसार की नियमावली के उप–नियम (2ए) धारा 5 के साथ पठित ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत सम्मन)

डायरी संख्या 105 — दिनांक : 24/07/2019

केनरा बैंक बनाम मैसर्स भारत ब्रिक फील्ड व अन्य

1. मैसर्स भारत ब्रिक फील्ड, ग्राम–अंबेहटा मोहन, तहसील–देवबंद जिला– सहारनपुर, यूपी अपने भागीदारों के माध्यम से।
2. जाहिदा बेगम पत्नि श्री [illegible] अली [illegible], निवासी [illegible] [illegible], पोस्ट– थाना भवन, तहसील– कैराना, जिला– मुजफ्फर नगर, यूपी।
3. सुजात खान पुत्र श्री [illegible] अली खान निवासी [illegible], पोस्ट– थाना भवन, तहसील– कैराना, जिला– मुजफ्फर नगर, यूपी।
4. [illegible] पुत्र श्री लतीफ, निवासी ग्राम–अंबेहटा मोहन, तहसील–देवबंद जिला–सहारनपुर, यूपी

सूचित हो कि ओ.ए. सं0 1096/2015 [illegible] रिकवरी ट्रिब्यूनल, लखनऊ से पहले लंबित था, जिसके लिए आप आवेदक बैंक द्वारा दायर किए गए 32,33,995/– के ऋणों की वसूली के लिए लखनऊ, जिसे ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था [illegible] अधिसूचना के माध्यम से 18 फरवरी 2017 एस.ओ. 454 (ई) दिनांक 15.02.2017, एस.ओ. 784 (ई) दिनांक 23.02.2018 और शुद्धिपत्र राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 816 (ई) दिनांक 27.02.2018। उपर्युक्त [illegible] मामले को टी.ए. सं 06/2019 के रूप में फिर से क्रमांकित किया गया था। माननीय पीठ अधिकारी के समक्ष दिनांक 24.04.2019 को सूचीबद्ध किया गया था।

यह कि न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण प्रक्रिया द्वारा सूचना देना संभव नहीं है अतः इस प्रकाशन द्वारा आपको दिनांक 07.09.2019 को प्रातः 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता अथवा लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

सूचित हो कि विनिर्दिष्ट तिथि और समय पर उपस्थित होने में आपकी चूक की स्थिति में वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 24 जुलाई 2019 दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालय: डीडीए बिल्डिंग, विकास मिनार, निकट आई.टी.ओ. नई दिल्ली

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गांरटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
1.	**कर्जदार:** **ओम शिव ट्रेडर्स** 71, सेक्टर–21बी, फरीदाबाद, हरियाणा–121001	श्रीमती सरला गर्ग पत्नी श्री मोहन लाल गर्ग के नाम पर लोहिया नगर जी.डी.ए. आवासीय कॉलोनी, गाजियाबाद में स्थित साम्यिक बंधक सम्पत्ति सं. सी–234, एल.आई.जी., एरिया परिमाप 120.96 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 50.72 वर्ग मीटर एव खुला एरिया 70.24 वर्ग मीटर जो निम्नानुसार घिरा है: पूर्व: रोड 9.15 मीटर चौड़ी, पश्चिम: मकान नं. सी–200, उत्तर: मकान नं. सी–235, दक्षिण: मकान नं. सी–233	30.07.2018 को एनपीए 26.06.2019 को बकाया रु.45,57,286/– (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है) भविष्य के ब्याज कानूनी शुल्क एवं वसूली शुल्क आदि सहित।
2.	**कर्जदार:** **संगीता चौहान पुत्र मानक मोती** सी–11, दूसरी मंजिल, हाज़रा पार्क, कृष्णा नगर दिल्ली–110051	**संगीता चौहान** के नाम पर गांव खुरेजी खास, हजरा पार्क की आबादी, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110051 में स्थित साम्यिक बंधक सम्पत्ति सम्पूर्ण द्वितीय तल बिना छत अधिकार, सम्पत्ति सं. सी–11, खसरा न. 15/33 का भाग, सम्पत्ति का एरिया–102 वर्ग यार्ड जो घिरा है: उत्तर: अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति, पूर्व: अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम: रोड	29.04.2019 को एनपीए 06.07.2019 को बकाया रु.7,24,103/– (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है) भविष्य के ब्याज कानूनी शुल्क एवं वसूली शुल्क आदि सहित।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

कृपया नोट करें कि इस सूचना से पूर्व वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत जारी सभी सूचनाएं निरस्त की जाती हैं।

स्थान: फरीदाबाद / दिल्ली
दिनांक: 28.07.2019

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास मिनार, नई दिल्ली

Gujchem Distillers India Limited
(Corporate Identification Number: L24230GJ1939PLC002480)
Registered Office: Office No. 6, 2nd Floor, National Chambers, Nr. City Gold, Ashram Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India.
Tel. No. +91-79- 26580893, **Email:** gujchemdistillers@gmail.com; **Web:** www.gujchemdistillers.com

Recommendation of the Committee of Independent Directors ("IDC") on the Open Offer to the shareholders of Gujchem Distillers India Limited (the 'Target Company' or "TC") by Mr. Sagar Samir Shah ("Acquirer 1") and Mrs. Rajasvee Sagar Shah ("Acquirer 2") (Acquirer 1 and Acquirer 2 are jointly referred to as the "Acquirers") for acquiring of 42,091 fully paid-up Equity Shares of Rs.10/- each, constituting 26% of the Equity Share and Voting Capital of Target Company under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto [the 'SEBI (SAST) Regulations'].

1.	Date	**July 26, 2019**
2.	Name of the Target Company (TC)	**Gujchem Distillers India Limited ("TC")**
3.	Details of the Offer pertaining to TC	The Open Offer is being made by the Acquirers to the shareholders of the TC, for acquisition of upto 42,091 fully paid-up Equity Shares of the face value of Rs. 10/- each, constituting 26% of the Equity Share Capital and Voting Capital, at a price of Rs. 120/- (Rupees One Hundred and Twenty only) per share in terms of Regulations 3(1) & 4 of SEBI (SAST) Regulations.
4.	Name(s) of the acquirer with the acquirer	• Mr. Sagar Samir Shah ("Acquirer 1") • Mrs. Rajasvee Sagar Shah ("Acquirer 2")
5.	Name of the Manager to the offer	**Systematix Corporate Services Limited** SEBI Registration No. INM 000004224 The Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606, Plot No. C-70, G - Block, Bandra-Kurla Complex (BKC), Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India. Tel. No. +91-22-6704 8000; Fax No. +91-22-6704 8022 Email: investor@systematixgroup.in Website: www.systematixgroup.in
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	• Shri Tapan Chokshi • Smt. Sachi Parikh Shri Tapan Chokshi is the Chairperson of the Committee of Independent Directors ("IDC").
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	All the IDC Members are Independent & Non-Executive Directors of the TC. They do not have any contractual relationship with the TC. Smt. Sachi Parikh is holding 2 equity shares in the Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC Members have done any trading in Equity Shares / Other securities of the TC since their appointment as Director.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirers.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	IDC is of the opinion that the offer is fair and reasonable on the date of the Public Announcement ("PA"). IDC also draws attention of public shareholders to the current share price which has exceeded the open offer price after the PA date. The shareholders may therefore independently evaluate the offer and take an informed decision in the best of their interests.
12.	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	IDC has evaluated the Public Announcement ("**PA**"), Detailed Public Statement ("**DPS**"), Draft Letter of Offer ("**DLOF**") and Corrigendum released by Systematix Corporate Services Limited (Manager to the Offer) for and on behalf of Acquirers. Based on the above, the IDC is of the opinion that the Offer Price, being offered by the Acquirers, of Rs. 120/- per fully paid-up Equity Share is fair and reasonable and recommends the acceptance of the Open Offer, in the light of the following: • The shares are frequently traded on the stock exchange. • The Offer Price offered by the Acquirers is in line with the regulation prescribed by SEBI under the SEBI (SAST) Regulations and prima facie appears to be justified. However, it is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer vis-à-vis current share price and take an informed decision before participating in the Offer.
13.	Details of Independent Advisors, if any.	Nil
14.	Any other matter(s) to be highlighted	Nil

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of Committee of Independent Directors of Gujchem Distillers India Limited
Sd/-
Tapan Chokshi
Chairman of Committee of Independent Directors
Place: Ahmedabad
Date: July 26, 2019

शीला फोम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : सी– 55, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली–110092
कॉर्पोरेट कार्यालय: 37/2, साईट IV, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, यू.पी. 201010
फोन: +91-120-4162200 सीआईएन: L74899DL1971PLC005679
वेबसाइट: www.sheelafoam.com ई–मेल: iquebal.ahmad@sheelafoam.com

सूचना

सेबी (लिस्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियमन 47 के साथ 29 नियम, एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक अन्य विषयों के साथ – साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक **अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों** पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदित करने के लिए दिनांक **06 अगस्त, 2019 दिन मंगलवार** को आयोजित की जाएगी।

कृते शीला फोम लिमिटेड
हस्ता/–
(मो. इकबाल अहमद)
कंपनी सचिव

स्थान : नौएडा
दिनांक : 26 जुलाई, 2019

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राईजेज लिमिटेड
(भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व के अधीन सहायक कंपनी)
(भारत सरकार का उपक्रम, रेलवे मंत्रालय के अधीन)
सीए स्टोर, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, राई, जिला सोनीपत, हरियाणा, पिन–131029
फोन: 918971882819 फैक्स: 91130.2366887
कॉनकॉर CONCOR

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

एफएचईएल निम्नलिखित कार्य के लिए टेंडरिंग के एकल पैकेट सिस्टम में ई–निविदा आमंत्रित करता है:

ई–निविदा सूचना सं	एफ एंड एच/08–टी/133/2019 दिनांक: 26.07.2019
कार्य का नाम	एफएचईएल, राई, सोनीपत, हरियाणा में 12,000 एमटी एग्री लॉजिस्टिक सेंटर का प्रचालन एवं रखरखाव।
अनुमानित लागत	रु. 38,73,805/–लाख
पूर्णता अवधि	12 (बारह) माह
धरोहर जमा राशि	रु. 77,500/– (सतहत्तर हजार पांच सौ रुपए) ई–भुगतान (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से
निविदा दस्तावेज की लागत (अ–प्रतिदेय)	रु. 1000/–सभी करों एवं प्रभारों सहित ई–भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अ–प्रतिदेय)	रु. 2,286/–सभी करों एवं प्रभारों सहित ई–भुगतान के माध्यम से
निविदा बिक्री तिथि (ऑनलाइन)	29.07.2019, 15.00 बजे से 19.08.2019 16.00 बजे तक
निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	20.08.2019 को 1600 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	21.08.2019 को 1200 बजे

विस्तृत योग्यता मानदंड, समान प्रकार के कार्य आदि के संबंध में अनुभव एवं कार्य के पूर्ण विवरण आदि के लिए कृपया वेबसाइट www.concorindia.com पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना का अवलोकन करें, लेकिन पूर्ण निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/FHEL से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा का आगे शुद्धि/परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे केवल वेबसाइट concorindia.com, www.tenderwizard.com/FHEL और सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
फोन नं. 011–41673093–96

फॉक्सग्लोव बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: जे–154, पहली मंजिल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027
ईमेल आईडी: mittalassociates@live.com **CIN No.:** U72900DL2017PTC322307

प्ररूप– आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में
और
फॉक्सग्लोव बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय जे–154, पहली मंजिल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 में स्थित है के मामले में
...आवेदक

[illegible]

पंजीकृत कार्यालय जे–154, पहली मंजिल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027

कृते और फॉक्सग्लोव बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से
हस्ता/–
मोहम्मद नबी शरीफ
निदेशक (DIN NO : 08461075)
आशियाना सीएचएस, बिल्डिंग नं. सी–1, फ्लैट नं. 302, मैथकन नगर, नियर मारोल फायर ब्रिगेड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400069

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29.07.2019

यूपी में हजारों करोड़ का निवेश करेंगे उद्योग जगत के दिग्गज

लखनऊ, 28 जुलाई (भाषा)।

उद्योग जगत की हस्तियों ने उत्तर प्रदेश को निवेश का पसंदीदा स्थल बताते हुए आने वाले समय में बड़ी परियोजनाओं के साथ राज्य में हजारों करोड़ रुपए के निवेश का एलान किया। उद्योग जगत की नामचीन हस्तियां रविवार को यहां दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रही थीं।

टोरंट की गैस पाइप लाइन नेटवर्क पर 3000 करोड़ के निवेश की योजना : बिजली व दवा कारोबार से जुड़े टोरंट समूह का प्रदेश में गैस पाइप लाइन नेटवर्क बिछाने के लिए 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। इसके अलावा 200 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने पर भी विचार हो रहा है। समूह के अध्यक्ष सुधीर मेहता ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी घरेलू, वाणिज्यिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए मजबूत और बेहद व्यापक गैस पाइप लाइन नेटवर्क बिछाने के काम में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा– साथ ही प्रदेश में 200 सीएनजी स्टेशन बनाने पर भी विचार हो रहा है। इस निवेश से प्रदेश के लोगों को आसानी से गैस उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में हम बिजली वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए भी निवेश के इच्छुक हैं। टोरंट समूह ने फरवरी 2018 में हुए निवेशक शिखर सम्मेलन में बिजली और गैस वितरण क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इनमें से 3000 करोड़ की परियोजनाएं बहुत कम समय में शुरू हो रही हैं।

अडाणी समूह करेगा 5,500 करोड़ रुपए का निवेश: अडाणी समूह उत्तर प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए के नए निवेश की योजना बना रहा है। समूह के अध्यक्ष गौतम अडाणी ने यहां दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मौके पर कहा कि फरवरी, 2018 में लखनऊ में हुए निवेशक सम्मेलन में अडाणी समूह ने उत्तर प्रदेश में बिजली पारेषण के क्षेत्र में पांच हजार करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। हमने दो पारेषण परियोजनाओं पर पहले ही काम शुरू कर दिया है। अगले पांच वर्षों में बिजली पारेक्षण क्षेत्र में हम पांच हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हम प्रदेश में 500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रहे हैं। इस निवेश से चावल मिल, आटा मिल, दाल मिल और कच्ची घानी रिफाइनिंग के कारखाने लगाए जाएंगे।

अडाणी ने कहा कि हम डेटा सेंटर और रक्षा जैसे नए युग के क्षेत्रों में भी बेहतर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के आकार, रणनीतिक स्थिति और आबादी को देखते हुए हमें उम्मीद है कि यह राज्य इन दोनों क्षेत्रों में अग्रणी बन सकता है। रक्षा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद महत्त्वपूर्ण है। हमारा सपना है कि अडाणी ग्रुप उत्तर प्रदेश के रक्षा कॉरिडोर में विश्व स्तरीय विनिर्माण हब का निर्माण करे। उन्होंने कहा कि अडाणी समूह ने उत्तर प्रदेश में अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ाने में मदद के लिए धमौरा और कन्नौज में 15 हजार टन क्षमता वाली इकाइयां बनाई हैं। भारत के अंतरदेशाय जलमार्गों की क्षमता में वृद्धि में मदद के लिए अडाणी ने वाराणसी में मल्टी मोडल रिवर टर्मिनल विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है। अडाणी ने कहा कि भारत की कामयाबी की कहानी उत्तर प्रदेश के बिना अधूरी है। हम उत्तर प्रदेश को तेजी से बदलते राज्य के तौर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बेहद अहम होगी।

लुलु समूह लगाएगा खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र: संयुक्त अरब अमीरात का कारोबारी समूह लुलु समूह उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र लगाने पर विचार कर रहा है। समूह ने कहा कि लखनऊ में बन रहा उत्तर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जल्द ही खुल जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। लुलु समूह के अध्यक्ष यूसुफ अली ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी–2 के मौके पर कहा कि समूह की दिल्ली से सटे साहिबाबाद में एक शॉपिंग मॉल बनाने की भी योजना है। उन्होंने कहा– हम लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। इससे पांच हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 10,000 से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसका 70 फीसद निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दो और मॉल बनाए जाएंगे। इनमें से एक वाराणसी और दूसरा नोएडा में बनाया जाएगा। इनका खाका तैयार हो चुका है और निर्माण कार्य शुरू होने वाला है।

टाटा संस जारी रखेगा अपना अपना विस्तार : टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्त्वपूर्ण राज्य है। हमारी सभी रिटेल कंपनियों की यहां मौजूदगी है। उन्होंने कहा कि एक कारोबारी समूह के तौर पर हम प्रदेश में असीम संभावनाएं देखते हैं। चाहे वह अक्षय ऊर्जा का क्षेत्र हो, पर्यटन हो, एअरलाइंस हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हम सब को बड़े मौके के तौर पर देखते हैं। मुझे खुशी है कि हम उत्तर प्रदेश में अपने विस्तार को जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा, सैमसंग इंडिया के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एचसी हांग ने घोषणा की कि नोएडा स्थित सैमसंग के कारखाने को निर्यात केंद्र में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्यबल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इसलिए उत्पादन की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा गंतव्य प्रदेश है।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
ओ.बी.सी. लार्ज कॉरपोरेट शाखा, प्रथम तल, हर्षा भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन: 011-49191101,49191134,49191135,49191139, फैक्स: (011) 23417236

ई–नीलामी बिक्री सूचना

चल एवं अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना ईएमडी (धरोहर जमा राशि) तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 30.08.2019 को सांय 4.00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 (2002 की सं. 54) के अधीन बैंक के पास बंधक पड़ी चल एवं अचल सम्पत्ति की बिक्री, जैसाकि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक की बकाया राशि की वसूली हेतु "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" उसको बेचने के अधिकार के साथ हमारी शाखाओं के पास निम्नलिखित ऋण खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन जारी की गयी सूचना के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। इसकी बिक्री वेब साईट: www.bankeauctionwizard.com में प्रदान किये गये ई–नीलामी लिंक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण

कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण (उपलब्ध विवरणानुसार)	कुल आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई–नीलामी की तारीख/समय	सम्पत्ति की निरीक्षण की तिथि एवं समय	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण
मैसर्स लालसन्स ज्वेल्स लि. (कर्जदार), निदेशक/गारंटर, संजीव पॉल सिंह उर्फ श्रीमती पूनम वर्मा, श्री संजीव पॉल सिंह वर्मा गारंटर, श्री के.आर. वर्मा एवं श्रीमती राजदुलारी वर्मा, मैसर्स आर. सलिक एण्ड क. प्रा. लि. (कार्पोरेट गारंटर)	**चल सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य:** रु. 0.81 करोड़ 1. Silver utensils & Articles 2. Fancy Jewelry 3. Diamond Articles 4. Gold Articles Etc. **अचल सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य:** रु. 13.72 करोड़ Immovable Plot No. 6, Block 23-B, WEA, New Rohtak Road, New Delhi	₹ 14.53 करोड़ / ₹ 1.46 करोड़ / ₹ 2.00 लाख	02-09-2019 दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	17-08-2019 पूर्वा. 11.00 से अपराह्न 4.30 बजे के बीच	04-11-2016 / ₹ 185,09,95,915/- (रु. एक सौ पिचासी करोड़ नौ लाख पिच्यान्वे हजार नौ सौ पंद्रह मात्र) दिनांक 31.10.2016 तक और प्लस दिनांक 01.11.2016 से भविष्य के ब्याज और सहायक व्यय इत्यादि सहित	00071182000031 E-auction under SARFAESI A/C Lalsons Jewellers Ltd IFSC Code ORBC0100007

नियम व शर्तें

1. ई–नीलामी दिनांक 02.09.2019 को दोपहर 12.00 से 1.00 बजे अपराह्न 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. ऊपर वर्णित चल और अचल संपत्तियों की नीलामी हेतु एकल या संयुक्त ईएमडी / बोली राशि होगी।
3. उपरोक्त सम्पत्तियों हेतु धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 30.08.2019 को सांय 4.00 बजे तक है।
4. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर [illegible]
5. रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त सभी अचल सम्पत्ति फ्री होल्ड सम्पत्ति है।
6. [illegible] अन्तारेस सिस्टम लि. [illegible] श्री [illegible], मो. 9555926408, श्री सुशील बोस, मो. 7686913157, [illegible] 7503347659, sachin@antaressystems.com, pushpraj@antaressystems.com [illegible] श्री विजय बिहारी प्रसाद, मुख्य प्रबंधक, 011-49191121, श्री एस एस फिलिप, (प्राधिकृत अधिकारी), श्रीमती [illegible] गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, 011-49191125/27/36, ई–मेल: bm0007@obc.co.in [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

(विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया हमारी वेबसाइट: www.obcindia.co.in और www.bankeauctionwizard.com देखें)

दिनांक 29.07.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन अक्तूबर में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रोद्यौगिकी और कानून व न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आइएमसी 2019) के तीसरे संस्करण का एलान किया। इसका आयोजन राजधानी के एरोसिटी में 14–16 अक्तूबर तक किया जाएगा।

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि आइएमसी एक सालाना कार्यक्रम है जिसमें भारत की शीर्ष दूरसंचार एवं डिजिटल प्रोद्यौगिकी कंपनियां हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कहा कि मैं उद्योग जगत के दिग्गजों, ब्रांड्स, इनोवेटर्स, अकादमिक प्रतिनिधियों और नीति निमार्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे आइएमसी में हिस्सा लेकर इसे एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो बनाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों के साथ डिजिटल इंडिया का उत्सव मनाने वाला यह कार्यक्रम जबरदस्त सफलता हासिल करेगा। इस मौके पर संचार मंत्रालय की सचिव अरुणा सुंदरराजन और अपर सचिव अंशु प्रकाश और सेलुलर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन (सीओएआइ) के महानिदेशक राजन मैथ्यूज उपस्थित थे।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी का निधन

हैदराबाद/नई दिल्ली 28 जुलाई (जनसत्ता/भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी का शनिवार देर रात हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। कांग्रेस के एक नेता ने एजंसी को बताया कि रेड्डी को हाल में निमोनिया हुआ था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां देर रात एक बजकर 28 मिनट पर उनका देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को होगा।

रेड्डी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। कोविंद ने ट्वीट किया, पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। वह एक विचारशील नेता और उत्कृष्ट सांसद थे। उनके परिवार और उनके अनेक सहयोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। नायडू ने कहा कि रेड्डी चार दशक से उनके निकट मित्र थे और आंध्र प्रदेश विधानसभा में वे अगल-बगल बैठा करते थे। उपराष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा, वह शानदार वक्ता थे। उन्हें 1998 में 'उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार' से नवाजा गया था। तीक्ष्ण बुद्धि के धनी और हाजिर जवाब रेड्डी अपनी पार्टी के एक प्रभावशाली प्रवक्ता थे।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जताया शोक

रेड्डी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। वह एक विचारशील नेता और उत्कृष्ट सांसद थे : कोविंद

जयपाल रेड्डी को सार्वजनिक जीवन का वर्षों का अनुभव था। स्पष्ट वक्ता और प्रभावी प्रशासक के रूप में उनका सम्मान किया जाता था। उनके निधन से दुखी हूं : मोदी

जयपाल रेड्डी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड्डी के निधन पर रविवार को शोक जताया और उन्हें प्रभावी प्रशासक बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मोदी के हवाले से ट्वीट किया, जयपाल रेड्डी को सार्वजनिक जीवन का वर्षों का अनुभव था। स्पष्ट वक्ता और प्रभावी प्रशासक के रूप में उनका सम्मान किया जाता था। उनके निधन से दुखी हूं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें बेहतरीन सांसद और तेलंगाना का महान पुत्र करार दिया। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेड्डी को बुद्धिमत्ता और ज्ञान का खजाना बताया। सिंह ने कहा, अपने मित्र और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी के असमय निधन से बेहद दुखी हूं। वह बुद्धिमत्ता और ज्ञान का खजाना थे। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। उन्होंने कहा, बेहतरीन सांसद, तेलंगाना के महान पुत्र, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा में समर्पित कर दिया। उनके परिवार और दोस्तों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कहा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी के निधन की खबर सुनकर हम बेहद दुखी हैं। वह पांच बार लोकसभा सांसद, दो बार राज्यसभा के सदस्य और चार बार विधायक रहे। हम उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार और दोस्तों को दुख की इस घड़ी से उबरने की शक्ति मिलेगी।

पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि वह रेड्डी के निधन से काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कहे या लिखे हर शब्द में गहरी विद्वता और एक जुनून था जो असाधारण था। उन्होंने पुराने मूल्यों और नई दुनिया की तकनीकों को सहजता से जोड़ा।

आइएमए ने आज अस्पताल बंद रखने का किया आह्वान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली ,28 जुलाई।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के तमाम प्रावधानों को गरीब विरोधी बताते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने इसके खिलाफ सोमवार को देशभर में सरकारी और निजी अस्पतालों को बंद रखने का आह्वान किया है। साथ ही जगह-जगह धरना प्रदर्शन करने का भी एलान किया है। इस बीच दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में विधेयक को लेकर दो गुट बन गए हैं। बंद सफल होने पर स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संसद में पेश व पारित किए चिकित्सा आयोग विधेयक में कई खामियां बताते हुए इसका विरोध किया है। आइएमए केप्रवक्ता डा नरेंदर सैनी ने कहा है कि आयोग पूरी तरह आम जन व गरीब विरोधी है। इसके तमाम प्रावधान निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने वाले हैं। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। यह पूरी तरह से सत्ता के कब्जे में रहने वाली संस्था होगी। भ्रष्टाचार इससे नहीं रुकेगा, उल्टे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता जरूर खराब हो जाएगी।

डा सैनी ने कहा किआयोग संबंधी मसौदे में प्रावधान किया गया है कि मेडिकल कालेजों की 50 फीसद सीटों के शुल्क तय करने का अधिकार निजी मेडिकल कालेजों के पास होंगे। इससे वे मनमाने शुल्क वसूलेंगे। अभी तक तो 50 फीसद सीटों पर शुल्क निधारण का अधिकार केंद्र व 35 फीसद सीटों के शुल्क का निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास था। केवल 15 फीसद सीटें ही निजी कालेज प्रबंधन के पास थीं। लेकिन अब 50 फीसद सीटों के शुल्क कालेंजो की ओर से तय किए जाएंगे। इससे जहां एक ओर मेधावी किंतु गरीब छात्र दाखिले से वंचित रह जाएंगे वहीं पूंजीपतियों के बच्चे मोटे शुल्क के आधार पर न केवल दाखिला पा जाएंगे बल्कि कम योग्यता के बावजूद डाक्टर बन जाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

परिवर्तन महारैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हुड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के बेहद करीब होने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन व विपक्ष के नेता पद को लेकर कोई नहीं निर्णय किए जाने के बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी 18 अगस्त को रोहतक में एक परिवर्तन महारैली के आयोजन का एलान किया है। समझा जा रहा है कि अपने राजनीतिक गढ़ रोहतक में इस सियासी जलसे के आयोजन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर हुड्डा पार्टी के भीतर और बाहर के अपने तमाम विरोधियों को साफ संदेश देना चाहते हैं कि लोकसभा में मिली हार को उनकी सियासी ताकत का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के दिल्ली स्थित निवास पर रविवार को उनकी अगुआई में हुई पार्टी विधायकों की बैठक में तय किया गया कि आगामी 18 अगस्त को रोहतक में कांग्रेस की एक परिवर्तन महारैली का आयोजन किया जाएगा। करीब एक दर्जन विधायकों संग चली दो घंटे की बैठक के बाद हुड्डा ने संवाददाताओं से कहा कि हम इस परिवर्तन महारैली के आयोजन के बहाने हम सूबे की भाजपा सरकार को उखाड़ने का आह्वान करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक सूबे में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल है तो पार्टी के विधायक बाकायदा एक प्रस्ताव पारित कर हाईकमान को भेज चुके हैं और हाईकमान ही इस मुद्दे पर निर्णय करेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 4 अगस्त को अनाज मंडी में महारैली की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और उसके बाद रैली का आयोजन होगा।

जानकारों का कहना है कि हुड्डा के अगुआई में होने वाली यह रैली एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन भी है जिससे कांग्रेस हाईकमान को भी यह संदेश दिया जाएगा कि सूबे में कांग्रेस को यदि सत्ता में वापसी करनी है तो इसके लिए हुड्डा का नेतृत्व जरूरी है। दूसरी ओर उनका खेमा प्रदेश की जनता को भी यह संदेश देना चाहता है कि हुड्डा यदि लोकसभा चुनाव हार गए इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उनकी सियासी ताकत बेहद कम हो गई है। उनमें अब भी सत्ता परिवर्तन करने का दमखम बाकी है। हुड्डा ने कहा भी कि लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने बेहद कमजोर संगठन के साथ लड़ा लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। हमलोग पूरी ताकत के साथ भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।

किशोर आरोपी के खिलाफ आज शुरू होगी सुनवाई

कठुआ बलात्कार-हत्याकांड

श्रीनगर, 28 जुलाई (भाषा)।

कठुआ में पिछले साल आठ साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले में किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड के सामने शुरू होगी क्योंकि जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने उस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिका में उसके नाबालिग होने को चुनौती दी गई है।

अब जम्मू क्षेत्र के कठुआ में किशोर न्याय बोर्ड के सामने मुकदमा शुरू होगा। किशोर न्याय बोर्ड ने 15 जुलाई को सुनवाई शुरू की थी लेकिन अपराध शाखा ने कहा था कि वह इस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है क्योंकि आरोपी के नाबालिग होने की स्थिति पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है। अपराध शाखा ने कहा था कि पुलिस ने हाई कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें आरोपी को किशोर ठहराया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर ने कहा, 'इसकी समय से पहले सुनवाई का मामला नहीं बनाया गया है। इस मामले पर उचित तारीख पर विचार किया जाए।' इस मामले को पांच अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अपराध शाखा जल्द सुनवाई की दरख्वास्त करते हुए हाई कोर्ट पहुंची थी क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड अपराधी प्रवृति वाले इस किशोर के खिलाफ आठ जुलाई को आरोप निर्धारण के बाद अपनी कार्यवाही शुरू कर चुका था। बोर्ड ने अपराध शाखा अभियोजन को सबूत प्रस्तुत करने को कहा था। अपराध शाखा की याचिका में कहा गया है, 'यदि किशोर न्याय बोर्ड के सामने इस मामले की आगे की कार्यवाही पर इस चरण में रोक नहीं लगाई गई तो पुनरीक्षण याचिका निष्फल हो जाएगी और अपराधी आरोपी के नाबालिग होने के निर्धारण का मूल प्रश्न धरा का धरा रह जाएगा।' 15 जुलाई को विशेष सरकारी वकील ने बोर्ड को सूचित किया था कि आरोपी को नाबालिग स्वीकार करने के कठुआ अदालत के फैसले के खिलाफ अपराध शाखा की अर्जी पर हाई कोर्ट ने अब तक अपना कोई आदेश नहीं सुनाया है। उन्होंने जम्मू मेडिकल कालेज की यह रिपोर्ट पेश की कि वह 19 साल से कम और 21 साल से अधिक नहीं है।

छत्तीसगढ़ में हाथी के हमले में बच्ची की मौत, माता-पिता घायल

रायगढ़, 28 जुलाई (भाषा) ।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों के एक झुंड के हमले में पांच साल की बच्ची की मौत हो गई और उसके माता-पिता घायल हो गए। वन विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

धरमजयगढ़ वन संभाग के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) प्रणय मिश्रा ने बताया कि घटना शनिवार रात को रवाफुल गांव के पास हुई। यह गांव बोरो वन क्षेत्र का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि घटना में प्रमिला साई की मौत हो गई, जबकि उसके पिता करमू साई (45) और माता गुरबाड़ी (42) घायल हो गए। उन्होंने बताया, एक हाथी ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करमू साई की हालत गंभीर बताई जाती है। उन्हें धरमजयगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पो. कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेज-4, गुड़गांव-122015 (हरियाणा)
फोन : 0124-4212530/31/32 ई-मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के तहत सूचना

क्र. सं.	कर्जदार(रों) का नाम	पता	सूचना राशि	प्रत्याभूत आस्ति
1	मनोज कुमार, रेखा	... फरीदाबाद, हरियाणा-121001	रु. 6,69,261/-	... फरीदाबाद, हरियाणा-121001
2	सुनील कुमार, बबली	मकान नंबर 98, ग्राम ... गुड़गांव, हरियाणा-122001	रु. 23,38,577/-	... गुड़गांव, हरियाणा-122001
3	राम हरि, राजेश्वरी	प्लॉट नंबर 412, 413, ... नजफगढ़ ... दिल्ली-110043	रु. 27,27,536/-	... गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010
4	अकरम अली, शिताश बेगम	... गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201014	रु. 19,78,414/-	... गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102

स्थान : गुड़गांव
तिथि : 27-07-2019
प्राधिकृत अधिकारी, शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड
(सीआईएनः L74899DL1992PLC049022)
पंजीकृत कार्यालयः एसेट संख्या 6, एरोसिटी होस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली-110037
दूरभाषः +91-11-4605 0101; फैक्सः +91-11-4605 0110
वेबसाइटः www.lemontreehotels.com
ईमेलः sectdeptt@lemontreehotels.com

27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना – ई-वोटिंग जानकारी

1. सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 27वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बृहस्पतिवार, 22 अगस्त 2019 को 03:00 बजे अपराह्न वायुसेना सभागार, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में एजीएम की सूचना में निहित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।
2. कंपनी ने 27 जुलाई 2019 को एजीएम की सूचना का प्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है तथा भौतिक प्रतिया अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत माध्यम से, पूर्ण कर लिया है।
3. उपर्युक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.lemontreehotels.com एवं कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा समय यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 के अनुपालन में, कट ऑफ तिथि अर्थात् 14 अगस्त 2019 को भौतिक व डिमैटेरियलाइज तौर पर शेयर धारण करने वाले सदस्य, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से, एजीएम की सूचना में निहित विषयों पर एजीएम स्थल से दूर किसी स्थान से अपना मतदान (रिमोट ई-वोटिंग) कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग पर विस्तृत निर्देश हेतु, सदस्यों से अनुरोध है की वे एजीएम की सूचना देखें।
5. सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है किः
   क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 19 अगस्त 2019 को 09.00 बजे (भारतीय मानक समय) पूर्वाह्न आरम्भ होगी तथा बुधवार, 21 अगस्त 2019 को 5:00 बजे अपराह्न समाप्त होगी। इसके पश्चात् ई-वोटिंग मॉड्यूल सदस्यों द्वारा मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
   ख) वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि अर्थात् 14 अगस्त 2019 को दर्शित हो, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ ही एजीएम में मतदान हेतु अधिकृत होगा।
   ग) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट ऑफ तिथि अर्थात् 14 अगस्त 2019 को शेयर धारण करता है, वह evoting@karvy.com पर अनुरोध भेजकर अथवा कार्वी के टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर कॉल कर के अथवा यदि सदस्य का मोबाइल नंबर फोलियो नंबर/डीपी आईडी क्लाइंट आईडी के सम्मुख पंजीकृत है, तो वे सदस्य MYEPWD इवेंट नंबर + फोलियो नंबर/डीपी आईडी क्लाइंट आईडी 9212993399 पर एसएमएस भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्तकर सकते हैं।
   घ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया है वे बैलट पेपर के माध्यम से एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया हो, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें एजीएम में पुनः मतदान का हकदार नहीं होगा।
   ङ) किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य कार्वी की ई-वोटिंग वेबसाइट https://evoting.karvy.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध "Frequently Asked Questions" (FAQs) एवं "remote e-voting user manual" संदर्भित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायतों के मामले में, सदस्य श्री प्रेम कुमार, प्रबंधक, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट रजिस्ट्री से टेलीफोन नंबर +91 40 6716 2222, ईमेल आईडी prem.kumar@karvy.com एवं पता टावर बी, प्लॉट संख्या 31 व 32, गचीबोवली, फाइनैनशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500032, तेलंगाना, भारत पर भी संपर्क कर सकते हैं।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, सूचना इत्यादि सहित सभी संचार प्राप्त करने हेतु कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड अथवा डिपोजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करा लें।

कृते लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड
हस्ता/-
निखिल सेठी
ग्रुप कम्पनी सचिव व जीएम लीगल एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 जुलाई 2019

फॉर्म सं. आईएनसी-26
केन्द्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
तथा
एक्सेल प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ... के मामले में
...
कृते एक्सेल प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
स्थान: दिल्ली
तिथि: 29.07.2019
DIN: 00270854

पॉल मर्चेन्ट्स लिमि.
(आइएसओ 9001:2015 प्रमाणित क.)
(सीआईएन L74900DL1984PLC018679)
info@paulmerchants.net
www.paulmerchants.net
सार्वजनिक सूचना
...
दिनांक: 26.07.2019

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
CONCOR
(A Govt. of India Navratna Undertaking)
खुली निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया)
...
समूह महाप्रबंधक (तकनीकी)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
शाखा कार्यालय
ज़िला गौतम बुध नगर (उ.प्र.)
परिशिष्ट IV
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
...
प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ़ बड़ौदा

कैल्कॉम विजन लिमिटेड
CIN:- L92111DL1985PLC021095
पंजी. कार्यालयः सी-41, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
Email id: corp.compliance@calcomindia.com
Website: www.calcomindia.com, Contact No.- 0120-2569761
30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए
अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण
(प्रति शेयर डैटा को छोड़कर रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.19 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.03.19 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.18 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.19 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	1517.81	1155.62	1259.27	5240.38
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से बाद)	81.09	62.37	63.07	301.48
3.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	81.09	62.37	63.07	301.48
4.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10 प्रति पूर्णतः प्रदत्त)	1054.34	1054.34	1054.34	1054.34
5.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)				(66.34)
6.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)				
	- मूल	0.77	0.59	0.60	2.86
	- तरल	0.77	0.59	0.60	2.86

टिप्पणीः
1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.calcomindia.com पर उपलब्ध है।
2. इन वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

बोर्ड के आदेश से
कैल्कॉम विजन लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
एस.के. मलिक
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 27 जुलाई, 2019

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
पवन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण
1. कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम: पवन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
...
महेन्द्र खण्डेलवाल
पवन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल
IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086
29 जुलाई, 2019
दिल्ली

चेन्नई लायंस ने पुणेरी पल्टन को हराया

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

अल्टीमेट टेबल टेनिस

चेन्नई लायंस ने त्यागराज स्टेडियम में खेले जा रहे अल्टीमेट टेबल टेनिस के तीसरे सत्र में पुणेरी पल्टन को 10–5 से हराकर रविवार को पहली जीत दर्ज की। लायंस के लिए जर्मनी की पेत्रिसा सोलजा, पुर्तगाल के तियागो अपोलोनिया ने जीत दर्ज करके टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पेत्रिसा ने महिला एकल में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता आहिका मुखर्जी को 3–0 से हराया तो वहीं अपोलोनिया ने पुरुष एकल में हरमीत देसाई को 2–1 से मात दी। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी शरत कमल और पेत्रिसा ने मिश्रित युगल में देसाई और सबिने विंटर की जोड़ी को 2–1 से हराकर मैच लायंस के नाम कर दिया।

मुकाबला गंवाने के बाद हालांकि पुणेरी पल्टन के चुआंग चिह-युआन ने पुरुष एकल में शरथ कमल को 2–1 से हराया जबकि सबिने ने लायंस की मधुरिका पाटकर को महिला एकल में 2–1 से शिकस्त दी।

दबंग दिल्ली ने हरियाणा स्टीलर्स को पीटा

मुंबई, 28 जुलाई (भाषा)।

पेशेवर कबड्डी लीग

दबंग दिल्ली ने पेशेवर कबड्डी लीग के सातवें सत्र में जीत का क्रम जारी रखते हुए रविवार को यहां हरियाणा स्टीलर्स को 41–21 से करारी शिकस्त दी। चंद्रन रंजीत (11 अंक) और नवीन कुमार (10 अंक) के दमदार खेल से दिल्ली की टीम ने सत्र की तीसरी जीत दर्ज की। नवीन का यह दूसरा 'सुपर 10' स्कोर था। इससे पहले उन्होंने हैदराबाद में तेलुगु टाइटंस के खिलाफ भी 10 अंक बनाए थे। मध्यांतर के समय दबंग दिल्ली की बढ़त 15–10 की थी लेकिन इसके बाद टीम ने आक्रामक रुख अख्तियार किया और हरियाणा स्टीलर्स के खिलाड़ी उन्हें रोकने में नाकाम रहे।

बंगलुरु बुल्स ने यू मुंबा को हराया : बंगलुरु बुल्स ने पेशेवर कबड्डी लीग के सातवें सत्र में रविवार को यहां यू मुंबा को रोमांचक मुकाबले में 30–26 से हराया।

मैरी कॉम और सिमरनजीत को स्वर्ण

प्रेसिडेंट कप में भारत को नौ पदक

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम (51 किग्रा) और 2018 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर (60 किग्रा) ने इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में स्वर्ण पदक जीते। इससे भारतीय मुक्केबाजों ने 23वें प्रेसिडेंट कप में अपने अभियान का अंत नौ पदक के साथ किया। भारतीय मुक्केबाजों ने सात स्वर्ण और दो रजत पदक जीते।

फाइनल में पहुंची भारत की चारों महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते जबकि पुरुष मुक्केबाजों के हाथ तीन स्वर्ण पदक लगे। दो खिलाड़ियों को हार के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ओलंपिक कांस्य पदकधारी मैरी कॉम ने फाइनल में आस्ट्रेलिया की एप्रिल फ्रैंक्स को 5–0 से शिकस्त दी। सिमरजीत ने भी फाइनल में एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता इंडोनेशिया की हसानाह हुसवातुन को 5–0 से हराया।

असम की युवा और प्रतिभावान जमुना बोरो ने महिला 54 किग्रा वर्ग के फाइनल में इटली की अनुभवी ग्युलिया लमाग्ना को 5–0 से हराकर सोने का तमगा अपने नाम किया। वहीं 48 किग्रा फाइनल में मोनिका ने इंडोनेशिया की एनडांग को इसी अंतर से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष वर्ग में अंकुश दाहिया (64 किग्रा), नीरज स्वामी (49 किग्रा) और अनंत चोपाड़ा (52 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीते।

अनंत ने अफगानिस्तान के रहमानी रमीश को 5–0 से हराकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना पहला बड़ा पदक जीता। दाहिया ने भी मकाऊ के ल्युंग किन फोंग को 5–0 से रौंदकर आसान जीत दर्ज की। नीरज ने फाइनल में फिलिपींस के मकाडो जूनियर रामेल को 4–1 से हराया। विश्व चैंपियनशिप के पूर्व कांस्य पदक विजेता गौरव बिधूड़ी और इंडिया ओपन 2018 के रजत पदक विजेता दिनेश डागर को फाइनल में हार के साथ रजत पदक मिला।

23वें प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में जीत दर्ज करने के बाद पदक के साथ भारतीय मुक्केबाज।

विदेशी मुक्केबाजों के साथ देश में ही तैयारी करेंगे भारतीय

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

ओलंपिक की तैयारियों के लिए भारतीय खिलाड़ियों का विदेश जाना आम बात है। लेकिन, अगले साल तोक्यो में होने वाले खेलों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी मुक्केबाज भारत आएंगे। ओलंपिक के क्वालीफाइंग टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों को यात्रा संबंधी थकान से बचाने के लिए दिसंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी मुक्केबाजों को भारत बुलाने की योजना है।

भारतीय मुक्केबाजी के हाई परफार्मेंस निदेशक सैंटियागो नीवा ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे मुक्केबाज थके नहीं। मौजूदा सत्र में हम पहले से ही काफी यात्रा कर रहे हैं। यह अच्छा होगा कि अगले साल जनवरी में होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के लिए घर में तैयारी करें।

'एशेज में दोनों टीमों के पास बराबरी का मौका'

लंदन, 28 जुलाई (एएफपी)।

पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ का कहना है कि एशेज श्रृंखला में इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया दोनों टीमों के पास बराबरी का मौका होगा। इसमें मेहमान टीम 18 साल के बाद सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी। आस्ट्रेलिया में 2010–11 श्रृंखला को छोड़कर (जिसमें इंग्लैंड ने 3–1 से जीत हासिल की थी) घरेलू फायदा निर्णायक रहा है।

वॉ की टीम ने 2001 में इंग्लैंड में श्रृंखला 4–1 से जीती थी। लेकिन 54 वर्षीय आस्ट्रेलियाई वॉ ने कहा कि मेरा सचमुच मानना है कि दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों के लिए छह हफ्तों में पांच टैस्ट खेलना बहुत बड़ा काम होगा। इसका पूरी श्रृंखला में बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे जिम्मी एंडरसन चोटिल हो जाएं या फिर हमारे लिए मिशेल स्टार्क चोटिल हो जाए। इससे लाइन-अप पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

टीम में अंदर-बाहर होने से मनोबल गिरता है : अय्यर

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

हर खिलाड़ी अपने करिअर को सुरक्षित करने की इच्छा रखता है और श्रेयस अय्यर भी इससे इतर नहीं हैं। उनका मानना है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए टीम में अंदर-बाहर होना सही स्थिति नहीं है। इससे लंबे समय में एक खिलाड़ी के आत्मविश्वास में कमी आती है। इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे कम उम्र के कप्तान (24 साल) अय्यर ने सात साल में पहली बार अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स को प्ले-ऑफ में पहुंचाया। वह कैरेबियाई सरजमीं पर होने वाली आगामी सीमित ओवरों की श्रृंखला की तैयारी में जुटे हैं।

श्रेयस दूसरी बार राष्ट्रीय टीम में शामिल हुए हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें कुछ और मौके मिलें जिससे उन्हें टीम में जगह पक्की करने में मदद मिलेगी। अय्यर ने कहा कि अगर आप बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं तो आपको खुद को साबित करने और परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए कुछ मौकों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आप टीम से अंदर-बाहर होते रहते हैं तो यह खिलाड़ी के आत्मविश्वास के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आप खुद की प्रतिभा पर शक करना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं तो आपको कुछ समय चाहिए। मुंबई के इस खिलाड़ी ने छह वनडे और इतने ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

मिनॉर और फ्रिट्ज के बीच होगा अटलांटा का फाइनल

वाशिंगटन, 28 जुलाई (एएफपी)।

तीसरे वरीय आस्ट्रेलिया के एलेक्स डि मिनॉर ने शनिवार को रेली ओपेलका पर जीत दर्ज कर जॉर्जिया के अटलांटा में चल रहे एटीपी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। अब खिताब के लिए वह टेलर फ्रिट्ज के सामने होंगे। बीस वर्षीय डि मिनॉर ने 7–6, 6–7, 6–3 से जीत हासिल की जिससे वह अटलांटा फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। वह अपने करिअर का दूसरा खिताब हासिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जनवरी में सिडनी में पहला फाइनल जीता था। वह एटीपी टूर के एक और युवा खिलाड़ी दूसरे वरीय फ्रिट्ज (21 वर्ष) से भिड़ेंगे जिन्होंने ब्रिटेन के कैमरन नौरी को 6–1, 3–6, 6–3 से शिकस्त दी।

हम चाहते हैं भारत राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हिस्सा ले : सीजीएफ

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) ने रविवार को कहा कि वे चाहते हैं कि भारत 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले। भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 से निशानेबाजी को हटाने पर इन खेलों के बहिष्कार का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। इसी के बाद सीजीएफ ने यह प्रतिक्रिया दी। सीजीएफ ने कहा कि वे निकट भविष्य में आइओए अधिकारियों से मिलना चाहते हैं जिससे कि चिंताओं का हल निकाला जा सके।

सीजीएफ के मीडिया एवं कम्यूनिकेशन मैनेजर टॉस डीगन ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत 2022 बर्मिंघम खेलों में हिस्सा ले। आगामी महीनों में भारत में अपने साथियों के साथ बैठक को लेकर वे उत्सुक हैं जिससे कि उनकी चिंताओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सके। आइओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए शनिवार को खेल मंत्री किरन रिजीजू को पत्र लिखकर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से निशानेबाजी को हटाने पर इन खेलों के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था और सरकार से स्वीकृति मांगी थी। आइओए ने निशानेबाजी को हटाए जाने के विरोध में सीजीएफ की आम सभा से नाम वापस ले लिया था जो सितंबर में रवांडा में होनी है। आइओए ने साथ ही क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए राजीव मेहता और खेल समिति के सदस्य के रूप में नामदेव शिरगांवकर के नाम भी वापस ले लिए थे। सीजीएफ अधिकारी ने कहा कि स्वभाविक रूप से हम निराश हैं कि भारत में हमारे साथियों ने रवांडा में 2019 सीजीएफ आम सभा में अन्य राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों के साथ नहीं आने का फैसला किया है।

एनआरएआइ ने आइओए का समर्थन किया

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने रविवार को कहा कि वह भारतीय ओलंपिक संघ के 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार करने के प्रस्ताव का समर्थन करता है। एनआरएआइ सचिव राजीव भाटिया ने कहा कि जहां तक राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार करने का संबंध है तो वे भी आइओए के साथ हैं।

"हम काफी समय से देख रहे हैं कि भारत जब भी खेलों पर पकड़ बनाने लगता है और अच्छा प्रदर्शन करने लगता है, तब नियमों में बदलाव की कोशिश की जाती है। हमें लगता है कि समय आ गया है कि हम आइओए/भारत में शामिल लोग कड़े सवाल पूछने शुरू करें और कड़ा रवैया अपनाएं। – नरिंदर बत्रा

इंटर मिलान ने पीएसजी को पेनल्टी में हराया

मकाऊ, 28 जुलाई (एएफपी)।

पुर्तगाल के मिडफील्डर जाओ मारियो ने अंतिम स्पॉट किक पर गोल किया जिससे इंटर मिलान ने यहां ब्राजीली स्टार नेमार की अनुपस्थिति में मैत्री मैच में पेनल्टी पर पेरिस सेंट जर्मेन को हरा दिया। पीएसजी शनिवार को जीत से सेकंड की दूरी पर था लेकिन सैमुअल लोंगो ने इंजुरी टाइम में बराबरी गोल दागकर स्कोर 1–1 कर दिया। इसके बाद इंटर मिलान ने पेनल्टी में 6–5 से जीत हासिल की। एंटोनियो कोंते की टीम को चीन में पेनल्टी पर ही इटली के प्रतिद्वंद्वी यूवेंतस से हार का मुंह देखना पड़ा था।

सरिता ने किया उलटफेर, विनेश-साक्षी जीतीं

लखनऊ, 28 जुलाई (भाषा)।

विश्व चैंपियनशिप का ट्रायल

विनेश फोगाट और साक्षी मलिक कुश्ती विश्व चैंपियनशिप के लिए रविवार को हुए ट्रायल्स में उम्मीदों के मुताबिक आसानी से जीत दर्ज करने में सफल रहीं। पूर्व कांस्य पदक विजेता पूजा ढांडा को सरिता मोर के खिलाफ उलटफेर का शिकार होना पड़ा। विनेश के 53 किग्रा वर्ग में सिर्फ तीन पहलवान थे जिससे उन्हें सिर्फ एक मुकाबले में उतरना पड़ा। उन्होंने फाइनल मुकबले में पिंकी के खिलाफ 9–0 की दमदार जीत दर्ज की।

सबसे कड़ा मुकाबला 57 किग्रा वर्ग में था जहां पूजा के अलावा तेजी से उभरती हुई अंशू मलिक, विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज मंजू और सरिता दावेदारी पेश कर रहीं थी। पूजा ने रानी राणा को मात देने के बाद अंशू को पटखनी देकर फाइनल में जगह बनाई। अंशू ने हालांकि पूजा को कड़ी टक्कर दी और एक समय वह 4–2 से आगे चल रही थी लेकिन अंतिम मिनट में पूजा ने दो अंक लेकर बराबरी की और फिर जीत दर्ज की।

इस वर्ग में मंजू को भी उलटफेर का सामना करना पड़ा जिसे मानसी ने 4–3 से हरा दिया। मानसी को हालांकि सरिता ने अगले मुकाबले में बाहर का रास्ता दिखा फाइनल में पहुंची। फाइनल में 52वें सेकंड में सरिता का घुटना चोटिल हो गया लेकिन फिर भी वह पूजा पर भारी पड़ीं। एशियाई चैंपियनशिप (2018) में रजत पदक जीतने वाली सरिता ने अपनी मानसिक मजबूती और दमदार डिफेंस से पूजा को हावी होने का मौका नहीं दिया।

रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को 62 किग्रा भार वर्ग में अंकिता को पटखनी देने में सिर्फ 58 सेकंड का समय लगा जबकि फाइनल बाउट में उन्होंने एक पीरियड में ही रेशमा मान को शिकस्त दी। दिव्या काकरान ने 68 किग्रा में विश्व चैंपियनशिप का टिकट कटाया।

जेकेएनआरसी के राउंड-1 में विष्णु, चिराग चमके

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

भारत के अग्रणी रेसर विष्णु प्रसाद और युवा चिराग घोरपड़े ने जेके टायर एफएमएससीआइ राष्ट्रीय चैंपियनशिप के 22वें संस्करण के राउंड-1 के पहले दिन अपनी चमक बिखेरी। इन दोनों ने अपने-अपने वर्ग में जीत दर्ज की। सैयद मुजामिल अली भी दिन के हीरो साबित हुए। अली ने जेके टायर सुजुकी जिक्सर कप के पहले राउंड की सपोर्ट रेस अपने नाम की।

चैंपियनशिप का पहला राउंड पूरी तरह बदला हुआ दिखा। इस साल युवा चालकों पर ध्यान है और 27 चालकों ने शीर्ष सम्मान के लिए अपनी क्षमताओं की अंतिम सीमा तक प्रदर्शन किया। मोमेंटम मोटरस्पोर्ट्स के बंगलुरु के चिराग ने सबसे अधिक प्रभावित किया। चिराग ने सुबह के सत्र में पोल पोजीशन हासिल किया और नोवाइस कप में दिन की पहली रेस में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने ने 13.37.912 मिनट का समय निकाला और अपने टीम के साथी आरोह रवींद्र और मोहम्मद रायन (एमस्पोर्ट) को पीछे छोड़ा। आरोह और रायन ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। चिराग यहीं नहीं रुके और दूसरी रेस में भी बाजी मार ली।

बाउंड्री गिनने के नियम पर चर्चा करेगी आइसीसी क्रिकेट समिति

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

अनिल कुंबले की अगुआई वाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की क्रिकेट समिति अगली बैठक में एतिहासिक विश्व कप फाइनल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। इसमें बाउंड्री गिनने का विवादास्पद नियम भी शामिल है। आइसीसी के क्रिकेट महाप्रबंधक ज्यौफ एलार्डिस ने यह जानकारी दी।

लॉर्ड्स पर 14 जुलाई को हुए विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड ने कम बाउंड्री लगाने के कारण विश्व खिताब मेजबान इंग्लैंड को गंवा दिया था। इसके बाद कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने मेहमान टीम से सहानुभूति जताई थी। इंग्लैंड को 22 चौके और दो छक्के जड़ने के कारण विजेता घोषित किया गया था जबकि न्यूजीलैंड की टीम 17 बाउंड्री ही लगा पाई थी।

TVS Presents

Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards

INDIA'S MOST PRESTIGIOUS
AND COVETED JOURNALISM AWARDS

CALL FOR ENTRIES 2018

Acknowledging accuracy, courage, credibility & fairness

Ramnath Goenka Memorial Foundation | Indian Express Group

Award Categories

Print/Digital & Broadcast
- Reporting from Conflict States
- Hindi
- Regional Languages
- Environment, Science and Technology Reporting
- Uncovering India Invisible
- Business and Economic Journalism
- Reporting on Politics and Government
- Sports Journalism
- Investigative Reporting

Print/Digital
- Reporting on Arts, Culture and Entertainment
- Foreign Correspondent Covering India
- Editorial Commentary and Cartoons
- Books (Non-Fiction)
- Prakash Kardaley Memorial Award for Civic Journalism
- Photo Journalism
- Best Student-Run Newspaper, Magazine and Digital News Portal

Apply Online: rngfoundation.com/awards

LAST DATE FOR ENTRIES | JULY 31, 2019 | Entries are invited for the year 2018 only.

Ramnath Goenka Memorial Foundation, Express Building, B-1/B, Sector-10, Noida-201 301, Uttar Pradesh, India; rngf@expressindia.com

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 253, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।